दिनमान तापमान
सूर्योदय 4.57 सूर्यास्त 6.10 अधिकतम 37° न्यूनतम 28°

वर्ष 18, अंक 327 पृष्ठ 8
कोलकाता, शुक्रवार, 15 मई 2026
ज्येष्ठ, कृष्णपक्ष, त्रयोदशी, वि.सं. 2083

मूल्य: ₹3

निष्पक्ष, निडर एवं सशक्त राष्ट्रीय दैनिक

युवा शक्ति

कोलकाता संस्करण www.yuvashaktinews.com

सीएम शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने जारी किया आदेश

बंगाल के स्कूलों में अब 'वंदे मातरम' का गायन अनिवार्य

सरकार ने ममता बनर्जी के पिछला निर्देश रद्द किया

- परिचम बंगाल में सुबह की प्रार्थना में सभी बच्चों को राष्ट्र गीत गाना अनिवार्य किया गया।
- सभी सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए शुभेंदु अधिकारी सरकार ने जारी किया आदेश।
- स्कूलों को राष्ट्र गीत गान करवाने की वीडियो रिकॉर्डिंग करके रखने का भी निर्देश जारी किया गया।

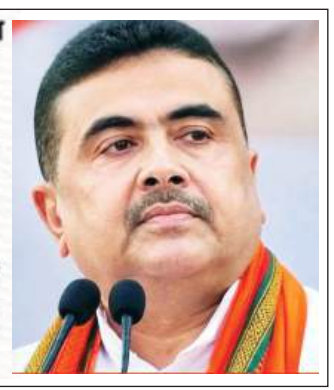

कोलकाताः पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ' वंदे मातरम ' को लेकर बड़ा ऐलान किया है. पश्चिम बंगाल सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से जारी एक आधिकारिक आदेश के अनुसार राज्य के सभी सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में सुबह की सभा के दौरान राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम' का गायन अनिवार्य होगा. निर्देश में कहा गया है कि स्कूल शुरू होने पर होने वाली सभा में प्रत्येक छात्र को राष्ट्रगीत के गायन में भाग लेना होगा. संस्थानों के प्रमुखों को इस आदेश का सख्ती से पालन कराने का निर्देश दिया गया है.

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा परिसर में पत्रकारों से कहा कि अगले सोमवार से राज्य के सभी स्कूलों में प्रार्थना गीत के रूप में 'वंदे मातरम' की शुरुआत की जाएगी. उन्होंने देर शाम इस बारे में आदेश अपने एक्स अकाउंट पर शेयर किया. इसमें कहा गया है कि सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षाओं की शुरुआत से पहले सुबह की सभा में 'वंदे मातरम' का गायन अनिवार्य किया जाना चाहिए, ताकि राज्य के सभी स्कूलों में तत्काल प्रभाव से सभी बच्चे इसे गाएं.

यह कदम केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति सम्मान से संबंधित प्रावधानों को मजबूत करने की पहल के कुछ समय बाद आया है. केंद्र सरकार ने 'राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम, 1971' में संशोधन का प्रस्ताव रखा है, जिससे वंदे मातरम के गायन में बाधा डालना एक दंडनीय अपराध बन जाएगा. स्कूल शिक्षा विभाग के एक अधिकारी ने गुरुवार को संकेत दिया कि राष्ट्रगीत का गायन प्रारंभिक सभा में किया जाएगा.

उन्होंने कहा कि स्कूल अधिकारियों को इस कार्यान्वयन के प्रमाण के रूप में वीडियो रिकॉर्डिंग सहित पूरी कार्यवाही का दस्तावेजीकरण करने के लिए भी कहा गया है.

इससे पहले, राज्य के स्कूलों में पारंपरिक रूप से केवल रवींद्रनाथ टैगोर की ओर से रचित राष्ट्रगान 'जन गण मन' ही गाया जाता था. पिछली तृणमूल कांग्रेस सरकार ने 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में टैगोर द्वारा ही लिखे गए गीत 'बांग्लार माटी बांग्लार जल' को हाल के वर्षों में राज्य गीत के रूप में पेश किया था. इस सूची में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय रचित राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम' के जुड़ जाने और राज्य के स्कूलों में इसका गायन अनिवार्य किए जाने से, सुबह की सभा के सीमित समय में इन सभी गीतों के गायन की अवधि और उनके क्रम को लेकर शिक्षकों के एक वर्ग के बीच सवाल उठने लगे हैं. वामपंथ समर्थित एक शिक्षक संगठन के प्रवक्ता ने कहा कि इस पर और अधिक स्पष्टता का इंतजार है कि क्या सभी गीत दैनिक रूप से गाए जाने हैं और उन्हें वर्तमान समय-सारणी में कैसे समायोजित किया जाएगा.

ईरान ने यूएई तट के पास एक जहाज किया जब्त

ओमान में भारतीय झंडा लगा जहाज हमले के बाद डूबा

दुबईः संयुक्त अरब अमीरात के पूर्वी तट के पास लंगर डाले एक जहाज को अज्ञात लोगों द्वारा जब्त कर ईरान की दिशा में ले जाने की खबर सामने आई है. इस घटना की पुष्टि ब्रिटिश सैन्य संगठन यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस ने की है.

घटना के बाद पूरे होर्मुज जलडमरूमध्य क्षेत्र में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं.यह जहाज फुजैरा बंदरगाह से लगभग 38 समुद्री मील (करीब 70 किलोमीटर) उत्तर-पूर्व में लंगर डाले था, जब उस पर अनधिकृत लोगों ने कब्जा कर लिया. प्रारंभिक रिपोर्टों में बताया गया है कि जहाज को जब्त करने के बाद उसे ईरानी जलक्षेत्र की ओर ले जाया गया. इसी बीच भारतीय अधिकारियों ने जानकारी दी है कि ओमान के तट के पास एक भारतीय ध्वज वाले मालवाहक जहाज पर हमला हुआ, जिससे उसमें आग लग गई और बाद में वह डूब गया. यह जहाज सोमालिया से यूएई के शारजाह की ओर जा रहा था. जहाज पर सवार सभी 14 भारतीय चालक दल को ओमान की तटरक्षक टीम ने सुरक्षित बचा लिया. अधिकारियों के अनुसार, सभी नाविक सुरक्षित हैं और उन्हें चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई गई है. *पेज 7 पर जारी*

भाजपा विधायक रथिंद्र बोस होंगे नये विधानसभा अध्यक्ष

कोलकाताः हाल में संपन्न चुनाव में उत्तर बंगाल के कूचबिहार दक्षिण से भाजपा के टिकट पर पहली बार विधायक निर्वाचित हुए रथिंद्र बोस बंगाल विधानसभा के नए अध्यक्ष (स्पीकर) होंगे. बंगाल में प्रचंड जीत के बाद पहली बार सत्ता में आई भाजपा ने गुरुवार को चौंकाने वाली घोषणा करते हुए स्पीकर पद के लिए बोस को अपना उम्मीदवार नामित किया. मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने उनकी उम्मीदवारी की घोषणा की. वरिष्ठ भाजपा नेता बोस पहली बार विधायक चुने गए हैं. अध्यक्ष जैसे महत्वपपूर्ण पद के लिए उनकी उम्मीदवारी की घोषणा पर सभी सदस्य आश्चर्यचकित रह गए. बोस का निर्विरोध विधानसभा अध्यक्ष चुना जाना तय है, क्योंकि गुरुवार को इस पद के लिए एकमात्र उन्होंने ही नामांकन दाखिल किया. लगातार 15 साल तक राज्य की सत्ता पर काबिज रही तृणमूल कांग्रेस ने अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार नहीं उतारे हैं. विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए शुक्रवार को चुनाव होना है. मुख्यमंत्री की मौजूदगी में स्पीकर पद के लिए बोस ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया.

जानकारी के अनुसार, बोस लंबे समय से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) और भाजपा दोनों से जुड़े रहे हैं. भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष के तौर पर, बोस ने उत्तर बंगाल में पार्टी की संगठनात्मक गतिविधियों को संभाला था. उत्तर बंगाल भाजपा का सबसे मजबूत गढ़ रहा है. फिलहाल, वे भाजपा के उत्तर बंगाल संभाग के संयोजक हैं. उन्हें संसदीय राजनीति का कोई अनुभव नहीं है, लेकिन वे एक जाने-माने वक्ता के तौर पर पहचाने जाते हैं. वहीं, पार्टी द्वारा इस पद के लिए नामित किए जाने पर बोस ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर वह विधानसभा अध्यक्ष चुने जाते हैं, तो सबका साथ, सबका विकास के मंत्र पर चलते हुए अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे. विधानसभा परिसर में पत्रकारों से बातचीत में भाजपा नेतृत्व का आभार जताते हुए उन्होंने कहा कि वे पार्टी के एक आज्ञाकारी और भरोसेमंद सिपाही के तौर पर अपनी पूरी क्षमता से काम करेंगे. बंगाल की 294 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा के पास 207 विधायक हैं और संख्या बल उसके पक्ष में है.

डीसीपी शांतनु सिन्हा बिश्वास को ईडी ने किया गिरफ्तार

कोलकाताः ईडी ने गुरुवार की रात को एक बड़ी कार्रवाई करते हुए कोलकाता पुलिस के उपायुक्त (डीसीपी) शांतनु सिन्हा बिश्वास को गिरफ्तार कर लिया है. जमीन हड़पने, जबरन वसूली और वित्तीय हेराफेरी के हाई-प्रोफाइल मामले में साढ़े 10 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद केंद्रीय जांच एजेंसी ने यह कदम उठाया. शुक्रवार को उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा, जहां ईडी उनकी हिरासत की मांग करेगी.शातिर अपराधी बिश्वजीत पोद्दार उर्फ 'सोनू पप्पू' से जुड़े मामलों में ईडी शांतनु सिन्हा से लंबे समय से जवाब मांग रही थी. गुरुवार सुबह करीब 11 बजे जब शांतनु साल्टलेक स्थित ईडी कार्यालय पहुंचे, तो अधिकारियों ने सवालों की झड़ी लगा दी. सूत्रों के अनुसार, शांतनु जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे और वित्तीय लेनदेन से जुड़े सवालों पर संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए. अंततः रात करीब

9.30 बजे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया.

शांतनु सिन्हा बिश्वास की मुश्किलें तब और बढ़ गई थीं जब उन्होंने ईडी के कई समन को नजरअंदाज किया. कालीघाट थाने के पूर्व प्रभारी रहे इस अधिकारी के खिलाफ एजेंसी ने लुकआउट नोटिस भी जारी किया था, ताकि वे देश छोड़कर न भाग सकें. इससे पहले ईडी ने उनके दक्षिण कोलकाता स्थित फर्न रोड आवास पर 20 घंटे से अधिक समय तक छापेमारी की थी, जिसमें उनके बेटों-सायंतन और मनीष-को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था. यह गिरफ्तारी मुख्य रूप से 'सोना पप्पू' और उसके गिरोह द्वारा की गई अवैध वसूली और जमीन कब्जाने के मामले से जुड़ी है. जांच में सामने आया है कि शांतनु सिन्हा के इस गिरोह के साथ संदिग्ध आर्थिक संबंध थे. बेहला के व्यवसायी जय कामदार की गिरफ्तारी के बाद शांतनु की भूमिका को लेकर ठोस सबूत मिले थे. इसके अलावा, उन पर बालू तस्करी मामले में भी संलिप्तता के आरोप हैं. इस गिरफ्तारी ने कोलकाता पुलिस महकमे में हड़कंप मचा दिया है, क्योंकि शांतनु सिन्हा बिश्वास शहर के प्रभावशाली पुलिस अधिकारियों में गिने जाते रहे हैं.

वीडी सतीशन सोमवार को लेंगे केरलम के सीएम पद की शपथ

तिरुवनंतपुरमः केरल के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर वी.डी सतीशन के नाम की घोषणा के साथ ही मुख्यमंत्री को लेकर जारी संशय खत्म हो गया है. कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ ने अब अपना ध्यान राजनीतिक खींचतान से हटाकर सत्ता हस्तांतरण पर केंद्रित कर लिया है. मुख्यमंत्री पद के लिए नामित वी.डी सतीशन सोमवार को शपथ ग्रहण करेंगे. राज्य के मुख्यमंत्री का मुद्दा सुलझने के बाद यूडीएफ के भीतर नए मंत्रिमंडल की संरचना को लेकर गहन चर्चा शुरू हो गई. सूत्रों के अनुसार, यह सुनिश्चित करने के प्रयास जारी हैं कि सभी 20 मंत्री सतीशन के साथ शपथ लें, जिससे मंत्रिमंडल के चरणबद्ध विस्तार की संभावना समाप्त हो जाएगी और इसके बजाय पहले ही दिन पूर्ण *पेज 7 पर जारी*

पश्चिम बंगाल में 12वीं बोर्ड परीक्षा में आद्रितो पाल बने टॉपर

500 में पाए 496 नंबर; कुल 91.23% परीक्षार्थी हुए उत्तीर्ण

कोलकाता. बंगाल शिक्षा बोर्ड की 12वीं की परीक्षा (उच्च माध्यमिक) के नतीजे गुरुवार को घोषित कर दिए गए. इस बार कुल 91.23 प्रतिशत परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं. दक्षिण 24 परगना जिले के नरेंद्रपुर रामकृष्ण मिशन विद्यालय (रेजिडेंशियल) के आद्रितो पाल 500 में 496 अंकों (99.2 प्रतिशत) के साथ टॉपर बने हैं, वहीं छात्राओं में पुरुलिया के रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ की देबप्रिया माजी 494 अंकों (98.8 प्रतिशत) के साथ अव्वल रही हैं. टॉप 10 की सूची में देबप्रिया तीसरे स्थान पर हैं. वहीं, टॉप 10 में कुल 64 परीक्षार्थी शामिल हैं.

पश्चिम बंगाल उच्च माध्यमिक शिक्षा काउंसिल के अध्यक्ष डॉक्टर पथ कर्मकार ने परीक्षाफल की जानकारी देते हुए बताया कि इस बार कुल 626258 परीक्षार्थी परीक्षा में बैठे थे, जिनमें 279936 छात्र व 346322 छात्राएं थीं. इसमें 89.71 प्रतिशत छात्र व 92.47 प्रतिशत छात्राएं उत्तीर्ण हुई हैं.

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने परीक्षा में सफल सभी छात्र-छात्राओं को शुभकामनाएं और बधाई दी. मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि विद्यार्थियों की मेहनत, अनुशासन और आत्मविश्वास ने उन्हें सफलता दिलाई है. उन्होंने कहा कि जीवन के इस महत्वपूर्ण पड़ाव पर मिली सफलता विद्यार्थियों को भविष्य में और बड़े लक्ष्य हासिल करने की प्रेरणा देगी. मुख्यमंत्री ने सभी विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि वे आगे चलकर परिवार, समाज और राज्य का नाम रोशन करें. इस साल उत्तीर्णता दर में पूर्व मेदिनीपुर सबसे आगे रहा है. वहां के 94.19 प्रतिशत परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं. इसके बाद 93.84 प्रतिशत के साथ हावड़ा दूसरे व 93.71 प्रतिशत के साथ दक्षिण 24 परगनातीसरे स्थान पर रहा है. मालूम हो कि परीक्षा के समापन के 76 दिनों के अंदर नतीजे घोषित किए गए हैं. इस बार 73 परीक्षार्थियों ने अस्वस्थ होने के कारण विभिन्न अस्पतालों से परीक्षा दी थी. परीक्षार्थियों में इस बार एक ट्रांसजेंडर भी था. काउंसिल ने एक अभिनव कदम उठाया है. पहली बार मार्कशीट पर परीक्षार्थी की तस्वीर भी होगी.

बंगाल सरकार ने सार्वजनिक रूप से पशुवध पर लगाई रोक, मवेशियों के लिए प्रमाण पत्र अनिवार्य

कोलकाता : पश्चिम बंगाल में नव निर्वाचित भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मवेशियों के वध के संबंध में उपयुक्त' प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिया है.राज्य सरकार द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है कि बिना इस अनिवार्य प्रमाण पत्र के किसी भी सांड, बैल, गाय, बछड़े, भैंस, भैंस के बछड़े और बधिया भैंसों का वध पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा. इसके अलावा सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि अब सार्वजनिक रूप से पशु वध की अनुमति नहीं होगी. केवल नगरपालिका की ओर से तय या अधिकृत वधशाला में ही पशुओं का वध किया जा सकेगा.इस नोटिस के कई प्रावधान पहले से ही लागू थे. खास बात यह है कि इस नोटिस में धार्मिक, औषधीय या शोध के उद्देश्यों से की जाने वाली कुर्बानी के लिए किसी छूट का ज़िक्र नहीं किया गया है.उल्लेखनीय है कि यह आदेश 26 मई को मनाए जाने वाले ईद-उल-अज़हा या बकरीद से कुछ ही दिन पहले आया है. ईद के जश्न का एक अहम हिस्सा बकरी, भेड़ या मेमने की कुर्बानी देना है.

गृह और पर्वतीय मामलों के विभाग द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है, 'कोई भी व्यक्ति किसी भी जानवर, जिसमें बैल, बछड़ा, गाय, बछिया, नर और मादा भैंसें, भैंस के बछड़े और बधिया भैंसें शामिल हैं, का वध तब तक नहीं करेगा, जब तक कि उसे इस संबंध में यह प्रमाण पत्र न मिल जाए कि वह जानवर वध के लिए उपयुक्त है.'नोटिस के अनुसार, प्रमाण पत्र नगर पालिका अध्यक्ष या पंचायत के सभापति द्वारा एक सरकारी पशु चिकित्सक के साथ मिलकर केवल तभी जारी किया जाएगा जब दोनों लिखित रूप में इस बात पर सहमत हों कि पशु की उम्र 14 साल से ज्यादा है और वह काम या प्रजनन के लायक नहीं रहा है या फिर किसी पुरानी बीमारी, चोट, शरीर की खराबी या ठीक न होने वाली बीमारी के कारण हमेशा के लिए अक्षम हो गया है.

इस प्रमाण पत्र का आवेदक आवेदन की अस्वीकृति की सूचना मिलने के 15 दिनों के भीतर राज्य सरकार में अपील कर सकता है.इसके अलावा आवश्यक प्रमाण पत्रों के साथ भी खुले में जानवरों की हत्या करना 'सख्ती से प्रतिबंधित' है. नोटिस में कहा गया है कि जानवर को किसी नगर पालिका वधशाला या स्थानीय प्रशासन द्वारा निर्धारित किसी अन्य स्थान पर ही ले जाना अनिवार्य है. नोटिस में आगे कहा गया है, 'पश्चिम बंगाल पशु वध नियंत्रण अधिनियम 1950 के प्रावधानों को लागू करने के लिए नगर पालिका के अध्यक्ष, पंचायत समिति के सभापति या सरकारी पशु चिकित्सक द्वारा अधिकृत किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी परिसर के निरीक्षण का कोई भी व्यक्ति विरोध नहीं करेगा.'नोटिस का हवाला देते हुए बताया कि इन प्रावधानों का उल्लंघन करते पाए जाने वालों को छह महीने तक की कैद, 1,000 रुपये तक का जुर्माना, या दोनों का सामना करना पड़ सकता है.

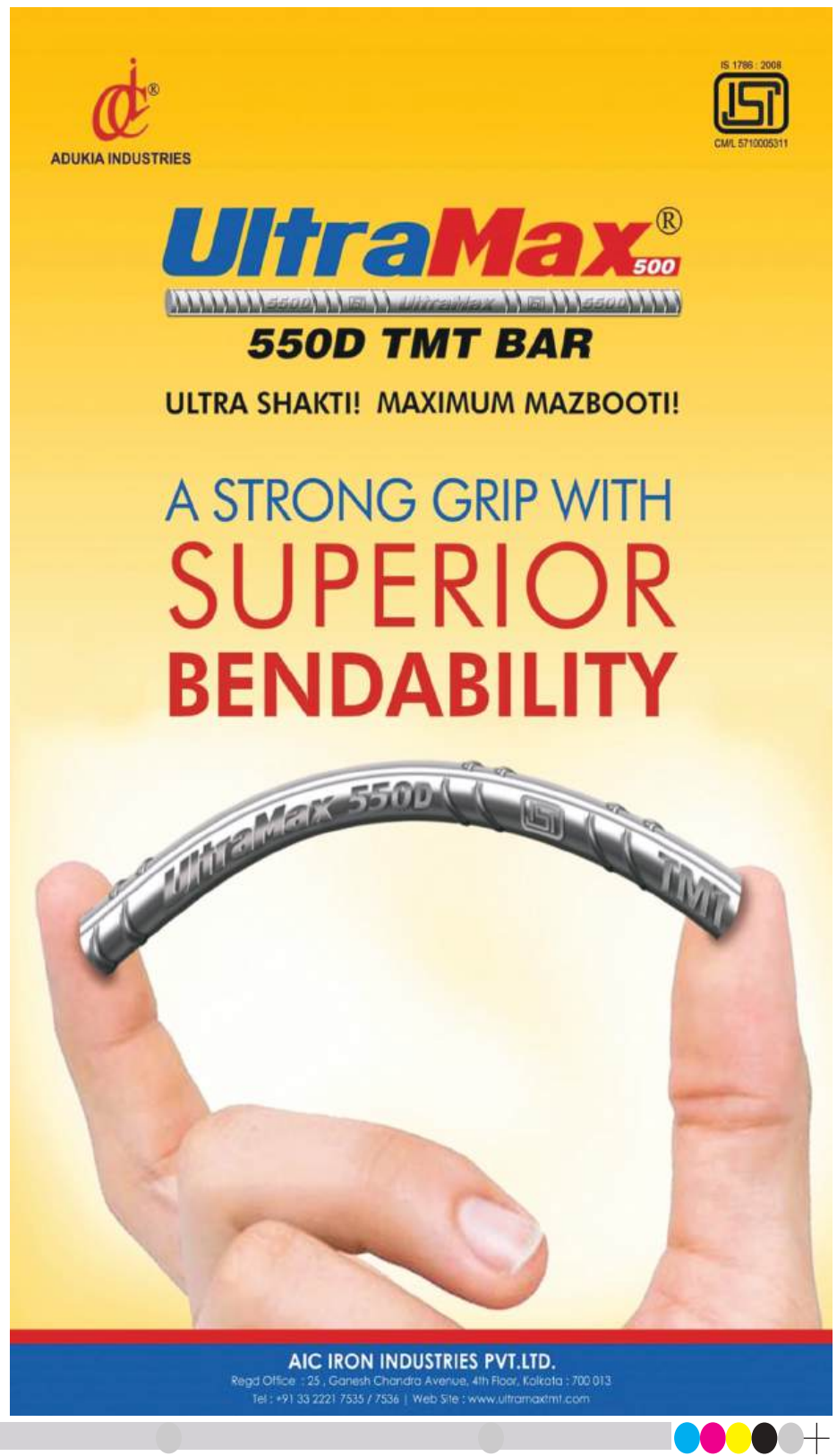

कलकत्ता हाईकोर्ट में ममता बनर्जी के खिलाफ चोर-चोर के नारे

कोलकाताः कलकत्ता हाईकोर्ट में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को देखते ही 'चोर-चोर' के नारे लगने लगे. गुरुवार को हाईकोर्ट परिसर में भारी तनाव फैल गया. ममता उस समय चुनाव के बाद हुई हिंसा से जुड़े एक मामले में अपनी दलीलें पेश करने के लिए कोर्ट आई थीं. जब वह परिसर से बाहर निकल रही थीं, तो वकीलों के एक समूह ने उन्हें देखते ही नारे लगाने शुरू कर दिए. इस तरह पूर्व मुख्यमंत्री को विरोध का सामना करना पड़ा. वह बड़ी मुश्किल से भीड़ से निकलकर अपनी कार तक पहुंच पाईं. बताया गया है कि सुनवाई खत्म होने के बाद जब ममता बनर्जी कोर्ट रूम नंबर 1 से बाहर निकल रही थीं तो गलियारे में 'जय श्री राम' के नारे गूंज उठे. इसके जवाब में 'जय बांग्ला' के नारे लगाए गए. इस दौरान मौके पर मौजूद पुलिस ने स्थिति को संभाला.उधर, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने पश्चिम बंगाल बार काउंसिल को पत्र लिखकर ममता बनर्जी के एनरोलमेंट और कानूनी प्रैक्टिस की स्थिति से जुड़े रिकॉर्ड मांगे हैं. बार काउंसिल ने 2 दिनों के भीतर एनरोलमेंट, प्रैक्टिस के निलंबन और फिर शुरू होने और प्रैक्टिस के प्रमाण पत्र से जुड़ी विस्तृत जानकारी मांगी है.

यह पीआईएल कलकत्ता हाईकोर्ट के वकील और वरिष्ठ अधिवक्ता और चार बार के तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी के बेटे सिरसन्या बनर्जी ने दायर की थी. सिरसन्या बनर्जी हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों में हुगली जिले की उत्तरपारा विधानसभा सीट से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार थे. हालांकि, उन्हें भाजपा उम्मीदवार और पूर्व एनएसजी कमांडेंट दीपंजन चक्रवर्ती ने 10,000 से अधिक वोटों के अंतर से हरा दिया था. ममता बनर्जी कलकत्ता हाईकोर्ट में वकीलों वाला पारंपरिक काला कोट और सफेद कॉलर-बैंड पहनकर पहुंची थीं. वे केस की सुनवाई के लिए मुख्य न्यायाधीश सुजॉय पॉल और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी सेन की डिवीजन बेंच के सामने पेश हुईं.नियमों के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति संवैधानिक पद पर कार्यरत होता है या किसी अन्य लाभकारी पद पर रहता है, तो उसे वकालत का लाइसेंस अस्थायी रूप से निलंबित करना होता है. सेवा समाप्त होने के बाद ही इसे पुनः सक्रिय किया जा सकता है. इसी संदर्भ में बीसीआई ने यह जांच शुरू की है कि क्या सभी प्रक्रियाओं का पालन किया गया था या नहीं.वहीं दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने कलकत्ता हाईकोर्ट से कहा कि पश्चिम बंगाल में हाल में संपन्न विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के दौरान पुलिस निष्क्रिय रही. उन्होंने पश्चिम बंगाल में अवैध ढांचों के खिलाफ जारी विध्वंस अभियान के बीच कहा कि यह (बंगाल) बुलडोजर राज्य नहीं है.एलएलबी डिग्री धारी ममता हाल के समय में किसी मामले में वकील के तौर पर दलीलें पेश करने के लिए अदालत में दूसरी बार पेश हुईं. वहीं, बंगाल चुनाव में तृणमूल की हार के बाद यह बतौर वकील अदालत में उनकी पहली उपस्थिति थी. *पेज 7 पर जारी*

बार काउंसिल ने मांगा वकालत का सर्टिफिकेट

उच्च माध्यमिक में कूचबिहार के चंद्रचूड़ सेन राज्य में चौथे स्थान पर

कूचबिहार : अपनी प्रतिभा का लोहा एक बार फिर मनवाते हुए कूचबिहार के रामभोला हाई स्कूल के छात्र चंद्रचूड़ सेन ने उच्च माध्यमिक परीक्षा में राज्य में चौथा स्थान हासिल किया है. उन्होंने 493 अंक प्राप्त कर यह बड़ी सफलता हासिल की है.2024 में वह माध्यमिक परीक्षा में पूरे राज्य में प्रथम स्थान पर रहे थे.हालांकि इस बड़ी उपलब्धि के बीच चंद्रचूड़ ने राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा (नीट) परीक्षा में हुए कथित पेपर लीक और अनियमितताओं को लेकर नाराजगी भी जताई. उसने बताया कि उच्च माध्यमिक की तैयारी के साथ-साथ उसने नीट परीक्षा के लिए भी काफी मेहनत की थी और तीन मई को परीक्षा दी थी, लेकिन देशभर में सामने आए विवाद के कारण परीक्षा रद्द होने से वह काफी निराश और क्षुब्ध है.चंद्रचूड़ की इस लगातार सफलता से उसके परिवार में खुशी का माहौल है. उसके पिता शांतनु सेन और मां मौसमी सेन बेटे की उपलब्धि पर बेहद गर्व महसूस कर रहे है. रिजल्ट आने के बाद घर में मिठाई खिलाकर जश्न मनाया गया. वहीं, पूरे जिले में एकमात्र छात्र के रूप में मेधा तालिका में जगह बनाने पर रामभोला हाई स्कूल के शिक्षक भी बेहद गौरवान्वित है.स्कूल के प्रधानाध्यापक तपन कुमार दास सहित अन्य शिक्षक उसके घर पहुंचे और उसे मिठाई खिलाकर सम्मानित किया. चंद्रचूड़ की इस सफलता से पूरे कूचबिहार में उत्सव का माहौल है और उसकी उपलब्धि अन्य छात्रों के लिए प्रेरणा बन गई है.

सिलीगुड़ी की श्रेयसी शील ने उच्च माध्यमिक में हासिल किया आठवां स्थान

सिलीगुड़ी : सिलीगुड़ी के एक्टियासाल इलाके की रहने वाली छात्रा श्रेयसी शील ने उच्च माध्यमिक परीक्षा में शानदार प्रदर्शन करते हुए पूरे राज्य में 8वां स्थान हासिल किया है. सिलीगुड़ी गर्ल्स हाई स्कूल की छात्रा श्रेयसी ने कला वर्ग से 489 अंक प्राप्त कर यह उपलब्धि हासिल की है.श्रेयसी के पिता घर के सामने एक किराना दुकान चलाते है, जबकि उसकी मां एक प्राथमिक विद्यालय की शिक्षिका है. गुरुवार को जैसे ही मेरिट लिस्ट में उसका नाम घोषित हुआ, परिवार और पूरे इलाके में खुशी की लहर दौड़ गई.स्कूल घर से काफी दूर होने के कारण श्रेयसी को रोजाना आने-जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था. कई बार उसे टोटो से लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी, और दूरी के कारण कभी कभी स्कूल जाना भी संभव नहीं हो पाता था. इसके बावजूद उसने सभी बाधाओं को पार कर यह सफलता हासिल की.श्रेयसी आगे भूगोल विषय में पढ़ाई करना चाहती है और भविष्य में सरकारी नौकरी करने का सपना देखती है. अपनी सफलता का श्रेय उसने अपने माता-पिता, स्कूल के शिक्षकों और ट्यूटर को दिया है. श्रेयसी की इस उपलब्धि पर उसके परिवार, स्कूल और पूरे इलाके में गर्व का माहौल है.

न्यूज़ कॉर्नर

मुख्यमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट करने के आरोप में दो गिरफ्तार

कूचबिहार : जिले के दिनहाटा क्षेत्र से दो ऑनलाइन कंटेंट क्रिएटर्स को मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने गुरुवार को यह जानकारी दी.पुलिस के मुताबिक, दोनों आरोपितों को बुधवार को उस वायरल वीडियो को लेकर मिली शिकायतों के आधार पर गिरफ्तार किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक और आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया था.दिनहाटा थाने की पुलिस ने मामले की जांच शुरू की, जिसके बाद दोनों को दिनहाटा इलाके से हिरासत में लेकर गिरफ्तार किया गया.प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपित सोशल मीडिया पर सक्रिय कंटेंट क्रिएटर्स है और उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म पर यह विवादित वीडियो पोस्ट किया था.पुलिस अधिकारी ने बताया कि शिकायत और शुरुआती जांच के आधार पर दोनों को पहले हिरासत में लिया गया और बाद में गिरफ्तार किया गया. मामले की जांच जारी है.इस बीच, पश्चिम बंगाल पुलिस ने एक बयान जारी कर कहा है कि कोई भी व्यक्ति किसी के खिलाफ अपमानजनक भाषा वाले कंटेंट को अपलोड या प्रसारित नहीं कर सकता, और न ही ऐसा कोई सामग्री साझा कर सकता है जिससे धार्मिक या सामाजिक भावनाएं आहत हों. नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

अवैध निर्माण पर कार्रवाई की तैयारी, यूपी से 24 जेसीबी मशीनों का ऑर्डर : सांसद राजू बिष्ट

सिलीगुड़ी : अवैध निर्माण और मादक गतिविधियों पर सख्त रुख अपनाते हुए दार्जिलिंग के सांसद राजू बिष्ट ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश (यूपी) से 24 जेसीबी मशीनों का ऑर्डर दिया गया है, जिनके आने पर शहर में अवैध निर्माणों पर बुलडोजर कार्रवाई तेज कर दी जाएगी.एसडीओ कार्यालय में गुरुवार को हुई एक उच्चस्तरीय बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए सांसद ने अवैध निर्माण करने वालों को चेतावनी दी कि वे खुद ही अपने निर्माण हटा लें, अन्यथा प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा.इस बैठक में पुलिस कमिश्नर सैयद वकार रजा, दार्जिलिंग के जिलाधिकारी हरिशंकर पनिक्कर, जिला एसपी और सिलीगुड़ी मेट्रोपोलिटन पुलिस के डीसीपी सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे. बैठक में शहर को मादक पदार्थों से मुक्त करने, अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने और कानून-व्यवस्था को मजबूत करने पर विस्तार से चर्चा हुई.सांसद बिष्ट ने कहा कि शहर में मादक तस्करी करने वालों की सूची उनके पास है और इस पर पुलिस प्रशासन के साथ समन्वय कर कार्रवाई की जाएगी. साथ ही, छोटे व्यापारियों से वसूले जा रहे कथित 'गुंडा टैक्स', अवैध टोल प्लाजा, अवैध शराब दुकानों और गैरकानूनी पब-बार के खिलाफ भी सख्त कदम उठाए जाएंगे.बिष्ट ने स्पष्ट किया कि यह परिवर्तन की सरकार है और इसमें किसी भी तरह की अवैध गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. प्रशासन अब अवैध निर्माणों की पहचान कर रहा है और आने वाले दिनों में बड़े स्तर पर कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है.

दांतन के सुवर्णरेखा नदी में नहाते समय 16 वर्षीय किशोर लापता

पश्चिम मेदिनीपुर : जिले के दांतन थाना क्षेत्र अंतर्गत बेलमूला घाट पर गुरुवार को दोस्तों के साथ स्नान करने आए एक 16 वर्षीय किशोर के नदी में डूबकर लापता होने की घटना से इलाके में सनसनी फैल गई.मिली जानकारी के अनुसार, पलसंडपुर इलाके का निवासी राजा प्रमाणिक (16) अपने दोस्तों के साथ सुवर्णरेखा नदी में स्नान कर रहा था, तभी अचानक वह गहरे पानी में डूब गया.प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, घटना के बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत बचाव कार्य शुरू किया.इस दौरान नदी में मौजूद अन्य तीन युवकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, लेकिन राजा प्रमाणिक का कोई पता नहीं चल सका. घटना की सूचना पाकर दांतन थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और तलाशी अभियान शुरू किया.

भारत-बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा मजबूत करने की तैयारी

45 दिन में जमीन हस्तांतरण का निर्देश

मालदा : भारत-बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. सीमा पर फेंसिंग (कांटेदार तार) लगाने के लिए 45 दिनों के भीतर जमीन हस्तांतरण करने का निर्देश जारी किया गया है. इसके बाद मालदा जिला प्रशासन ने 'युद्ध स्तर' पर काम शुरू कर दिया है.

मिली जानकारी के अनुसार, मालदा जिले में करीब 36 किलोमीटर लंबा सीमा क्षेत्र अब भी बिना फेंसिंग के है, जिससे घुसपैठ और तस्करी की घटनाएं लगातार सामने आती रहती है. इस पूरे इलाके में फेंसिंग और बॉर्डर रोड बनाने के लिए लगभग 260 एकड़ जमीन की आवश्यकता है.इसी मुद्दे पर गुरुवार को जिला प्रशासनिक

भवन में एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई.बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी राजनवीर सिंह कपूर ने की, जिसमें सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) और भूमि विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.

साथ ही राज्य के उच्च अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े.

हालांकि, खराब मौसम और बारिश प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है.

जिलाधिकारी राजनवीर सिंह कपूर ने कहा कि जमीन हस्तांतरण से जुड़ी समस्याओं की पहचान कर ली गई है और उम्मीद है कि तय समय सीमा के भीतर प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी. अगर यह परियोजना समय पर पूरी होती है, तो सीमा सुरक्षा और अधिक मजबूत होगी. हालांकि, मौसम की बाधाओं के बीच प्रशासन कितनी तेजी से काम पूरा करता है, इस पर सभी की नजरें टिकी है.

ब्राउन शुगर खरीदने आए तीन युवक पकड़े गए

सिलीगुड़ी : सिलीगुड़ी के नजदीक फुलबाड़ी इलाके में गुरुवार को ब्राउन शुगर खरीदने आए तीन युवकों को ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है. घटना फुलबाड़ी दो नंबर ग्राम पंचायत के कालांगिनी क्षेत्र की है.स्थानीय सूत्रों के अनुसार, तीन युवक तीन टोटो लेकर कालांगिनी पहुंचे थे. उनके संदिग्ध व्यवहार को देखकर इलाके की कुछ महिलाओं ने पहले उन्हें रोका और पूछताछ शुरू की. आरोप है कि पूछताछ के दौरान युवकों ने स्वीकार किया कि वे ब्राउन शुगर खरीदने आए थे. हालांकि, जिससे उन्हें मादक पदार्थ लेना था, उसका मोबाइल फोन बंद होने के कारण संपर्क नहीं हो सका.घटना की खबर फैलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुट गए. इसके बाद एनजेपी थाने की पुलिस को सूचना दी गई. पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों युवकों को हिरासत में लिया. पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.

जागरूकता से कार्रवाई तक : पूर्व रेलवे ने त्वरित प्रतिक्रिया चुनौती के साथ स्वच्छता को दी नई पहचान

कोलकाता : पिछले एक महीने से, पूर्व रेलवे ज़ोन में पहियों की लयबद्ध गड़गड़ाहट के साथ एक नई, सशक्त भावना गूंज रही है: स्वच्छता क्रांति की भावना. भारतीय रेल विरासत के 173 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाते हुए, पूर्व रेलवे ने पारंपरिक समारोहों से हटकर स्वच्छता के लिए एक ऊर्जावान अभियान की ओर कदम बढ़ाया है. महाप्रबंधक मिलिंद देऊस्कर के दूरदर्शी नेतृत्व में, ज़ोन ने 15 अप्रैल से 14 मई तक स्वच्छता जागरूकता अभियान का पहला चरण सफलतापूर्वक पूरा किया, जिससे स्टेशन और कोच बदलाव के गलियारे बन गए. इस विशाल परिवर्तन का हर पहलू श्री देऊस्कर के प्रत्यक्ष नेतृत्व और मार्गदर्शन में क्रियान्वित किया जा रहा है. इस प्रयास ने केवल झाड़ू तक सीमित न रहकर, सियालदह, हावड़ा, मालदा और आसनसोल-सभी चार मंडलों को एकजुट कर रेलवे नेटवर्क को करोड़ों यात्रियों का साझा घर मानते हुए आगे बढ़ाया.पहले चरण में पूर्व रेलवे के भारत स्काउट्स एंड गाइड्स की उमंग भरी ऊर्जा से प्रेरित एक अभूतपूर्व जन आंदोलन देखने को मिला. हावड़ा के प्लेटफार्म से लेकर मालदा की रेलवे कॉलोनियों तक, इन युवा स्वयंसेवकों ने न केवल सफाई की, बल्कि लोगों को प्रेरित भी किया. कांचरापारा में रचनात्मक नुक्कड़ नाटकों, बर्द्धमान में नारा लेखन प्रतियोगिताओं और यहां तक कि

नैहाटी में बच्चों को जोड़ने के लिए मिकी माउस और छोटा भीम जैसे लोकप्रिय शुभंकरों के उपयोग के माध्यम से, इस अभियान ने एक सामान्य प्रशासनिक कार्य को सामाजिक परिवर्तन की एक जीवंत कहानी में बदल दिया. महाप्रबंधक और अपर महाप्रबंधक सहित वरिष्ठ अधिकारियों ने स्वयं स्टेशनों का दौरा किया और पूर्वा एक्सप्रेस और विभिन्न एमईएमयू सेवाओं जैसी ट्रेनों में सवार होकर यात्रियों से बातचीत की, उनकी प्रतिक्रियाएँ एकत्र कीं और उन्हें ट्रेन में मौजूद कूड़ेदानों का उपयोग करने और जैव-शौचालयों को कचरे से मुक्त रखने के महत्व के बारे में जागरूक किया. इस व्यापक जनसमर्थन और उत्साह को आगे बढ़ाते हुए, पूर्व रेलवे 16 मई से 30 मई 2026 तक चलने वाले कार्यक्रम के दूसरे चरण की घोषणा करते हुए गर्व महसूस कर रहा है. इस चरण में एक क्रांतिकारी त्वरित प्रतिक्रिया का वादा शामिल है, जिसका उद्देश्य इसे देखें, इसकी सूचना दें, हम इस पर कार्रवाई करेंगे पहल के माध्यम से स्वच्छता की शक्ति सीधे यात्रियों के हाथों में देना है. यात्रियों के लिए इन ट्रेनों और स्टेशनों को अपना दूसरा घर मानने की भावना को ध्यान में रखते हुए, पूर्व रेलवे ईआर चैलेंज की शुरुआत कर रहा है.यह दूसरा चरण तकनीक और समर्पित कार्यबल का एक अनूठा संगम है, जिसमें चारों विभाग और सभी आंतरिक विभाग चौबीसों घंटे असंभव को संभव बनाने के लिए तत्पर हैं. जनता को वास्तविक समय की निगरानी में शामिल करके, पूर्व रेलवे का लक्ष्य यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाना और सभी के लिए एक स्वस्थ और सम्मानजनक यात्रा सुनिश्चित करना है. हालांकि, प्रशासन यह भी याद दिलाता है कि इस मानक को बनाए रखना एक सामूहिक कर्तव्य है. रेलवे परिसर में कूड़ा फेंकना या थूकना रेलवे अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध है, जिसके लिए 500 तक का जुर्माना हो सकता है. लक्ष्य अस्थायी सफाई अभियानों से आगे बढ़कर एक स्थायी नागरिक गौरव की संस्कृति को बढ़ावा देना है, जहां प्रत्येक यात्री पटरियों की सुंदरता को संरक्षित करने में सहभागी बने.जागरूकता फैलाने से लेकर वास्तविक समय में समाधान प्रदान करने तक के इस बदलाव पर विचार व्यक्त करते हुए, पूर्व रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शिबराम माझी ने कहा: हमारा पहला चरण मानसिकता को साफ करने से संबंधित था, और यह दूसरा चरण त्वरित कार्रवाई के माध्यम से अपनी प्रतिबद्धता को साबित करने के बारे में है. हम चाहते हैं कि प्रत्येक यात्री इस यात्रा में एक भागीदार महसूस करे. 30 मिनट के ईआर चैलेंज की शुरुआत करके, हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि स्वच्छता केवल एक वादा नहीं बल्कि आपकी उंगलियों पर एक उपलब्ध एक वास्तविकता बने. हम प्रत्येक यात्री से आग्रह करते हैं कि वे रेलवे परिसर को उसी सावधानी से संभालें जैसे वे अपने घरों को संभालते हैं. जब नागरिक और रेलवे मिलकर काम करते हैं, तो हमारा नेटवर्क केवल एक परिवहन व्यवस्था नहीं रहता, बल्कि राष्ट्रीय गौरव का स्वच्छ और सुंदर प्रतीक बन जाता है.

अग्नि सुरक्षा संस्थान के होनहार विद्यार्थी सम्मानित

बैंडेल : हुगली इंस्टिट्यूट ऑफ़ फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग ने होनहार और सफल स्टूडेंट्स का सम्मान समारोह 14 मई को बैंडेल के इंस्टिट्यूट रूम, सुभाष नगर में आयोजित किया. शुरुआत में, आए हुए मेहमानों को उत्तरीय पहनाकर सम्मानित किया गया. फिर उन्होंने इस इंस्टिट्यूट की सफलता और आने वाली पीढ़ियों को ध्यान में रखने के बारे में बताया. इसका मुख्य मकसद आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा करना है. इस इंस्टिट्यूट के सफल स्टूडेंट्स को सम्मानित करने के लिए आयोजित इस समारोह में, इंस्टिट्यूट से पास करने वाले लोगों के माता-पिता मौजूद थे और उन्होंने स्टूडेंट्स की सफलता के पीछे हुगली इंस्टिट्यूट ऑफ़ फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग इंस्टिट्यूट की खास भूमिका पर ज़ोर दिया. छात्रों को जुपिटर वैगन लिमिटेड के सेफ्टी हेड ऑफिसर आमोद सिंह को हुगली फायर स्टेशन बड़ाबाबू और मेजो बाबू ने सम्मानित किया, जिन्होंने अपने भाषणों के माध्यम से सफलता के पहलुओं पर प्रकाश डाला.

बिहार-यूपी वालों पर कल्याण बनर्जी के बयान से तृणमूल के हिंदीभाषी नेताओं में आक्रोश

हुगली : पश्चिम बंगाल में रहने वाले बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों को लेकर कल्याण बनर्जी द्वारा हाल ही में दिए गए विवादास्पद बयान को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है. भाजपा ने बुधवार को ही साफ कर दिया था कि हार के बौखलाहट में तृणमूल सांसद अनर्गल बयानबाजी कर रहें हैं. गुरुवार को तृणमूल कांग्रेस के हिंदीभाषी नेताओं ने भी कल्याण बनर्जी के बयान की आलोचना की.चांपदानी नगरपालिका के चेयरमैन और हुगली जिले के कद्दावर हिंदीभाषी नेता सुरेश मिश्रा ने कहा कि वे सांसद के बयान से आहत हैं.

कल्याण बनर्जी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए मिश्रा ने कहा, क्रिमिनल का कोई जाति धर्म नहीं होता है. समाज विरोधी कहीं का भी हो वो समाजविरोधी होता है. उत्तर प्रदेश और बिहार से आए सभी लोगों को एक ही चश्मे से देखना ठीक नहीं है. मेरी जड़ें खुद उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई हैं. मेरे दादाजी यहां आए थे. मेरा जन्म यहां हुआ है. लेकिन सांसद के इस बयान से मैं बेहद आहत हूं.वहीं कल्याण बनर्जी के बिहार यूपी के लोगों पर दिए गए आपत्तिजनक बयान के विरोध में कई नेताओं ने कल्याण बनर्जी के तस्वीर को अपने कार्यालय से हटा दिया है.उल्लेखनीय है कि श्रीरामपुर के तृणमूल सांसद काल्याण बनर्जी ने हाल ही में एक प्रेस कांफ्रेंस के दौरान यूपी बिहार के लोगों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. इसके बाद से ही उनकी चौतरफा आलोचना हो रही है.

बेलदा में नगदी और जेवरात की लूट, 24 घंटे में एक आरोपित गिरफ्तार

खड़गपुर : पश्चिम मेदिनीपुर जिले के बेलदा क्षेत्र में 60 हजार रुपये नगद और सोने के गहनों की लूट के मामले में पुलिस ने एक आरोपित को गिरफ्तार किया है. जानकारी के अनुसार, नारायणगढ़ ब्लॉक के बखराबाद ग्राम पंचायत के जंगुरिया इलाके के निवासी सुभल चंद्र माइती बुधवार को बेलदा स्थित एक को-ऑपरेटिव बैंक में सोने के गहने गिरवी रखकर लगभग 60 हजार रुपये का ऋण लेकर लौट रहे थे.आरोप है कि घर लौटते समय मोटरसाइकिल सवार तीन अज्ञात बदमाशों ने उन्हें रोक लिया और उनके पास से 60 हजार रुपये नकद तथा सोने के गहने लूट लिए.

पुरुलिया से पश्चिम मेदिनीपुर तक बालू घाटों पर सख्ती का असर

मेदिनीपुर : विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद भी जिले के कुछ बालू घाटों से बालू उठाने की तस्वीरें सामने आई थीं. लेकिन राज्य नए मुख्यमंत्री बनने के बाद स्थिति में बदलाव देखने को मिला है. कई जगहों पर बालू घाटों की गतिविधियां थम गई हैं और माहौल शांत दिखाई दे रहा है.सूत्रों के अनुसार, पुरुलिया जिले में कुल 14 वैध बालू घाट हैं, जो पश्चिम बंगाल मिनरल डेवलपमेंट एंड ट्रेडिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से नीलामी प्रक्रिया के तहत संचालित होते हैं. पहले बालू कारोबार को लेकर लंबे समय से अनियमितता और सिंडिकेट के प्रभाव के आरोप लगते रहे हैं.स्थानीय लोगों का कहना है कि बिना सरकारी नियंत्रण के बालू की कीमतें कई गुना तक बढ़ जाती थीं और अवैध घाटों से भी बड़े पैमाने पर खनन होता था.हाल के घटनाक्रम के बाद कई वैध घाटों पर सन्नाटा पसरा हुआ है. प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, यह स्थिति अस्थायी है और जल्द ही नियमित संचालन बहाल किया जाएगा.इसी बीच, पश्चिम मेदिनीपुर जिले में भी बालू घाटों की भूमिका स्थानीय अर्थव्यवस्था और निर्माण कार्यों के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है. यहां शीलावती, सुवर्णरेखा और कंसाबती जैसी प्रमुख नदियों के किनारे खनन गतिविधियां संचालित होती हैं. वर्तमान में राज्य सरकार और पश्चिम बंगाल खनिज विकास एवं व्यापार निगम की ओर से गड़वेता-खख जैसे क्षेत्रों में वैज्ञानिक और पर्यावरण-अनुकूल खनन के लिए नई निविदाएं जारी की जा रही हैं, ताकि अवैध उत्खनन पर प्रभावी रोक लगाई जा सके.इन घाटों के प्रबंधन के लिए जिला भूमि एवं भूमि सुधार कार्यालय (डीएल एवं एलआरओ) और राज्य स्तरीय समितियों द्वारा कड़े नियम लागू किए गए हैं, जिनका उद्देश्य पर्यावरण सुरक्षा सुनिश्चित करना और राजस्व व्यवस्था को मजबूत बनाना बताया जा रहा है.

सिलीगुड़ी में 'महाकाल महातीर्थ' परियोजना पर अनिश्चितता, काम धीमा

सिलीगुड़ी : माटीगाड़ा उपनगर के पास खाली पड़ी जमीन पर बनने वाला बहुचर्चित 'महाकाल महातीर्थ' प्रोजेक्ट अब अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा है. इसी साल की शुरुआत में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़े धूमधाम से इस परियोजना की आधारशिला रखी थी, लेकिन राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद अब इसकी रफ्तार धीमी पड़ गई है.यह परियोजना करीब 17.81 एकड़ जमीन पर विकसित की जानी थी, जिसमें 108 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा और देश के 12 ज्योतिर्लिंगों की प्रतिकृतियां बनाने की योजना थी. इसे ढाई साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था, ताकि सिलीगुड़ी को एक प्रमुख धार्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जा सके.

हालांकि, अब राजनीतिक परिस्थितियां बदल चुकी है.राज्य में

भाजपा की सरकार बनने के बाद यह परियोजना दुविधा का विषय बन गई है. एक ओर हिंदुत्व की विचारधारा के चलते मंदिर निर्माण को रोकना आसान नहीं है, वहीं दूसरी ओर सरकारी फंड से मंदिर निर्माण को लेकर पहले जताए गए विरोध के कारण नई सरकार के सामने आर्थिक व्यवस्था एक बड़ी चुनौती बन गई है.इस बीच, परियोजना के लिए गठित ट्रस्ट बोर्ड को भी नई अधिसूचना के बाद भंग कर दिया गया है, जिससे प्रशासनिक स्तर पर भी असमंजस की स्थिति बन गई है.अधिकारियों का कहना है कि अब नई सरकार की नीति का इंतजार करना होगा.सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देव ने भी इस मुद्दे पर अनिश्चितता जताते हुए कहा कि नई सरकार इस परियोजना को लेकर क्या फैसला लेगी, यह अभी स्पष्ट नहीं है.

वहीं, स्थानीय जनप्रतिनिधियों का मानना है कि इस तरह की बड़ी परियोजना से क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा.

माटीगाड़ा-नक्सलबाड़ी के विधायक आनंदमय बर्मन और सिलीगुड़ी के विधायक शंकर घोष ने भी उम्मीद जताई है कि परियोजना को आगे बढ़ाया जाएगा.दार्जिलिंग के सांसद राजू बिष्ट ने भी मंदिर निर्माण के पक्ष में राय दी, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि किसी सरकार के लिए सीधे मंदिर निर्माण में फंड देना संभव नहीं है, इसलिए वित्तीय स्रोत तय करना जरूरी है.फिलहाल, परियोजना स्थल पर धीमी गति से कुछ काम जारी है, लेकिन यह भव्य 'महाकाल महातीर्थ' कब पूरा होगा, इसे लेकर स्थिति अभी भी साफ नहीं है.

नगर निगम में मेयर के चेंबर से ममता बनर्जी की तस्वीर हटाने को लेकर विवाद

पश्चिम बर्दवान : आसनसोल नगर निगम में एक नया सियासी विवाद सामने आया है. मेयर चेंबर के अंदर पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तस्वीर अब भी लगी होने पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेताओं ने कड़ी आपत्ति जताई है. उनका कहना है कि राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद भी पुराने राजनीतिक प्रतीकों को बनाए रखना उचित नहीं है.भाजपा नेता केशब पोद्दार ने तस्वीर को तुरंत हटाने की मांग की है. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं की गई, तो पार्टी इस मुद्दे पर बड़ा आंदोलन करेगी.आसनसोल के मेयर बिधान उपाध्याय ने स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार का बदलाव केवल सरकारी निर्देश मिलने के बाद ही किया जाएगा. उन्होंने कहा कि बिना आधिकारिक आदेश के तस्वीर हटाना संभव नहीं है.इस पूरे मामले ने शहर की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है.

महानगर में अवैध पार्किंग वसूली पर फूटा मंत्री अग्निमित्रा पाल का गुस्सा

कड़ी निगरानी का निर्देश देते हुए मंत्री ने कही कार्रवाई की बात

कोलकाताः भाजपा सरकार के आते ही तमाम जगहों पर कथित तौर पर पार्टी के ही नेताओं के निर्देश पर अवैध पार्किंग से लेकर वसूली शुरु हो गई है. ऐसे में राज्य की मंत्री अग्निमित्रा पाल ने गुरुवार को इस पर सख्ती दिखाई है और साफ कहा कि, लिप्त लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी. राज्य की मंत्री अग्निमित्रा पाल ने आज ही शहरी सेवाओं के आधुनिकीकरण और कथित तौर पर 15 वर्षों से चली आ रही नागरिक अनियमितताओं को समाप्त करने के उद्देश्य से कई कठोर नीतियों की घोषणा की. कोलकाता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए, राज्य की मंत्री अग्निमित्रा पाल ने ट्राफिक जाम और अवैध पार्किंग की वसूली की लंबे समय से चली आ रही समस्याओं पर ध्यान केंद्रित किया. सबसे तत्काल बदलाव के तहत ट्राफिक को सुगम बनाने के लिए शहर की सभी सड़कों पर एक तरफा पार्किंग का नियम लागू किया जाएगा. प्रशासन ने जोर दिया कि दो तरफा पार्किंग ने कोलकाता और आसनसोल जैसे शहरों में लंबे समय से आवागमन को बाधित कर रखा है, और यातायात व्यवस्था को सामान्य करने के लिए तत्काल सख्त प्रवर्तन शुरू किया जाएगा. मंत्री ने अवैध रूप से वसूले जा रहे पार्किंग शुल्क के खिलाफ सख्त कार्रवाई की घोषणा की, जिसके बारे में उन्होंने आरोप लगाया कि यह राजस्व के भारी नुकसान का स्रोत बन गया है. पाल ने कहा कि पिछली सरकार के समय, पार्किंग शुल्क का पैसा स्थानीय गिरोहों द्वारा सरकारी खजाने तक पहुंचने से पहले ही हड़प लिया जाता था. इससे निपटने के लिए, नगर पालिका और शहरी विकास विभाग अब सभी पार्किंग क्षेत्रों की संयुक्त रूप से निगरानी करेंगे. सरकार ने चेतावनी दी कि किसी भी प्रकार की अनधिकृत वसूली को आपराधिक अपराध माना जाएगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी शुल्क आधिकारिक कर के रूप में दर्ज किए जाएं ताकि शहरी विकास के लिए धन जुटाया जा सके. जन सुरक्षा और स्वच्छता के मोर्चे पर, सरकार बाल एवं महिला हेल्पलाइनों को एक मजबूत आपातकालीन नंबर में एकीकृत कर रही है. इस पहल में तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए महिला एवं बाल कल्याण विभाग के अंतर्गत समर्पित कॉल सेंटर स्थापित करना शामिल है. इसके अलावा, पॉल ने शहर के कचरा संकट के लिए एक तकनीक-आधारित समाधान पेश किया है. एक नया मोबाइल ऐप नागरिकों को कचरे की जियोटैग वाली तस्वीरें अपलोड करने की अनुमति देगा. एक बार तस्वीर जमा हो जाने पर, संबंधित नगर निगम को दो घंटे के भीतर उस स्थान को साफ करना अनिवार्य होगा, जो प्रौद्योगिकी-आधारित जवाबदेही की दिशा में एक महत्वपूर्ण बदलाव है.

एडीपीसी को ईडी ने मनोरंजन मंडल के गिरफ्तारी का दिया आदेश

कोलकाताः कोयला घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आसनसोल-दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट (एडीपीसी) को बड़ा निर्देश जारी किया है. ईडी ने बुदबुद थाना के पूर्व प्रभारी मनोरंजन मंडल को गिरफ्तार करने का आदेश दिया है. सूत्रों के अनुसार, कोयला तस्करी और अवैध खनन से जुड़े इस बहुचर्चित घोटाले की जांच के दौरान ईडी को बुदबुद थाना पूर्व प्रभारी की भूमिका संदिग्ध प्रतीत हुई. जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर ईडी ने पुलिस कमिश्नरेट को तत्काल कार्रवाई करते हुए संबंधित अधिकारी को हिरासत में लेने का निर्देश भेजा है. इस कार्रवाई को कोयला घोटाले में प्रशासनिक स्तर पर संभावित मिलीभगत की जांच को तेज करने के रूप में देखा जा रहा है.

ममता बनर्जी की कालीघाट में तृणमूल सांसदों संग अहम बैठक

चुनाव बाद हालात और आंदोलन रणनीति पर चर्चा

कोलकाताः पश्चिम बंगाल में राजनीतिक माहौल के बीच गुरुवार को कोलकाता के कालीघाट स्थित पार्टी कार्यालय में तृणमूल कांग्रेस की अहम बैठक हुई. इस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने की. बैठक में पार्टी के सांसदों और राज्यसभा सदस्यों ने भाग लिया. इनमें अभिषेक बनर्जी, सौगत राय, सुदीप बनर्जी, कल्याण बनर्जी, शताब्दी राय और यूसुफ पठान सहित कई नेता मौजूद रहे. बैठक शाम करीब चार बजे शुरू हुई. पार्टी सूत्रों के अनुसार, बैठक में चुनाव के बाद की स्थिति और तृणमूल कांग्रेस द्वारा लगाए जा रहे मतदान में अनियमितता व हिंसा के आरोपों पर चर्चा हुई. साथ ही आने वाले दिनों में विरोध-प्रदर्शन और राजनीतिक आंदोलन की रूपरेखा भी तय की गई. बताया गया कि जिला स्तर से लेकर राज्य स्तर तक विरोध कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. बैठक में चुनाव के बाद हुई हिंसा की घटनाओं का मुद्दा भी उठा. तृणमूल का दावा है कि चुनाव के बाद विभिन्न इलाकों में पार्टी के 10 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है और कई पार्टी कार्यालयों में तोड़फोड़ की गई है. घबराकर घर छोड़ने वाले कार्यकर्ताओं की सुरक्षित वापसी और इस संबंध में अदालत के निर्देशों पर भी चर्चा की गई. बैठक के बाद सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस पहले की तरह सड़कों पर उतरकर आंदोलन जारी रखेगी.

बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद अजीब इत्तेफाक

14 साल बाद किसी अमेरिकी विदेश मंत्री का होगा कोलकाता आगमन

कोलकाताः बंगाल में सत्ता परिवर्तन ने अंतरराष्ट्रीय गलियारों में भी हलचल तेज कर दी है. राज्य में भाजपा सरकार के गठन को अभी महज पांच दिन ही हुए हैं, और संयोग देखिए कि ठीक 14 साल बाद कोलकाता की धरती पर किसी शीर्ष अमेरिकी राजनयिक के कदम पड़ने वाले हैं. अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो इस महीने के अंत में भारत दौरे पर आ रहे हैं, और सूत्रों की मानें तो दिल्ली के साथ-साथ उनके एजेंडे में कोलकाता भी शामिल है. आखिरी बार नवंबर 2012 में तत्कालीन अमेरिकी विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन कोलकाता आई थीं. उस समय 34 वर्षों के वामपंथी शासन के अंत के बाद ममता बनर्जी के शासन को एक साल से कुछ अधिस समय हुआ था. उन्होंने राइटर्स बिल्डिंग जाकर तत्कालीन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की थी. उसके बाद से, मोदी युग में ओबामा से लेकर जो बाइडन और पुतिन से लेकर शी जिनपिंग तक भारत आए, लेकिन कोलकाता अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के नक्शे से लगभग गायब रहा. जी-20 से लेकर ब्रिक्स सम्मेलन तक हुए, मेहमान अहमदाबाद और महाबलीपुरम तो गए, पर बंगाल बड़े अंतरराष्ट्रीय आयोजन से दूर रहा. इतिहास गवाह है कि बंगाल में विदेशी मेहमानों का अनुभव हमेशा सुखद नहीं रहा. 1968 में राबर्ट मैकनामारा को वामपंथी विरोध के कारण हेलीकाप्टर से भागना पड़ा था. मदर टेरेसा के अंतिम संस्कार को छोड़ दें, तो बंगाल की धरती पर कूटनीतिक सक्रियता न के बराबर रही. विशेषज्ञों का मानना है कि राज्य में सत्ता परिवर्तन और शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में नई सरकार के आते ही स्थिति बदल रही है. 24 से 26 मई के बीच रुबियो की यह यात्रा, जिसमें क्वाड देशों की बैठक भी शामिल है, न केवल ईरान युद्ध के साये में वैश्विक महत्व रखती है, बल्कि बंगाल के लिए आर्थिक और कूटनीतिक पुनर्जागरण' का संकेत भी है. यदि मार्को रुबियो कोलकाता आते हैं, तो यह महज एक दौरा नहीं, बल्कि बंगाल के उस वनवास की समाप्ति होगी जिसने इसे वर्षों तक वैश्विक निवेश और विमर्श से दूर रखा था.

आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में भागीदारी करें बंगालवासी : राज्यपाल का ईंधन बचत और 'वोकल फॉर लोकल' पर जोर

कोलकाताः पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आर एन रवि ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश को आगे बढ़ाते हुए राज्य के लोगों से आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में सक्रिय भागीदारी की अपील की है. गुरुवार को सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर जारी संदेश में राज्यपाल ने ईंधन बचत, जिम्मेदार उपभोग और जनभागीदारी के माध्यम से देश को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का आह्वान किया. राज्यपाल ने नागरिकों से ईंधन की बचत करने, सार्वजनिक परिवहन और कारपूलिंग को बढ़ावा देने तथा 'वोकल फॉर लोकल' अभियान के तहत स्वदेशी उत्पादों को प्राथमिकता देने की अपील की. उन्होंने घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने का भी आग्रह किया. अपने संदेश में उन्होंने कहा कि संसाधनों का जिम्मेदारी से उपयोग, खाद्य तेल की सीमित खपत, अनावश्यक आयात में कमी और सोने की खरीदारी में विवेकपूर्ण निर्णय देश की आर्थिक नींव को और मजबूत कर सकते हैं. उन्होंने प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन देने को भी आत्मनिर्भर भारत की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया. राज्यपाल ने केवल आम नागरिकों ही नहीं, बल्कि विभिन्न संस्थानों और उद्योग संगठनों से भी अपील की कि जहां संभव हो, वहां वर्चुअल बैठकों और 'वर्क फ्रॉम होम' व्यवस्था को बढ़ावा दिया जाए, ताकि राष्ट्रीय संसाधनों की बचत हो सके. उन्होंने कहा कि भारत की वास्तविक शक्ति 'जनभागीदारी' में निहित है और जब नागरिक सेवा की भावना के साथ एकजुट होकर काम करते हैं, तभी राष्ट्र निर्माण का उद्देश्य सफल होता है. राज्यपाल ने आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ एक मजबूत और स्थिर भारत के निर्माण में सभी से योगदान देने का आह्वान किया.

ममता बनर्जी की करीबी रहीं नंदिनी चक्रवर्ती को शुभेंदु सरकार में मिली अहम जिम्मेदारी

कोलकाताः पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती को मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली नई राज्य सरकार में अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है. विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद चुनाव आयोग द्वारा पद से हटाई गईं नंदिनी चक्रवर्ती को अब मुख्यमंत्री कार्यालय के अधीन विकास कार्यों की प्रधान समन्वयक के रूप में महत्वपूर्ण दायित्व दिया गया है. नवान्न सूत्रों के अनुसार, नंदिनी चक्रवर्ती को भारत-बांग्लादेश अंतरराष्ट्रीय सीमा पर बाड़बंदी के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन हस्तांतरण की प्रक्रिया की निगरानी की जिम्मेदारी दी गई है. नई राज्य मंत्रिमंडल की 11 मई को हुई पहली बैठक में इस प्रक्रिया को अगले 45 दिनों के भीतर पूरा करने का प्रस्ताव पारित किया गया था. सूत्रों ने बताया कि प्रशासनिक अनुभव और गृह विभाग समेत कई महत्वपूर्ण विभागों में कार्य करने के कारण नंदिनी चक्रवर्ती को इस जिम्मेदारी के लिए उपयुक्त माना गया है. वह केंद्र प्रायोजित विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी भी करेंगी. भारतीय प्रशासनिक सेवा में पश्चिम बंगाल कैडर की नंदिनी चक्रवर्ती राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव रही हैं. हालांकि, उनका कार्यकाल काफी छोटा रहा. 15 मार्च को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार द्वारा विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के कुछ घंटों बाद ही चुनाव आयोग ने उन्हें पद से हटा दिया था. नंदिनी चक्रवर्ती को पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की करीबी अधिकारियों में गिना जाता था. उन्होंने राज्य के गृह सचिव, सूचना एवं संस्कृति विभाग की सचिव तथा पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल सीवी आनंद बोस की सचिव के रूप में भी कार्य किया है. राजनीति विज्ञान में स्नातक नंदिनी चक्रवर्ती ने कोलकाता के लेडी ब्रेबोर्न कॉलेज और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त की है. जनवरी, 2026 में उन्हें कई वरिष्ठ अधिकारियों की वरिष्ठता को दरकिनार कर मुख्य सचिव बनाया गया था, जिसे लेकर भी विवाद खड़ा हुआ था.

टीएमसी को अब भी नहीं नतीजों पर ऐतबार

सायोनी घोष ने कहा- हारें नहीं, हमको हराया गया

कोलकाताः पश्चिम बंगाल विधानसभा के नतीजों को 10 दिन बीत चुके है. विजयी पार्टी भाजपा के नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ मंत्रियों ने शपथ ले ली है और नई सरकार ने बंगाल में कामकाज शुरू भी कर दिया है. हालांकि तृणमूल कांग्रेस के नेता अब भी नतीजों को लेकर आशंकित है. उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा कि, प्रचंड सीटों के साथ 10 सालों तक बंगाल में सत्ताशीन रही ममता बनर्जी की पार्टी को इस चुनाव 100 से भी कम सीट हासिल हुई है, उन्हें सात विरोधी लहर का खामियाजा भुगतना पड़ा हैं. दरअसल हम बात करे हैं टीएमसी के महिला सांसद सायोनी घोष के उस बयान की जिसमे उन्होंने फिर से वोट चोरी का राग अलापा है. बता दें कि, नतीजों के बाद आज टीएमसी की महिला सांसद सायोनी घोष पूर्व सीएम ममता बनर्जी से सौजन्य भेंट करने उनके आवास पर पहुंची थी. इस दौरान मीडिया ने उनसे नतीजों को लेकर सवाल पूछे. पत्रकारों के सवाल पर सांसद घोष ने कहा, हम हारे नहीं हैं, बल्कि ममता बनर्जी पर पराजय हुई है. ममता बनर्जी को वोटों की चोरी और लूट के जरिए हराया गया है. 2029 में बंगाल की जनता, पूरे देश की जनता और 2031 में पश्चिम बंगाल की माताएं, धरती और जनता उन्हें मुंहतोड़ जवाब देंगी.

हाईकोर्ट परिसर में ममता को लेकर नारेबाजी, शमीक भट्टाचार्य बोले- यह भाजपा की संस्कृति नहीं

कोलकाताः पश्चिम बंगाल की राजनीति में उस समय हलचल बढ़ गई जब कोलकाता हाईकोर्ट परिसर के बाहर पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लेकर चोर-चोर के नारे लगाए गए. इस घटना को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. शमीक भट्टाचार्य ने कहा कि यह घटना भाजपा की संस्कृति नहीं है और न ही पार्टी ऐसे किसी व्यवहार का समर्थन करती है. उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा हालात की जिम्मेदारी तृणमूल कांग्रेस की है. उन्होंने कहा कि कृतकर्म का फल हमेशा पीछे आता है और इस तरह की घटनाएं समाज के लिए ठीक नहीं हैं. उन्होंने यह भी कहा कि एक स्वस्थ और सामान्य समाज में इस तरह की स्थिति नहीं होनी चाहिए. इधर, यह पूरा मामला उस समय हुआ जब ममता बनर्जी हाईकोर्ट में पोस्ट पोल हिंसा से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान मौजूद थीं. अदालत परिसर के बाहर कुछ वकीलों और लोगों ने उनके खिलाफ नारेबाजी की, जिसके बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया. भट्टाचार्य ने आगे कहा कि पश्चिम बंगाल में किसी भी तरह की हिंसा स्वीकार नहीं की जाएगी और कानून-व्यवस्था बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है. उन्होंने दावा किया कि राज्य में विकास और रोजगार पर ध्यान देने की जरूरत है.

ममता का काला कोर्ट में हाईकोर्ट आना सिर्फ 'ड्रामा' है: हुमायूं

स्कूलों में 'वंदे मातरम' गायन का कबीर ने समर्थन किया

कोलकाताः पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की, चुनाव के बाद कथित हिंसा के मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट जाने को लेकर आम जनता उन्नयन पार्टी (एजेयूपी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और विधायक हुमायूं कबीर ने गुरुवार को नाटक करार दिया इसकी उन्होंने आलोचना की. उन्होंने इसे 'कोरा नाटक' करार दिया और दावा किया कि चुनाव के बाद ऐसी कोई घटना हुई ही नहीं थी. कबीर ने चुनाव के बाद हुई हिंसा के आरोपों पर सवाल उठाए और बनर्जी पर आरोप लगाया कि उन्होंने 2021 में अपने कार्यकाल के दौरान कथित तौर पर हुई घटनाओं को नजरअंदाज किया. कबीर ने कहा, चुनाव के बाद हिंसा कहां हुई? 2021 में, जब वह मुख्यमंत्री थीं, तो कई लोगों की जान खतरे में थी, और कई लोग मारे गए थे. अब उसे याद नहीं किया जा रहा है. वह भूल रही है कि पहले क्या किया गया था. उन्होंने आगे आरोप लगाया कि बनर्जी का हाई कोर्ट जाना राजनीतिक रूप से प्रेरित था और इसका मकसद सिर्फ लोगों का ध्यान खींचना था. उन्होंने आगे कहा, आज वह सिर्फ नाटक कर रही हैं और एक नाटक के लिए हाई कोर्ट जा रही हैं. इससे कोई मकसद पूरा नहीं होगा. यह सब नाटक है, किसी को चोट नहीं लगी, चुनाव के बाद कोई हिंसा नहीं हुई. कबीर ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के उस ऐलान पर भी प्रतिक्रिया दी, जिसमें कहा गया था कि सोमवार से पूरे पश्चिम बंगाल के स्कूलों में राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम' गाया जाएगा. इस कदम का समर्थन करते हुए कबीर ने कहा कि यह नारा और गीत देश की पहचान का एक अहम हिस्सा हैं और इस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए. उन्होंने कहा, 'वंदे मातरम' भारत का नारा है. यह मातृभूमि का राष्ट्रगीत है. तो इसमें क्या दिक्कत है? पहले भी स्कूलों, कॉलेजों और कई जगहों पर 'वंदे मातरम' गाया जाता था. तो अगर मुख्यमंत्री ने ऐसा कहा है, तो इसमें क्या परेशानी है? किसी को भी इस पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए.

वायरल वीडियो में भड़काऊ टिप्पणी करने के आरोप में टीएमसी विधायक के आवास पर छापेमारी

कोलकाताः पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के बिष्णुपुर में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) विधायक दिलीप मंडल के दो घरों पर पुलिस ने बृहस्पतिवार को छापेमारी की. मंडल पर एक वीडियो संदेश में भड़काऊ टिप्पणी करने और भाजपा कार्यकर्ताओं को धमकी देने का आरोप है. एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि डायमंड हार्बर जिला पुलिस केंद्रीय बलों के साथ सुबह पायलान क्षेत्र में विधायक के आवास पर पहुंची. पुलिस अधिकारी ने बताया, प्राथमिकी में दर्ज विशिष्ट आरोपों के आधार पर जारी जांच के तहत तलाशी अभियान चलाया जा रहा है. कानून के अनुसार सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं. वायरल हो रहे वीडियो में, मंडल को एक जनसभा के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ धमकी भरे बयान देते हुए सुना जा सकता है. अधिकारी ने बताया कि बिष्णुपुर के विधायक के खिलाफ गैर-जमानती धाराओं के तहत दो प्राथमिकी दर्ज की गई हैं. उन्होंने बताया कि पुलिस टीम के पहुंचने पर मंडल अपने आवास पर मौजूद नहीं थे. हालांकि, अधिकारी ने बताया कि उन्हें आज सुबह इलाके में देखा गया था.

तृणमूल में भाई भतीजावाद के आरोप

पार्टी विधायक कुणाल घोष की टिप्पणी से पार्टी में हलचल

कोलकाताः तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधायक कुणाल घोष ने शपथ ग्रहण के बाद अपनी ही पार्टी के खिलाफ बयान देकर राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है. उन्होंने संगठन में 'स्वजनपोषण' (भाई भतीजावाद) और आंतरिक गुटबाजी को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं. विधानसभा चुनाव में जीत के बाद विधायक पद की शपथ लेने के तुरंत बाद कुणाल घोष ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उत्तर और मध्य कोलकाता में पहले जिन नेताओं तापस राय और सजल घोष को पार्टी छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा था, उन्हें रोकने की कोशिश की गई थी, लेकिन सफलता नहीं मिली. उन्होंने लिखा कि आज वही नेता विधायक बन चुके हैं, जबकि वे स्वयं भी तृणमूल कांग्रेस के विधायक के रूप में शपथ ले रहे हैं. कुणाल घोष ने आरोप लगाया कि पार्टी में स्वजनपोषण की राजनीति चल रही है, जिससे कार्यकर्ताओं में असंतोष बढ़ रहा है. अपने पोस्ट में उन्होंने कहा कि पार्टी को मजबूत करने के लिए आत्ममंथन जरूरी है. हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस के साथ ही बने रहेंगे और संगठन के लिए संघर्ष जारी रहेगा.

नगर निकाय भर्ती घोटाला : ईडी का दावा, सुजीत बोस के करीबी संस्थानों के जरिए हुआ करोड़ों का लेनदेन

कोलकाताः नगर निकाय भर्ती घोटाले की जांच में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि पश्चिम बंगाल के पूर्व अग्निशमन मंत्री सुजीत बोस से जुड़े दो निजी संस्थानों के माध्यम से कथित तौर पर करोड़ों रुपये के लेनदेन किए गए. एजेंसी का आरोप है कि भर्ती घोटाले के काले धन को सफेद करने के लिए इन कंपनियों का इस्तेमाल किया गया. ईडी ने 11 मई को सुजीत बोस को गिरफ्तार किया था. जांच एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक, मामले के गवाह रहे कुछ कारोबारियों के बयान से महत्वपूर्ण जानकारी हाथ लगी है. जांच में पता चला है कि संबंधित कंपनियों में से एक खुद को लॉजिस्टिक सेवा प्रदाता बताती है. ईडी ने वर्ष 2016 में सुजीत बोस और उक्त कंपनी के बीच हुए एक समझौता पत्र को भी जब्त किया है. एक अगस्त 2016 को हुए इस समझौते के अनुसार, 'मैनपावर सप्लाई एंड मैनेजमेंट' सेवाओं के बदले कंपनी हर महीने ढाई लाख रुपये सुजीत बोस को देती थी. जांच एजेंसी का दावा है कि इस कंपनी और एक सरकारी बैंक में मौजूद सुजीत बोस के खाते के बीच वित्तीय लेनदेन के प्रमाण मिले हैं. ईडी के अनुसार, कंपनी प्रबंधन ने पूछताछ में बताया कि अंडाल, डानकुनी और कोलकाता के हाइड रोड स्थित गोदामों में श्रमिक अक्सर काम बंद कर देते थे तथा श्रमिक यूनियनों के साथ विवाद होता था. ऐसे मामलों को सुलझाने के लिए सुजीत बोस की मदद ली जाती थी और इसके एवज में उन्हें मासिक भुगतान किया जाता था. हालांकि ईडी को संदेह है कि यह भुगतान वास्तविक श्रमिक प्रबंधन सेवाओं के लिए नहीं, बल्कि भर्ती घोटाले से जुड़े धन को घुमाकर सुजीत बोस और उनके परिवार तक पहुंचाने का माध्यम था. जांच में यह भी सामने आया है कि सुजीत बोस के पुत्र समुद्र बोस के आयकर रिटर्न के अनुसार संबंधित कंपनी ने उन्हें 83 लाख रुपये का भुगतान किया था. वहीं उनकी पुत्री मोहिनी बोस के आयकर दस्तावेजों में दूसरी कंपनी से एक करोड़ सात लाख रुपये प्राप्त होने का उल्लेख मिला है. ईडी का कहना है कि इन भुगतानों के पीछे का स्पष्ट कारण अब तक सामने नहीं आया है. हालांकि समुद्र बोस पहले ही कह चुके हैं कि ईडी केवल आरोप लगा रही है और एजेंसी को अपने दावों को साबित करना होगा.

आपकी वेदना, हमारी संवेदना
युवा शक्ति समाचार पत्र उठावना का विज्ञापन मात्र 1500 रुपये में प्रकाशित करता है
(साइज 12x8)
सम्पर्क :
मो. : 9831572125, 9831494084
www.yuvashakti.news.com
email: yuvashakti@hotmail.com

पूर्व रेलवे
निविदा सूचना सं. एसजी.निविदा/डीएसटीई/एसडीएएच/614, दिनांक 13.05.2026, वरिष्ठ डीएसटीई, पूर्व रेलवे, सियालदह, दूसरी मंजिल, कंट्रोल बिल्डिंग, डीआरएम बिल्डिंग, काइजर स्ट्रीट, सियालदह, कोलकाता-700014 द्वारा निम्नलिखित कार्य के लिए ई-निविदा आमंत्रित की जाती है: ई-निविदा सं. : एसडीएसटीई/एसआईजी/टी/05/26-27/आरआरएसके। कार्य का नाम एवं इसका स्थान: सियालदह मंडल के दक्षिण खंड में सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस सहित अर्थिंग सिस्टम का पुनर्स्थापन। निविदा मूल्य : रु.2,28,65,308.23, बयाना राशि/बोली प्रतिभूति जमा की जाएगी : रु.4,57,300/-, निविदा कागजात का मूल्य : शून्य। कार्य की समापन अवधि: 09 माह। निविदा जमा देने की प्रारंभिक तिथि: 28.05.2026, निविदा जमा देने की अंतिम तिथि: 11.06.2026 को 14.00 बजे तक। निविदा बोली के खोलने की तिथि: 11.06.2026 को 14.30 बजे। विवरण यहाँ से देखा जा सकता है: www.ireps.gov.in तकनीकी पात्रता मानदंड: निविदाकार ने निविदा आमंत्रण से पूर्व महीने के अंतिम दिन को समाप्त, पिछले 07 (सात) वर्षों के दौरान, निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी एक कार्य का सफलतापूर्वक पूरा या पर्याप्त रूप से निष्पादन किया है: (i) तीन समरूप कार्य जिनमें से प्रत्येक की लागत निविदा के विज्ञापित मूल्य के 30% की समान राशि से कम न हो, या (ii) दो समरूप कार्य जिनमें से प्रत्येक की लागत निविदा के विज्ञापित मूल्य के 40% की समान राशि से कम न हो, या (iii) एक समरूप कार्य जिसकी लागत निविदा के विज्ञापित मूल्य के 60% की समान राशि से कम न हो। वित्तीय पात्रता मानदंड: निविदाकार का न्यूनतम औसत वार्षिक ठेकाजनित कारोबार V/N या 'V' होना चाहिए, जो भी कम हो, जहाँ V = निविदा का विज्ञापित मूल्य करोड़ रुपये में, N = कार्य पूरा करने के लिए निर्धारित वर्षों की संख्या जिसके लिए बोलियाँ आमंत्रित की गई हैं। औसत वार्षिक ठेकाजनित कारोबार की गणना लेखापरीक्षित तुलन पत्र के अनुसार पिछले तीन वित्तीय वर्षों में "कुल ठेकाजनित भुगतान" के औसत के रूप में की जाएगी। तथापि, यदि पिछले वर्ष का तुलन-पत्र अभी तैयार किया जाना है/लेखापरीक्षित नहीं है, तो औसत वार्षिक ठेकाजनित कारोबार की गणना के लिए चौथे पिछले वर्ष के लेखापरीक्षित तुलन-पत्र को विचार में लिया जाएगा। निविदाकार जीसीसी 2022 के अनेक्सर-VIबी (मौजूदा निविदा कागजात का फॉर्म-6) के अनुसार आवश्यक जानकारी के साथ सनदी लेखापाल द्वारा यथा प्रमाणित लेखापरीक्षित तुलन पत्र की प्रतियाँ/लेखापरीक्षित तुलन पत्र द्वारा यथा समर्थित सनदी लेखापाल से प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे। जमा किए जाने वाले अन्य कागजात: निविदा कागजात में उल्लिखित अनुसार। समरूप कार्य की प्रकृति: सिग्नल या टेलीकम का कोई भी कार्य जिसमें सिग्नल या टेलीकम केबलों की खुदाई, बिछाना और परीक्षण या कोई अन्य विविध आउटडोर एस एंड टी कार्य शामिल हैं। टिप्पणी: निविदाकार अपने निविदा प्रस्ताव के साथ निविदा कागजात में उल्लिखित पात्रता मानदंड को पूरा करने के अपने दावे के समर्थन में कागजात प्रस्तुत करेंगे। निविदाकार द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रमाण पत्रों के समर्थन में कागजातों/प्रमाणपत्रों की प्रतिलिपि का प्रत्येक पृष्ठ निविदाकार या निविदाकारी फर्म के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्व-सत्यापित/डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित होगा। स्व-सत्यापन में हस्ताक्षर, मुहर और तिथि (प्रत्येक पृष्ठ पर) शामिल होंगे।
SDAH-41/2026-27
निविदा सूचना वेबसाइट www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in पर भी उपलब्ध है
हमें यहाँ देखें: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

संपादकीय

कामयाब होने के लिए स्वयं पर भरोसा होना चाहिए

कोलकाता | शुक्रवार | 15 मई, 2026

'पेपर लीक' का माफिया कौन?

एक बार फिर 'पेपरलीक' और करीब 23 लाख युवा बच्चों का भविष्य अधर में, अंधकारपूर्ण और अनिश्चित! 'नीट' का पेपर लीक हुआ है. अभ्यर्थी युवाओं में कई होनहार, विशेषज्ञ डॉक्टर बन सकते थे! जिंदगियां बचा सकते थे! घर-परिवार की आर्थिक स्थितियां बेहतर कर सकते थे! मां-बाप के कर्ज चुकता कर सकते थे! लेकिन एक माफिया, संगठित गिरोह, पैसे के हवसी, संवेदनहीन साजिशकार इस देश में सक्रिय हैं, जो युवा पीढ़ी को बार-बार निराश, हताश कर रहे हैं. उनकी उम्मीदें छीन रहे हैं. विडंबना यह है कि बीते सालों में 70 बार या अधिक पेपरलीक कराए गए हैं, कुछ 'काली भेड़ें' जेल में हो सकती हैं, लेकिन सरगना बेखौफ, बेलगाम षड्यंत्र रच रहे हैं. आज तक न तो सीबीआई और न ही सरकारों की अन्य एजेंसियां इस नापाक नेटवर्क के 'माफिया' को तय नहीं कर पाई हैं. बेशक सीबीआई देश की प्रमुख जांच एजेंसी है. कानून में सजा कितनी है-3, 4, 5 अथवा 10 साल तक. किसको सजा दी गई? किस पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना ठोंका गया? किस पर स्थायी पाबंदी लगाई गई? इन सवालों के जवाब तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री को देने चाहिए. हकीकत यह है कि यह शर्मनाक, देशद्रोही धंधा आज हजारों करोड़ रुपए का बताया जा रहा है. क्या इन साजिशकारों के घरों में युवा बच्चे नहीं हैं? वे भी डॉक्टर, इंजीनियर बनना चाहते होंगे! शायद उनके साथ ऐसे हादसे नहीं हुए या उनके बच्चे भी पेपरलीक के जरिए पास हो गए होंगे! पेपरलीक का धंधा तो शाश्वत लगता है हमें! भारत जैसे विराट, सम्मानित और विश्व-गुरु की खुशफहमी पाले देश के लिए ये करतूतें, हरकतें, युवा पीढ़ी के सपनों को चकनाचूर करने वाली 'माफियागीरी' शर्मनाक ही नहीं, बल्कि इसका दमन भी आतंकवाद, नक्सलवाद की तरह किया जाना चाहिए. दरअसल मौजूदा शिक्षा मंत्री नालायक हैं, शिक्षा मंत्रालय नकारा, भ्रष्ट है और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) बार-बार साबित हो रही है कि वह पारदर्शी, ईमानदार, लीक-मुक्त परीक्षाएं कराने के लायक ही नहीं है. प्रधानमंत्री मोदी बेहद जागरूक और पारदर्शी नेता हैं, ऐसे निकम्मेपन के खिलाफ माने जाते रहे हैं, लिहाजा मौजूदा व्यवस्था को पूरी तरह बदलें. अंततः युवा पीढ़ी और जनता को सड़कों पर बिछ कर जन-आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा. यह सिर्फ 23 लाख बच्चों के भविष्य का ही नहीं, बल्कि 23 लाख परिवारों के भविष्य पर आघात किया गया है. अधिकांश बच्चे गरीब या निम्न मध्यवर्गीय होते हैं. जिन बच्चों के लिए 10-28 लाख रुपए में लीक वाले प्रश्नपत्र खरीदे जाते हैं, उस जमात को छोड़ दीजिए. दरअसल ये ही पेपरलीक के धंधे के थोक-ग्राहक हैं, लिहाजा इस शर्मनाक धंधे के सह-भागीदार हैं. हमने चार दशक से अधिक की पत्रकारिता के दौरान पेपर और भ्रष्टाचार के मामले देखे हैं, कवर किए हैं. नकदी के बंडलों के लेन-देन देखे हैं. उनमें कुलपति, रजिस्ट्रार से लेकर प्रिंटिंग प्रेस तक की 'मिलीभगत' भी देखी है, लिहाजा पेपरलीक के दौर में प्रिंटिंग प्रेस और उसके दल्लों की धंधेबाजी और नतीजतन पेपरलीक कमोबेश हमें नहीं चौंकाता. अब इस नेटवर्क को तोड़ने और मसलने का वक्त आ गया है. अब प्रधानमंत्री मोदी और उनकी कैबिनेट के खास, समझदार मंत्रियों को विमर्श कर यह तय करना पड़ेगा कि परीक्षा का तरीका क्या होना चाहिए? ऑफलाइन परीक्षा क्यों जरूरी है? डिजिटल के दौर में कई परीक्षाएं ऑनलाइन आयोजित की जा रही हैं. अब 'नीट' का पेपरलीक हुआ है, तो 400-500 करोड़ रुपए पर पानी फिर गया. यह करदाता का पैसा था. बताया जा रहा है कि एक गैस पेपर बीते 15-30 दिनों से घूम रहा था. वह 150 पन्नों का था, जिसमें 410 प्रश्न संकलित किए गए थे. उनमें 120-140 सवाल हूबहू परीक्षा में पूछे गए. बॉयलोजी के तो 90 प्रश्न और रसायन विज्ञान के 45 प्रश्न परीक्षा में आ गए, मानो गैस पेपर की 'फोटोप्रति' की गई हो! सीबीआई जांच करेगी कि यह कैसे और क्यों हो सकता है? अनुमानित पेपर के नाम पर पुस्तिकाएं बाजार में बिकती रही हैं, लेकिन इतना मिलान, हूबहू होना सवालिया और संदेहजनक है. परीक्षा रद्द करना कोई समाधान नहीं है.

पेट्रोल संकट का दीर्घकालीन समाधान भारत के पास है

– कुलभूषण उपमन्यु

ईरान, इजराइल-अमेरिका युद्ध ने वैश्विक स्तर पर खनिज तेल आधारित ऊर्जा व्यवस्था को डांवाडोल कर दिया है. भारतवर्ष पर इसका खासा असर होना स्वाभाविक है क्योंकि हमारी 85 फीसद ऊर्जा जरूरतें आयात के माध्यम से ही पूरी होती हैं और इसका बड़ा भाग मध्य पूर्वी देशों से ही आता है. होर्मुज जलडमरूमध्य से समुद्री नौवहन में युद्ध के कारण आई रुकावट के चलते यह स्पष्ट हो चुका है कि इस तरह की स्थितियां देश की घरेलू, औद्योगिक, और सैनिक जरूरतों के लिए घातक साबित हो सकती हैं. अंतरराष्ट्रीय बाजार में युद्ध के चलते खनिज तेल की कीमतें दुगनी हो चुकी हैं. सरकार ने अभी तक तो घरेलू ऊर्जा जरूरतों पर बढ़ी हुई कीमतों का उतना असर नहीं होने दिया है किन्तु लंबे समय तक ऐसा कर पाना संभव नहीं होगा. इस समस्या के दीर्घकालीन समाधान को ध्यान में रख कर ही सरकार ने एथनोल को पेट्रोल में मिला कर पेट्रोलियम पदार्थों की मांग कम करने का प्रयास शुरू किया है. एथनोल के प्रयोग को लगातार बढ़ाते जाने की योजना पर काम हो रहा है, लेकिन इसकी भी सीमा है जिससे आगे एथनोल उत्पादन संभव नहीं होगा. हमारे पास और भी संसाधन हैं जिनके योजनाबद्ध उपयोग से हम उर्जा सुरक्षा और आत्मनिर्भरता में बड़ा योगदान कर सकते हैं. हमारे पास कृषि अपशिष्ट और गोबर का प्रचुर भंडार है, जिससे मीथेन, सीएनजी, पीएनजी बना कर खनिज तेल की आयात जरूरतों को कम किया जा सकता है. फिलहाल उपलब्ध गोबर का उपयोग करने पर क्या स्थितियां बनेंगी इस पर विचार करते हैं. देश में 2025 की पशु गणना के अनुसार 193.50 करोड़ गोवंश और 109.85 करोड़ भैंस हैं. कुल 303.35 करोड़ ऐसा पशु धन है जिनके गोबर से मीथेन गैस बनाई जा सकती है. एक किलो मीथेन गैस बनाने के लिए लगभग 30 किलो गोबर चाहिए, जो हमें दो पशुओं से दैनिक प्राप्त हो सकता है. इस तरह 150 करोड़ किलो गैस प्रतिदिन बनाई जा सकती है. साल में कुछ कमीबेशी को छोड़ दें तो 300 दिन का गिनते हैं. इससे 45000 करोड़ किलो गैस प्रतिवर्ष बनाई जा सकती है. इसको टन में बदल लें तो 45 करोड़ टन हुए. एक सिलिंडर में 15 किलो गैस के हिसाब से एक टन से 66 सिलिंडर भरे जा सकते हैं. 45 करोड़ टन से 2970 करोड़ सिलिंडर भरे जाएंगे. देश की आबादी को 140 करोड़ मानते हुए औसत पांच प्राणियों का परिवार मानते हुए 28 करोड़ परिवार हुए. यदि हर महीने प्रति परिवार एक सिलेंडर की खपत मान कर चलें तो 12 महीने में 336 करोड़ सिलेंडर की खपत होगी. जबकि हमारे पास संसाधन 2970 करोड़ सिलेंडर भरने की है. यानि इस क्षमता का 15-20 प्रतिशत दोहन भी कर लिया जाए तो घरेलू खपत को पूरा किया जा सकता है और इससे आगे व्यवसायिक खपत की भी गुंजाइश रह जाती है. हर घर में गोबर गैस प्लांट बनाना शायद संभव नहीं होगा किन्तु कुछ में तो संभव होगा. शेष संसाधन को वाणिज्यिक स्तर पर बड़े और आधुनिक तकनीक पर कार्य करने वाले गोबर गैस प्लांट बना कर ऊर्जा सुरक्षा की ओर आत्मनिर्भर कदम बढ़ाया जा सकता है, और आयात बिल और विदेशी मुद्रा को भी बचाया जा सकता है. जिस तरह एथनोल उत्पादन कार्य को गंभीरता से तेज गति से बढ़ाया गया है यदि उसी भावना से गोबर गैस उत्पादन को भी वाणिज्यिक स्तर पर प्रोत्साहन दे कर आगे बढ़ाया जाए तो बड़ी उपलब्धि हासिल की जा सकती है. इससे किसानों को भी गोबर उपलब्ध करवाने के बदले अतिरिक्त कमाई हो सकती है. इस प्रक्रिया में गैस तो निकल जाती है, शेष गोबर, डाइजेस्टर में अच्छी तरह सड़ कर बाहर आता है जो ज्यादा गुणवत्ता पूर्ण खाद होता है. इसके अलावा फसलों के अपशिष्ट, पराली या गेहूं के अपशिष्ट भी सीएनजी, पीएनजी बनाने के लिए उपयोग कर लिए जाएं तो काफी बड़ी मात्रा में प्राकृतिक गैस के आयात में कमी आ सकती है. फसल अपशिष्ट से सीएनजी बनाने के कुछ संयंत्र तो शुरू भी हो चुके हैं. इन सब कामों के लिए तकनीक तो हमारे पास उपलब्ध ही है केवल राजनीतिक इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प से आरंभ करने की बात है. फसल अपशिष्ट इस तरह इस्तेमाल कर लेने से उन्हें जलाने के कारण होने वाले प्रदूषण और उससे होने वाली बीमारियों और असमय मौतों से भी बचा जा सकता है. इस कार्य में भी कुछ कठिनाइयां तो आएंगी किन्तु अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक गुलामी से मुक्ति भी तो मिलेगी. *(लेखक, पर्यावरणविद और हिमालय नीति अभियान के अध्यक्ष हैं)*

दवा नहीं, जहर का कारोबार: भारत की साख पर संकट

– ललित गर्ग

पिछले दिनों सामने आई खबरों ने पूरे देश को चिंता और बेचैनी में डाल दिया कि जीवनरक्षक और सामान्य उपयोग की अनेक दवाइयां गुणवत्ता के मानकों पर खरी नहीं उतरीं. केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन द्वारा जारी ड्रग अलर्ट में जिन दवाओं के नमूने फेल पाए गए, उनमें हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, मिर्गी, संक्रमण, विटामिन सप्लीमेंट और कफ सिरप जैसी आम उपयोग की दवाएं भी शामिल थीं. यह कोई सामान्य प्रशासनिक त्रुटि नहीं, बल्कि मानव जीवन के साथ किया जा रहा ऐसा खतरनाक खिलवाड़ है, जिसने देश की स्वास्थ्य सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगा दिया है. जिस दवा को रोगी जीवन बचाने की आशा में खरीदता है, वही यदि उसके शरीर में जहर का काम करने लगे तो यह केवल चिकित्सा व्यवस्था की विफलता नहीं, बल्कि मानवीय संवेदनाओं के पतन की पराकाष्ठा है. विडंबना यह है कि दवाओं के निर्माण और वितरण के लिए देश में कठोर नियम, निरीक्षण और परीक्षण की व्यवस्थाएं मौजूद हैं. कच्चे माल की गुणवत्ता से लेकर उत्पादन प्रक्रिया तक कई स्तरों पर जांच होती है, फिर भी बड़ी-बड़ी नामी कंपनियों की दवाइयां यदि अमानक पाई जाती हैं तो यह साफ संकेत है कि कहीं-न-कहीं मुनाफे की अंधी दौड़ ने नैतिकता और मानवता को कुचल दिया है. यह केवल आर्थिक अपराध नहीं, बल्कि मानवता के विरुद्ध अपराध है. दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि जिन लोगों पर समाज की जिंदगी बचाने की जिम्मेदारी है, वही लोग अपने स्वार्थ के लिए लोगों की जिंदगी दांव पर लगा रहे हैं. भारत आज दुनिया की सबसे बड़ी दवा उत्पादन शक्तियों में शामिल है. भारतीय दवाइयां अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया और मध्य-पूर्व के अनेक देशों में निर्यात होती हैं. भारत को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है क्योंकि सस्ती और प्रभावी दवाओं की आपूर्ति में भारत की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है. कोरोना महामारी के दौरान भारत ने वैक्सीन और आवश्यक दवाइयों की आपूर्ति कर पूरी दुनिया में अपनी विश्वसनीयता और मानवीय प्रतिबद्धता का परिचय दिया था. जिन राज्यों में उत्पादित घटिया दवाओं का खुलासा हुआ, उनमें हिमाचल प्रदेश पहले पायदान पर रहा, फिर उत्तराखंड, गुजरात, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, पुडुचेरी, तेलंगाना, सिक्किम, झारखंड, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, आंध्रप्रदेश, ओडिशा आदि राज्य शामिल हैं. यानी एक-दो राज्य नहीं, तमाम राज्यों के दवा उत्पादक इस अपवित्र कर्म में शामिल हैं. यूं कहें कि दाल में काला नहीं है बल्कि पूरी दाल काली है. विडंबना देखिए कि कफ सिरप के 17 नमूने फेल हुए हैं. अब यह साफ हो गया कि अफ्रीका व सेंट्रल एशिया के कुछ देशों तथा भारत के कुछ राज्यों में कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत के जो आरोप भारतीय दवा कंपनियों पर लगे थे, वे गलत नहीं थे, जिससे पूरी दुनिया में भारतीय दवा उद्योग की छवि खराब हुई. अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारत की प्रतिष्ठा को धक्का लगता है और दुनिया भारतीय दवा उद्योग को संदेह की दृष्टि से देखने लगती है. यह स्थिति ऐसे समय में सामने आ रही है जब भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है. नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत 2047 तक स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे होने पर विकसित भारत का सपना साकार करने की दिशा में अनेक नए आयाम स्थापित कर रहा है. भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है. डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधारों के माध्यम से देश वैश्विक नेतृत्व की ओर बढ़ रहा है. भारत को विश्वगुरु बनाने का सपना केवल आर्थिक विकास से नहीं, बल्कि नैतिकता, गुणवत्ता और विश्वसनीयता से भी जुड़ा हुआ है. यदि जीवनरक्षक दवाओं में ही मिलावट और घटियापन सामने आएगा, तो यह सारे सकारात्मक प्रयासों पर धब्बा लगाने जैसा होगा. आज आवश्यकता इस बात की है कि सरकार दवा नियंत्रण व्यवस्था को और अधिक सशक्त बनाए. केवल औपचारिक निरीक्षण और समय-समय पर जारी होने वाले ड्रग अलर्ट पर्याप्त नहीं हैं. दवा निर्माण इकाइयों की नियमित और पारदर्शी जांच होनी चाहिए. जिन कंपनियों की दवाएं बार-बार मानकों पर फेल होती हैं, उनके लाइसेंस तुरंत रद्द किए जाएं और उनके खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई हो. दवा माफिया और नकली दवा बनाने वाले गिरोहों के खिलाफ विशेष अभियान चलाए जाने चाहिए. यह भी जरूरी है कि दोषियों को केवल आर्थिक जुर्माने तक सीमित न रखा जाए, बल्कि उन्हें कठोर कारावास की सजा दी जाए ताकि दूसरों के लिए भी कड़ा संदेश जाए. यह भी एक गंभीर चिंता का विषय है कि कई बार राज्य सरकारें और नियामक एजेंसियां प्रभावशाली दवा कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करने से बचती दिखाई देती हैं. धनबल और प्रभाव के कारण जांच प्रक्रियाएं धीमी पड़ जाती हैं और अंततः आम जनता ही इसकी कीमत चुकाती है. यह स्थिति लोकतांत्रिक शासन और प्रशासनिक जवाबदेही दोनों के लिए खतरनाक है. रोगी इस उम्मीद में दवा लेते हैं कि इससे उनकी बीमारी ठीक होगी. लेकिन यह पता लगे कि जिन दवाइयों का वे सेवन कर रहे हैं वे दवा नहीं बल्कि जहर के रूप में बाजार में आ गई हैं तो क्या बीतेगी? हिंदुस्तान में आज लाखों लोगों को ये दवाएं जीवन-रक्षा नहीं दे रही है बल्कि मार रही है, इंसान का लोभ एवं लालच इंसान को मार रहा है. ऐसे स्वार्थी लोगों एवं जीवन से खिलवाड़ करने वालों को राक्षस, असुर या दैत्य कहा गया है जो समाज एवं राष्ट्र में तरह-तरह से स्वास्थ्य सुरक्षा के नाम पर मौत बांट रहे हैं. अमानक एवं गुणवत्ता में दोषपूर्ण पाई गई इन दवाओं में कई नामी कंपनियों की दवाएं भी शामिल हैं. दवा उद्योग केवल व्यापार नहीं है, यह विश्वास का उद्योग है. यहां नैतिकता का महत्व सबसे अधिक होना चाहिए. लेकिन दुर्भाग्य से आज लालच और मुनाफाखोरी ने इस क्षेत्र में भी गहरी जड़ें जमा ली हैं. नकली इंजेक्शन, मिलावटी दवाएं, एक्सपायरी दवाओं की री-पैकेजिंग और घटिया कच्चे माल के उपयोग जैसी घटनाएं यह साबित करती हैं कि समाज में संवेदनाओं का स्रोत सूखता जा रहा है. इंसान केवल अपने लाभ के लिए दूसरों की जिंदगी से खेलने को तैयार हो गया है. यह केवल कानून का विषय नहीं, बल्कि सामाजिक और नैतिक पतन का भी संकेत है. आवश्यकता इस बात की भी है कि आम जनता को दवाओं के प्रति जागरूक बनाया जाए. दवा खरीदते समय बिल लेना, पैकेजिंग और निर्माण तिथि की जांच करना, संदिग्ध दवाओं की शिकायत संबंधित विभागों को करना और बिना चिकित्सकीय सलाह के दवाओं का सेवन न करना, ये सब छोटे लेकिन महत्वपूर्ण कदम हैं. मेडिकल स्टोरों की भी नियमित निगरानी होनी चाहिए ताकि नकली या घटिया दवाओं की बिक्री रोकी जा सके. दवाओं की गुणवत्ता से खिलवाड़ दवा निर्माता कम्पनियों का एक घिनौना, क्रूर एवं अमानवीय चेहरा ही है जो मनुष्य के स्वास्थ्य को चैपट कर रहे हैं. एक तो बीमारियों का कोई कारगर इलाज नहीं है, दूसरा इन बीमारी में काम आने वाली तमाम जरूरी दवाइयां लालची लोगों ने अमानक एवं दोषपूर्ण कर दी हैं. बढ़ती बीमारियां इन राक्षसों के कारण ही बेकाबू हो रही है. सरकारें इन त्रासद स्थितियों एवं बीमारी पर नियंत्रण पाने में नाकाम साबित हुई है. देश के लाखों लोग कातर निगाहों से शासन-प्रशासन की ओर देख रहे हैं कि कोई तो राह निकले. भारत आज एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है. एक ओर देश नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है, दूसरी ओर ऐसी त्रासद एवं विडम्बनापूर्ण घटनाएं हमारी नैतिक और प्रशासनिक कमजोरी को उजागर कर रही हैं. यदि हम सचमुच विकसित और विश्वसनीय भारत बनाना चाहते हैं, तो हमें केवल आर्थिक विकास नहीं, बल्कि गुणवत्ता, ईमानदारी और मानवीय मूल्यों को भी सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी. जीवनरक्षक दवाओं में मिलावट केवल स्वास्थ्य का संकट नहीं, बल्कि राष्ट्र की आत्मा पर लगा कलंक है. यह समय आत्ममंथन का है. सरकार, दवा उद्योग, चिकित्सा जगत और समाज-सभी को मिलकर यह सुनिश्चित करना होगा कि दवा जीवन बचाने का माध्यम बने, मौत का व्यापार नहीं. तभी विकसित भारत का सपना वास्तविक अर्थों में सार्थक हो सकेगा.

(लेखक, पत्रकार, स्तंभकार)

आपका जन्मदिन मंगलमय हो — 15 मई

आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएँ. आपका जन्मतिथि 15 मई है. अंक ज्योतिष के अनुसार आपकी जन्मतिथि का स्वामी ग्रह शुक्र है. इस माह का अधिपति ग्रह शुक्र है. आप आजीवन शुक्र ग्रह से प्रभावी रहेंगे. आकस्मिकता आपके जीवन की प्रधान विशेषता होगी. लेकिन आपका जीवन शान्ति और धैर्य का सूचक होगा. आप सदैव कुछ न कुछ सोचते होंगे. त्वरित निर्णय व दूरदर्शिता आपकी प्रगति में सहायक होगा. मार्ग निर्देशन के क्षेत्र में आप अग्रणी रहेंगे. आप किसी की चापलूसी या झूठी प्रशंसा करना पसन्द नहीं करेंगे. शृंगार एवं सौन्दर्य प्रसाधन वस्तुओं के क्रय में आप कुछ ज्यादा ही व्यय करेंगे. आप सदैव उत्तरदायित्व के बोझ से दबे रहेंगे. आप स्पष्टवादी प्रवृत्ति के होंगे. लेकिन स्पष्टवादिता कभी घातक भी सिद्ध होगी. गृहस्थ जीवन सामान्य रहेगा. निर्देशन के क्षेत्र में आप सर्वोपरि रहेंगे. आपकी स्मरण शक्ति श्रेष्ठ होगी. आप जो भी निर्णय लेंगे वह स्वतंत्र रूप से होगा. जीवन में शुभ-लाभ के लिए अपने आराध्य देव की पूजा एवं अर्चना बराबर करें. अपने दैनिक जीवन में आसमानी रंग का प्रयोग न करें. सफेद रंग की वस्तुओं का प्रयोग अधिकतम करें. मान-मर्यादा का ख्याल रखें. याचक को निराश न करें. मुफ्त में किसी वस्तु की चाह न करें. परोपकारी बनें. सुख-सौभाग्य के लिए रत्न या उपरत्न तथा यन्त्र विधि-विधानपूर्वक धारण करें.

आपके लिए अनुकूल :-

मन्त्र	:	ॐ शुं शुक्राय नमः	मास	:	फरवरी, अप्रैल एवं नवम्बर
व्रत	:	शुक्रवार	वर्ष	:	6, 15, 24, 33, 42, 51, 60, 69
दिन	:	सोमवार, मंगलवार एवं शुक्रवार	रंग	:	हल्का नीला एवं सफेद
दिनांक	:	6, 15, 24	जन्मरत्न	:	हीरा
उपरत्न	:	सफेद पुखराज	अंक	:	4, 5, 8
जड़ी	:	अरण्ड की जड़	दिशा	:	आग्नेय

यंत्र

11	6	13
12	10	8
7	14	9

वर्ष का महत्वपूर्ण समय – 20 अप्रैल से 21 मई, 23 सित. से 20 अक्टू.

हस्तरेखा विशेषज्ञ, रत्न-परामर्शदाता, फलित व अंक ज्योतिषी एवं वास्तुविद

विमल जैन एस. 2/1-76 ए, द्वितीय तल, वरदान भवन, पंचक्रोशी मार्ग, भोजूबीर, वाराणसी-221002 मो0 : 09335414722

आपका आज का दिन 2026

मेष : व्यावसायिक सफलता, प्रियजनों-मित्रों से विचार-विमर्श, व्यक्तिगत जीवन में महत्वपूर्ण उपलब्धि, रचनात्मक कृत्यों से यश की प्राप्ति, शुभ कार्यों में अधिक व्यय.

वृषभ : समस्याओं से उलझनें, कार्य-व्यवसाय में निराशा, लेन-देन में जोखिम से नुकसान, दूसरों की भूलों से स्वयं को हानि, परिवार में आपसी गलतफहमी.

मिथुन : ग्रहस्थिति अनुकूल, व्यापारिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त, स्वाध्याय की ओर रुचि, पारिवारिक सुख-शांति, राजनैतिक क्रियाकलापों की ओर रुचि, लाभ भी.

कर्क : बहुप्रतीक्षित कार्य बनने की ओर, पुरातन विवाद का समापन, मित्रों-परिजनों से विचार-विनिमय, धार्मिक मांगलिक कृत्य सम्पन्न, मनो-विनोद के सुअवसर प्राप्त.

सिंह : विचारित योजना फलीभूत, धन संचय की ओर प्रवृत्ति, इच्छाशक्ति जागृत, आनन्द की अनुभूति, दर्शनीय स्थलों की यात्रा का प्रसंग, संत समागम, यश में वृद्धि.

कन्या : आरोग्य सुख में व्यवधान, आर्थिक पक्ष से असंतोष, पारिवारिक कष्ट, कार्यों के प्रति उदासीनता, खर्च की अधिकता, विवाद की आशंका, भय भी.

तुला : नव प्रयास सार्थक, आमोद-प्रमोद के साधन सुलभ, बकाए धन की वसूली, मित्रों-परिजनों से सहयोग, कुछेक मसला हल, अध्यात्म के प्रति आस्था.

वृश्चिक : कार्य-व्यवसाय में वृद्धि, जीवन में महत्वपूर्ण उपलब्धि, रचनात्मक क्रियाकलापों में रुचि, शत्रु हानि पहुँचाने में विफल, धार्मिक कृत्यों में रुझान, मानसिक शांति.

धनु : आर्थिक पक्ष से संतोष, इच्छित योजना का सुपरिणाम प्राप्त, भोग विलासिता की ओर रुझान, धार्मिक गतिविधियों की ओर अभिरुचि, जीवन साथी से सामंजस्य.

मकर : किसी योजना के लिए चिन्तित, घरेलू समस्याओं से परेशान, वाद-विवाद की आशंका, वाहन से चोट-चपेट, दुर्घटना संभव, धन का अभाव, यात्रा में असुविधा.

कुम्भ: कठिनाइयों का निराकरण, परोपकार की भावना जागृत, भौतिक सुख-सुविधा में वृद्धि, किसी के माध्यम से महत्वपूर्ण उपलब्धि, विरोधी पराभूत, प्रसन्नता.

मीन: ग्रहयोग बेहतर, दूसरों के आश्वासनों से कुछेक कार्यों में सफलता, व्यापारिक वातावरण मनोनुकूल, कठिनाइयों में कमी का एहसास, विवादास्पद मसला हल.

- ज्योतिषाचार्य विमल जैन, वाराणसी, मो. नं. 09335414722

मानव धर्म-शास्त्र

लेखक : लक्ष्मी नारायण मीणा

मानव धर्मशास्त्र के प्रणेता
अवधूत देवी दास जी महाराज

अष्टम स्कन्ध

जन्मत सुत रां उचारी। पीड़ा प्रसव विगत महतारी।।
चहुँदिसि भयउ प्रकृति उछाहु। मंगल सुगन अनुकूल सबाहु।।

व्याख्या - जन्म लेते ही पुत्र ने रां नाम का उच्चारण किया, जिससे माता की प्रसव पीड़ा तुरन्त दूर हो गई। चारों तरफ प्रकृति में उत्साह छा गया तथा समस्त मंगलकारी सगुन होने लग गए।

समाचार सुनि ऋषि सब आए। देखि मुख छवि आशीष बरसाए।।
बालक इहँ होइब ब्रम्ह ग्यानी। सकल ऋषि मुनि कहा बखानी।।

व्याख्या - समाचार सुनकर सब ऋषि आए और बालक की छवि देखकर आर्शीवाद देने लगे। सब ऋषि - मुनियों ने कहा कि यह बालक ब्रम्हज्ञानी होगा।

सत्ता का नया महासमर और सामाजिक न्याय की शुचिता

–अशोक प्रवृद्ध

भारत का सामाजिक ढांचा मात्र एक श्रेणीबद्ध व्यवस्था नहीं, बल्कि अधिकार और अवसर के संघर्ष की एक दीर्घकालीन गाथा है. आज जब हम पिछड़ी जातियों की महत्ता पर विचार करते हैं, तो यह केवल वोट बैंक की अंकगणितीय गणना नहीं, बल्कि भारतीय लोकतंत्र की वह धुरी है, जिसके इर्द-गिर्द सत्ता का चक्रव्यूह घूमता है. वहीं, इन जातियों की ऐतिहासिक जड़ें भारत के शिल्प, कृषि और सृजन की उस शाश्वत मेधा में निहित हैं, जिसने राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को सदियों तक अक्षुण्ण रखा. भारत का पिछड़ा वर्ग वस्तुतः राष्ट्र का विश्वकर्मा रहा है. प्राचीन संहिताओं में जिन समुदायों को उत्पादक श्रेणियों के रूप में प्रतिष्ठित किया गया, वे ही राष्ट्र की आर्थिक रीढ़ थे. धातु विज्ञान, वस्त्र शिल्प और कृषि अधिष्ठान में इनका योगदान अप्रतिहत था. ऐतिहासिक कालखंड के प्रवाह में, विशेषकर मध्यकाल और औपनिवेशिक शासन के दौरान, इन उत्पादक वर्गों को सामाजिक सोपान में हाशिए पर धकेल दिया गया. जिस मेधा को पुरस्कृत होना चाहिए था, उसे पिछड़ापन का ठप्पा दे दिया गया. यह केवल सामाजिक पतन नहीं, बल्कि भारत की मौलिक प्रतिभा का संस्थागत दमन था. मंडल आयोग के उपरांत भारतीय राजनीति का जो दोहरा चेहरा सामने आया, उसने पिछड़ी जातियों को सत्ता की चाबी तो बना दिया, पर क्या उन्हें ताला खोलने का अधिकार मिला? लोहिया से लेकर आधुनिक क्षत्रपों तक, पिछड़ी जातियों ने दिल्ली के कुलीन दरबार को चुनौती दी है. आज कोई भी दल इन जातियों की उपेक्षा कर सत्ता की कल्पना नहीं कर सकता. पिछड़ी जातियों के नाम पर राजनीति करने वाले नेताओं ने क्या वास्तव में जातियों का उत्थान किया, या केवल अपने कुनबे को मलाई खिलाई? सत्ता के गलियारों में पिछड़ों की हिस्सेदारी बढ़ी है, किन्तु उसका लाभ अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचने के बजाय क्रीमी लेयर के अवरोध में फंस गया है. आर्थिक दृष्टि से यह वर्ग आज भी एक संक्रमण काल से गुजर रहा है. ग्लोबलाइजेशन (वैश्वीकरण) ने उन पारंपरिक शिल्पों और लघु उद्योगों को ध्वस्त कर दिया, जो पिछड़ी जातियों की आर्थिक शक्ति थे. आर्थिक न्याय का अर्थ केवल आरक्षण नहीं, बल्कि कौशल पुनर्जागरण होना चाहिए. जब तक पिछड़ी जातियों को आधुनिक तकनीक और पूंजी तक सुलभ पहुंच नहीं मिलेगी, तब तक वे केवल श्रमिक बने रहेंगे, स्वामी नहीं. भविष्य की राह जातीय चेतना और आधुनिक मेधा के समन्वय में है. भावी उम्मीदें उस युवा नेतृत्व से हैं, जो पहचान की राजनीति से ऊपर उठकर विकास की राजनीति की बात करे. पिछड़ी जातियों को अपनी पहचान के लिए केवल संवैधानिक सुरक्षा पर निर्भर रहने के बजाय अपनी ऐतिहासिक श्रेष्ठता को पुनः खोजना होगा. उल्लेखनीय है कि भारत में पिछड़ी जातियों का प्रश्न केवल सीटों के बंटवारे का नहीं, बल्कि मानवीय गरिमा की पुनर्स्थापना का है. सत्ता के समीकरण बदलते रहेंगे, पर शाश्वत सत्य यह है कि जब तक समाज का यह विराट उत्पादक वर्ग हीनता की भावना से मुक्त नहीं होगा, तब तक राष्ट्र का परम वैभव एक कोरी कल्पना ही रहेगा. भविष्य का भारत वही होगा, जहां जन्म नहीं, बल्कि कर्म और सामर्थ्य व्यक्ति की नियति तय करेंगे. पिछड़ी जातियों की भावी उम्मीदें इसी समतामूलक चेतना के जागरण में निहित हैं. वर्तमान भारतीय राजनीति जिस मोड़ पर खड़ी है, वहां जातीय जनगणना मात्र एक सांख्यिकीय आंकड़ा नहीं, बल्कि सत्ता की चाबी हासिल करने का एक रणकौशल बन गई है. यह मांग दरअसल दिल्ली के उस कुलीन तंत्र को हिला देने की कवायद है, जिसने दशकों से नीति निर्धारण पर एकाधिकार जमा रखा है. वहीं राष्ट्र की सांस्कृतिक चेतना हमें सचेत करती है कि संख्या बल का यह शोर कहीं भारत की एकात्मता के उस मूल मंत्र को विखंडित न कर दे, जो जातियों को वर्गों में नहीं, बल्कि अंग-प्रत्यंग के रूप में जोड़ता था. जनगणना की मांग करने वाले दलों का उद्देश्य अंतिम व्यक्ति का कल्याण कम और मंडल 2.0 के जरिए अपनी खोई हुई राजनैतिक जमीन वापस पाना अधिक है. यदि जनगणना से यह सिद्ध होता है कि पिछड़ों की आबादी 50% से अधिक है, तो जितनी आबादी, उतना हक का नारा सत्ता के वर्तमान समीकरणों को छिन्न-भिन्न कर देगा. यह उन दलों के लिए जीवन-मरण का प्रश्न है जिनकी राजनीति केवल जातीय ध्रुवीकरण पर टिकी है. दूसरी ओर, सत्ता पक्ष इसे हिंदू एकता के लिए खतरा मानता है. राजनीति का यह वह मोड़ है, जहां धर्म की काट जाति से और जाति की काट धर्म से करने की बिसात बिछ चुकी है. गहरा प्रश्न है कि क्या केवल संख्या जान लेने से न्याय हो जाएगा? शास्त्र कहते हैं कि न्याय केवल वितरण नहीं, बल्कि पात्रता का सम्मान है. यदि जनगणना केवल नए विशेषाधिकार प्राप्त समूहों को जन्म देती है, तो यह सामाजिक समरसता के शाश्वत सत्य की बलि चढ़ा देगी. जनगणना के आंकड़ों में उन जातियों की पीड़ा कहीं लुप्त न हो जाए, जो राजनीतिक रूप से मुखर नहीं हैं. वास्तविक न्याय वह है जो अतिपिछड़े को मुख्यधारा में लाए, न कि केवल जातीय क्षत्रपों की तिजोरियां भरे. जातीय जनगणना के उपरांत भारतीय लोकतंत्र एक नये युग में प्रवेश करेगा. संसाधनों का बंटवारा अब अंदाज से नहीं, बल्कि तथ्य से होगा. यह शिक्षा, नौकरियों और बजट के आवंटन की पूरी प्रक्रिया को बदल कर रख देगा. यह आरक्षण की 50% वाली लक्ष्मण रेखा के पुनर्निर्धारण का मार्ग प्रशस्त करेगा, जिससे कानूनी और सामाजिक संघर्ष की नई स्थितियां उत्पन्न होंगी. सच यही है कि जातीय जनगणना को केवल राजनैतिक लाभ-हानि के तराजू पर तौलना एक ऐतिहासिक भूल होगी. यह एक ऐसा दर्पण है, जिसमें भारत को अपनी वास्तविक सामाजिक छवि देखनी है. यदि जनगणना का उद्देश्य 'सर्वे भवन्तु सुखिनः' की भावना से ओत-प्रोत है, तो यह राष्ट्र के लिए अमृत सिद्ध होगी. यदि इसे समाज को टुकड़ों में बांटने का हथियार बनाया गया, तो यह शांति और प्रगति के भविष्य को भस्म कर देगा. उम्मीद केवल उस मौलिक चिंतन से है, जहां जाति एक गर्व का विषय तो हो, पर प्रगति में बाधा न बने. शाश्वत सत्य तो यह है कि न्याय और विवेक का संगम ही किसी भी राष्ट्र की अक्षुण्णता का आधार है. जनगणना केवल सिरों की गिनती न रहे, बल्कि वह दबे हुए कंठों की गूंज और उपेक्षित प्रतिभाओं के सम्मान का अनुष्ठान बने. तभी भारत अपनी ऐतिहासिक मेधा और आधुनिक आकांक्षाओं के बीच समरसता का सेतु बना पाएगा. आज भारत का आरक्षण विमर्श एक ऐसे दोराहे पर खड़ा है, जहां सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय की धाराएं आपस में टकरा रही हैं. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का उदय भारतीय राजनीति की वह मास्टरस्ट्रोक चाल थी, जिसने दशकों से चले आ रहे जातीय आरक्षण के एकाधिकार को मनोवैज्ञानिक चुनौती दे दी. न्याय जब खंडों में विभाजित होता है, तो वह लोक कल्याण के बजाय लोक विग्रह (सामाजिक संघर्ष) का कारण बन जाता है. जातीय आरक्षण का आधार ऐतिहासिक अपमान की भरपाई था, जबकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का आधार वर्तमान अभाव की चिंता है. वोट की मंडी में अब केवल जाति नहीं बिकती, अब निर्धनता का कार्ड भी बराबरी से खेला जा रहा है. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ने सवर्ण जातियों के भीतर व्याप्त उस आक्रोश को शांत करने का प्रयास किया है, जो स्वयं को व्यवस्था में उपेक्षित महसूस कर रहे थे. यह समता और समानता के मध्य का सूक्ष्म संघर्ष है. जहां जातीय आरक्षण समान अवसर की बात करता है, वहीं आर्थिक आधार पर आरक्षण आर्थिक शुचिता की आकांक्षा रखता है. आरक्षण चाहे जातीय हो या आर्थिक, यदि वह पात्र के बजाय प्रभावशाली के पास पहुंचता है, तो वह अधर्म है. जब पिछड़ी जातियों का एक संपन्न वर्ग (क्रीमी लेयर) आरक्षण का लाभ छोड़ने को तैयार नहीं, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में भी फर्जी आय प्रमाणपत्रों की बाढ़ है, तो न्याय कहां है? समस्या आरक्षण की पद्धति में कम और अवसरों की कमी में अधिक है. जब तक अर्थव्यवस्था पर्याप्त रोजगार सृजन नहीं करती, तब तक आरक्षण केवल अभाव का बंवारा बनकर रह जाएगा. इस द्वंद्व का समाधान किसी एक पक्ष की जीत में नहीं, बल्कि समग्र समावेश में है. भविष्य की राजनीति को अब जाति और वर्ग के झगड़े से ऊपर उठकर मेधा और मानवीय गरिमा के समन्वय पर ध्यान देना होगा. अंतिम सत्य यही है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः का लक्ष्य तभी प्राप्त होगा, जब आरक्षण एक बैसाखी न रहकर सीढ़ी बने, जिससे चढ़कर समाज का अंतिम व्यक्ति राष्ट्र की मुख्यधारा में विलीन हो सके. *(लेखक, आध्यात्मिक चिंतक व साहित्यकार)*

न्यूज कॉर्नर

6 मई को स्वर्ण जयंती वर्ष पर भव्य सम्मेलन : देशभर के डॉक्टर होंगे शामिल

धनबाद : धनबाद सोसाइटी ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी इस वर्ष अपना स्वर्ण जयंती वर्ष मना रही है. इस ऐतिहासिक और गौरवशाली अवसर को यादगार बनाने के लिए 16 और 17 मई, 2026 को धनबाद के ग्रैंड मिराज (रेडिसन इंडिविजुअल्स) में दो दिवसीय वार्षिक सम्मेलन उद्घजक्रउजछका आयोजन किया जा रहा है.इस वर्ष सम्मेलन की थीम स्वस्थ नारी और सशक्त समाज रखी गई है.इस सम्मेलन का विस्तृत कार्यक्रम 16 मई (प्रथम दिन): कार्यक्रम की शुरुआत मातृ मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से आयोजित झझक (प्रसवोत्तर रक्तस्राव) वर्कशॉप से होगी. इस दिन FOGSI की उपाध्यक्ष डॉ. आभा रानी सिन्हा 'प्री-एक्लेमप्सिया की स्क्रीनिंग' विषय पर अपना महत्वपूर्ण शोध प्रस्तुत करेंगी. इसके अलावा वैज्ञानिक सत्रों में 'बांझपन प्रबंधन' और 'गर्भधारण-पूर्व देखभाल' जैसे विषयों पर चर्चा होगी.17 मई (द्वितीय दिन): दूसरे दिन की शुरुआत 'गर्भसंस्कार' कार्यक्रम से होगी. दोपहर के सत्र में दो प्रमुख व्याख्यान होंगे: डॉ. सी.सी. हजरा ओरेशन में DSOGCONकी नवनिर्वाचित अध्यक्ष डॉ. माधुरी पटेल 'गर्भावस्था में मधुमेह' पर और डॉ. लीना प्रिया ओरेशन में FOGSI अध्यक्ष डॉ. भास्कर पाल 'एंडोमेट्रियोसिस' विषय पर जानकारी साझा करेंगे. साथ ही कैंसर स्क्रीनिंग और सीजेरियन ऑपरेशन की उन्नत तकनीकों पर भी सत्र होंगे. सम्मेलन का भव्य औपचारिक उद्घाटन समारोह आयोजित किया जाएगा.विशेषज्ञों की भागीदारी: FOGSI वर्कशॉप का संचालन डॉ. शीला माने, डॉ. मित्रा सक्सेना, डॉ. मंजू पुरी, डॉ. पूनम गोयल, डॉ. निवेदिता दत्ता और डॉ. राजलक्ष्मी टुबिड की टीम द्वारा किया जाएगा. इनके साथ ही डॉ. आभा रानी सिन्हा डॉ. एम.सी. पटेल, डॉ. संपत कुमारी और एडिटर-इन-चीफ डॉ. सुजाता दलवी विभिन्न वैज्ञानिक विषयों पर अपनी प्रस्तुति देंगे.इस मौके पर डॉ. कोमल सिंह और डॉ. रीना बरनवाल के साथ डॉ. एस.के. दास,डॉ चौधरी डॉ. प्रतिभा राय, डॉ. राजलक्ष्मी टुबिड, डॉ. कविता प्रिया, डॉ. शिवानी झा, डॉ. साधना, कोषाध्यक्ष डॉ. नूपुर चंदन, डॉ. नेहा प्रियदर्शिनी और डॉ. नीतू सहाय उपस्थित थे

घाटी में असंतुलित होकर टेंपो पलटने से पति-पत्नी की दर्दनाक मौत एक की स्थिति गभीर

लिट्टीपाड़ा: जिले के लिट्टीपाड़ा थाना क्षेत्र के कुंजबोन मुख्य सड़क लब्दाघाटी में बुधवार देर रात टेम्पो पलटने से पति पत्नी की मौत हो गया जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया. जानकारी कर अनुसार टेम्पो संख्या जेएच 04 टी 5357 मोहनपुर साप्ताहिक हटिया से यात्री लेकर घाटी के रास्ते लिट्टीपाड़ा की ओर आ रहा था कि लब्दाघाटी पहाड़ी ढलान में टेम्पो असंतुलित होकर सड़क पर पलट गया जिससे टेम्पो में सवार थाना क्षेत्र के पाकुड़ थाना क्षेत्र के मालिपाड़ा गांव निवासी चारलेस मरांडी 55 वर्ष साबित हांसदा, 45 गंभीर रूप से घायल हो गया. घटना की सूचना ग्रामीणों द्वारा पुलिस को दिया गया. सूचना मिलते ही एसआई अनिल पंडित दल बल के साथ मौके पर पहुंच दोनों घायलों को एम्बुलेंस के द्वारा पाकुड़ सदर हॉस्पिटल भेज दिया गया. जहा डॉक्टरों के द्वारा दो मृत घोषित कर दिया. प्रभारी थाना प्रभारी अनिल पंडित ने बताया सड़क दुर्घटना में दो लोगो की मौत हुआ है. दोनों शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. दुर्घटनाग्रस्त टेम्पो को जप्त कर थाना लाया गया है. चालक फरार है. मामले की जांच किया जा रहा है.

रिफत प्रवीण ने रखी श्मशान घाट में प्यूरीफायर वाटर कूलर मशीन लगाने की मांग

साहिबगंज : गुरूवार को नगर परिषद के बोर्ड की बैठक कीअध्यक्षता नगर पार्षद अध्यक्ष ने की.बोर्ड की बैठ में वार्ड नंबर नौ की वार्ड पार्षद रिफत प्रवीण ने श्मशान घाट में शुद्ध व शीतल पानी मशीन (प्यूरीफायर वाटर कूलर मशीन) लगाने की मांग रखी. रिफत ने बोर्ड की मीटिंग में अपने लेटर पैड के माध्यम से कहा कि हिन्दु धर्म के अनुसार शहर के मुनीलाल श्मसान घाट एक महत्वपूर्ण स्थल है. श्मसान घाट पर शव की अंत्योष्टि करने जाने वाले लोगों को वहां पर पानी खरीदकर पीना पड़ता है. वहां शुद्ध व शीतल पेयजल की व्यवस्था नहीं है. अनुरोध है कि श्मसान घाट पर एक शुद्ध व शीतल पेयजल के लिए एक प्यूरीफायर वाटर कूलर मशीन लगाया जाए. इससे हमारे वार्ड क्षेत्र के अलावा पूरे शहर के लोगों को राहत मिलेगी और जेब पर अत्यंत खर्च का भार नहीं पड़ेगा. इसके अलावा वार्ड क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट, वेपर लाइट लगाने, नाली का निर्माण कराने, वार्ड क्षेत्र में पूर्व में लगाए गए चापाकल बंद पड़ा हुआ है. इन चापाकल की बोरिंग बढ़ाकर दोबारा चालू कराने, जल समस्या को दूर करने के लिए छह जगहों पर जल मीनार का निर्माण कराने की मांग की है.वार्ड पार्षद द्वारा उठाए गए इन जनसुविधाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर बैठक में चर्चा हुई और लोगों को बेहतर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया.मौके पर मौजूद नगर प्रशासक अभिषेक कुमार सिंह,उपाध्यक्ष,एव सभी वार्ड के पार्षद मौजूद थे.

बाइक सवार से दो बदमाशो ने दुकान में की मारपीट थाना को दी सूचना

साहिबगंज : मुफस्सिल थाना क्षेत्र के एन एच 80 स्थित मां समुंद्रा पेट्रोल पंप के नजदीक मोटर पार्ट्स की दुकान में बाइक सवार दो अज्ञात युवक द्वारा बुधवार की रात मारपीट कर रुपए छीन लेने का मामला प्रकाश में आया है. पीड़ित दुकानदार मो इब्बो ने बताया कि कुछ जरूरी काम से वह अपने पुत्र अमन को दुकान में रखकर गया हुआ था कि इसी बीच रात करीब नौ बजे मोटरसाइकिल से दो युवक आकर उनके पुत्र को बैल्ट से मौका से मारपीट किया एवं उसके पुत्र के पॉकेट से दस हजार तीन सौ रुपए भी छीन कर जान मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गया.घटना की लिखित सूचना मुफस्सिल थाना को पीड़ित ने दी है.मामले में पुलिस छानबीन कर रही है.

दिव्यांग बोर्ड शिविर में 70 दिव्यांगों की हुई जांच

साहिबगंज : जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा सदर अस्पताल स्थित ओपीडी में गुरुवार को दिव्यांग जांच शिविर का लगाया गया है. दिव्यांगों के रजिस्ट्रेशन के लिए अलग अलग काउंटर लगाया गया था. इधर शिविर में सीएस डॉ. रामदेव पासवान शामिल हुए. उन्होंने शिविर का जायजा लेते हुए दिव्यांगों सुविधाओ के बारे में जानकारी लिया गया. इसमे हड्डी, आंख, मानसिक समेत 70 दिव्यांगों की जांच की गई है. मौके पर मौजूद हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉ. सचिन कुमार, ईएनटी डॉ. सत्य प्रकाश आदि थे.

सीबीएसई 12वीं के रिजल्ट में जिला टॉपर बना संत पॉल पब्लिक स्कूल तेघड़ा

तेघड़ा/बेगूसराय (युवा शक्ति ब्यूरो) :बेगूसराय जिले में शिक्षा के क्षेत्र में एक बार फिर संत पॉल पब्लिक स्कूल, तेघड़ा ने अपनी उत्कृष्टता का परचम लहराया है.

सीबीएसई बारहवीं बोर्ड परीक्षा 2026 के परिणामों में विद्यालय ने लगातार कई वर्षों की तरह इस वर्ष भी जिले में सर्वोच्च प्रदर्शन करते हुये अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की. विद्यालय के छात्र रमण कुमार ने 96 प्रतिशत अंक प्राप्त कर जिला टॉपर बनने का गौरव हासिल किया. इस वर्ष विद्यालय के कुल 115 विद्यार्थियों ने परीक्षा में भाग लिया, जिनमें सभी विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुये. वहीं 17 विद्यार्थियों ने 90 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त कर विद्यालय का नाम रोशन किया. साइंस एवं कॉमर्स दोनों संकायों में विद्यार्थियों ने शानदार प्रदर्शन किया. प्रमुख सफल विद्यार्थियों में साहिल कुमार चौधरी (94.5%), अभिजीत अमन (94%), आलोक नाथ (93%), हर्ष कश्यप (93%), शिवम (90%) तथा देव ऋषि (90%)

शामिल है. विद्यालय के निदेशक सुनील कुमार सिंह ने इस उपलब्धि का श्रेय प्राचार्या के कुशल नेतृत्व, शिक्षकों की निष्ठा, विद्यार्थियों की मेहनत एवं अभिभावकों के सतत सहयोग को दिया. वहीं संत पॉल एजुकेशनल सोसाइटी के सचिव रामबली सिंह ने कहा कि यह सफलता विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. विद्यालय की प्रेसिडेंट लक्ष्मी कुमारी ने विद्यार्थियों के अनुशासन, आत्मविश्वास एवं समर्पण की सराहना करते हुये कहा कि देश का भविष्य ऐसे होनहार विद्यार्थियों के हाथों में सुरक्षित है. प्राचार्या तनु सौरभ ने सभी विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं अभिभावकों को बधाई देते हुये कहा कि यह परिणाम सामूहिक मेहनत और समर्पण का प्रतिफल है. इस अवसर पर राम कुमार मिश्र, सुरेंद्र कुमार सिंह, एम. रामचंद्रन, अविनाश कुमार मिश्रा, दीपक कुमार, मो. खालिद , संजीव कुमार सिंह, राकेश कुमार, कंचन कुमारी, प्रेम माधुरी, शिवशंकर मिश्रा, संजीत कुमार, रामपुनित राय सहित विद्यालय परिवार एवं अनेक अभिभावक उपस्थित थे. स्थानीय बुद्धिजीवियों ने विद्यार्थियों की सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुये कहा कि मेहनत, अनुशासन और समर्पण से कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता.

यह उपलब्धि आने वाली पीढ़ियों के लिये प्रेरणा का स्रोत बनेगी.

लखिणरायनपुर में सियार का आतंक

पाकुड़: मुफ्फसिल थाना क्षेत्र के लखिणरायनपुर गांव में सियार के हमले से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है. सियार के हमले में एक बच्ची की मौत हो गई, जबकि चार अन्य लोग घायल होने के समाचार हैं. घटना के बाद वन विभाग द्वारा सियार को पकड़ने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं.डीएफओ सौरभ चंद्रा ने बताया कि संभवतः सियारों के झुंड का एक सदस्य रेबीज से संक्रमित है और वही लोगों पर हमला कर रहा है. ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए विशेष क्रिक रिस्पांस प्रोटोकॉल टीम का गठन किया गया है, जिसने प्रभावित गांवों का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया जा सके. उन्होंने बताया कि मृतक के परिजनों को तत्काल 50 हजार रुपये तथा दो घायलों को पांच-पांच हजार रुपये की सहायता राशि दी गई है. प्रावधान के अनुसार मृतक के परिजनों को 4 लाख रुपये, गंभीर घायल को 1 लाख रुपये एवं सामान्य घायलों को 15 हजार रुपये मुआवजा दिया जाएगा.

जदयू विधायक प्रमोद कुमार सिंह ने राजद सांसद और पुलिस कार्रवाई पर भी उठाया है गंभीर सवाल

औरंगाबाद (बिहार) : रफीगंज विधानसभा क्षेत्र संख्या - 224 के एन.डी.ए. गठबंधन समर्थित जदयू विधायक सह समाजसेवी, प्रमोद कुमार सिंह ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से एक ब्यान जारी करते हुए कहा है, कि मंगलवार की रात औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र के इंडिया गठबंधन समर्थित राष्ट्रीय जनता दल सांसद, अभय कुशवाहा की गाड़ी पर हमला किए जाने का मामला सामने आया है. इस हमले ने कई सवाल छोड़ दिए है. प्रथम दृष्टया पुलिस की कार्रवाई भी कई सवाल खड़ा करती है, क्योंकि पुलिस ने यह कार्रवाई सांसद के दबाव में किया. जिससे न सिर्फ औरंगाबाद की पुलिस की साख गिरी है, और सरकार की बदनामी हुई है. जिस मामले में थाने से ही अभियुक्त बनाए लोगों को छोड़ दिया जा सकता था! उस मामले में सांसद ने अपने पद का दुरुपयोग करके पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी पर दबाव बनाया! दोनों अधिकारी सांसद के दबाव में आकर सरकार की पारदर्शी सोच को कटघरे में खड़ा कर दिया है, और आने वाले समय में इस मामले में अधिकारियों की कार्यशैली क्या थी? इसे मुख्यमंत्री एवं उप - मुख्यमंत्री के पास भी रखा जाएगा. यहां

पुलिस भी इस बात को मानती है, कि गाड़ी को आगे - पीछे करने के कारण घटना घटी है. सोचने वाली बात यह है कि जिस व्यक्ति को अभियुक्त बनाया गया है! वह किस वर्ग का था. यह वही वर्ग है, जिसकी विसात पर सांसद ने चुनाव जीता. आखिर वह क्यों सांसद के खिलाफ हुआ. ऐसा इसलिए कि सांसद की कार्यशैली से उनके ही कोर वोटर में नाराजगी बढ़ गई है, और वे इनसे खफा चल रहे है. यही कारण है कि सांसद अब दूसरा ठिकाना तलाश करने की कोशिश में लगे हुए है. दूसरी बात सांसद का यह ब्यान भी बेहद ही हास्यास्पद है, कि यह उनके हत्या कराने की साजिश हो सकती है. इस मामले में जिला प्रशासन से एक सवाल है, कि जब सांसद क्षेत्र में नहीं हैं? तो सांसद का बोर्ड लगाकर कोई अन्य व्यक्ति खुलेआम क्षेत्र में कैसे घूम सकता है? यह संविधान में वर्णित अनुच्छेद - 18 का उल्लंघन है! पदाधिकारियों ने कार्रवाई करने से पहले इस बिंदु को कैसे इग्नोर कर दिया. तब तो कोई भी व्यक्ति जब - तक पकड़ा नहीं जाता है! तब - तक सांसद, विधायक, जिला - प्रशासन, डी.एम., एस.पी. या अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के पद का बोर्ड लगाकर क्षेत्र में घूम सकता है, और किसी भी अपराधिक घटना को अंजाम दे सकता है. निश्चित रूप में सांसद के मेल - मिलाप में आकर अधिकारियों ने बड़ी गलती की है! जिसे बर्दास्त नहीं किया जा सकता है. शीघ्र ही इस मामले को सदन में भी रखा जाएगा.

एसएसबी ने वांछित नक्सली को किया गिरफ्तार

युवा शक्ति न्यूज

गया : गुरुवार को विश्वनीय सूत्रों से प्राप्त आसूचना के आधार पर एसएसबी 29वीं बटालियन गया के कमांडेंट कुणाल के दिशानिर्देशन में बटालियन के सी समवाय डुमरिया के निरीक्षक (सामान्य) मंतोष कुमार के नेतृत्व में एसएसबी एवं जिला पुलिस थाना बोधिबिगहा के साथ संयुक्त अभियान चलाया गया.अभियान के दौरान एक वांछित नक्सली विमल जी उर्फ विमल यादव, उर्फ गणेश यादव, पिता- स्व. मुसाफिर यादव, ग्राम- जमुनिया, थाना- आंजन (मदनपुर), जिला- औरंगाबाद को उसके गांव- जमुनिया क्षेत्र से देर रात गिरफ्तार किया गया.उपरोक्त गिरफ्तार वांछित नक्सली द्वारा 02 दिसंबर 2007 को ग्राम- हुरमेठ निवासी विनोद यादव के परिवार के साथ मारपीट की गई थी तथा लेवी की मांग की गई थी.उक्त घटना में लगभग 40-50 उग्रवादियों के साथ मिलकर विनोद यादव एवं सरेखा यादव के खलिहान से लगभग 500 मन धान ट्रैक्टर पर लादकर ले जाया गया था.इसके अतिरिक्त शेष लगभग 1000 बोझा धान में आग लगा दिया था एवं घटना स्थल पर ग्रामीणों में भय एवं आतंक उत्पन्न करने के उद्देश्य से तीन राउंड फायरिंग भी की गई थी.साथ ही उक्त नक्सली, नक्सली संदीप यादव के साथ सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ था.उक्त नक्सली गया जिले के थाना डुमरिया एवं बोधिबिगहा कांड संख्या- 45/07 दिनांक 02.12.2007, जो विभिन्न धाराओं के तहत वांछित था.गिरफ्तार किये गए नक्सली को थाना- डुमरिया, जिला-गया को विधिक कार्रवाई हेतु सौंप दिया गया.

बोधगया में दुकानों पर गिरी पेड़ की बड़ी टहनी

युवा शक्ति न्यूज

गया : जिले के बोधगया में बुधवार की रात महाबोधि मंदिर जाने वाले मुख्य मार्ग पर जयप्रकाश उद्यान स्थित एक विशाल बरगद के पेड़ की भारी भरकम टहनी टूटकर दुकानों पर गिर गई.उस समय न आंधी थी और न बारिश हो रही थी.फिर भी अचानक से आवाज के साथ टहनी कुछ ही सेकंड में गिर पड़ी.हादसा इतना अचानक हुआ कि वहां मौजूद दुकानदारों और पर्यटकों को संभलने तक का मौका नहीं मिला.गनीमत रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई.लेकिन कुछ सेकेंड की देरी बड़ी अनहोनी में बदल सकती थी.देर शाम के वक्त महाबोधि मंदिर में दर्शन के बाद लौटते वक्त आसपास की दुकानों में खरीदारी के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचे थे. दुकानदार अपनी दुकान छोड़कर मौके से जान बचाने के लिए भागे.पर्यटकों के बीच भी अफरा-तफरी का माहौल हो गया.टहनी गिरने से कई दुकानों के ऊपर रखे सामान बर्बाद हो गए.दुकान संचालकों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा.साथ ही बिजली के तार भी टूट गए.

व्यक्तिगत सुविधा से पहले राष्ट्रहित हम सबका कर्तव्य : कुलपति

युवा शक्ति न्यूज

टिकारी(गया) : एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में यह हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी व्यक्तिगत सुविधा से पहले राष्ट्र के हित के बारे में सोचें.ईंधन की खपत कम करने एवं विदेशी मुद्रा बचत के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए सात सूत्रीय आह्वान का हमें पूरी तरह समर्थन करना चाहिए.उक्त वक्तव्य दक्षिण बिहार केन्द्रीय विश्वविद्यालय (सीयूएसबी) के कुलपति कामेश्वर नाथ सिंह ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सात सूत्रीय आह्वान पर आयोजित विशेष पैनल चर्चा के दौरान कहीं. सीयूएसबी के प्रशासनिक भवन के सम्मेलन कक्ष में आयोजित इस परिचर्चा का आयोजन संयुक्त रूप से वाणिज्य एवं व्यवसाय अध्ययन विभाग तथा अर्थशास्त्र एवं नीति अध्ययन विभाग द्वारा किया गया था.कुलपति प्रो. सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में राष्ट्र विकसित भारत 2047 की दिशा में आगे बढ़ रहा है तथा इज़राइल-ईरान युद्ध के कारण उत्पन्न हुए वैश्विक आर्थिक समस्या का

सामना बुद्धिमानी से किए जाने की आवश्यकता है.उन्होंने सम्मेलन कक्ष में उपस्थित पैनल विशेषज्ञों, प्रतिभागियों तथा विश्वविद्यालय परिवार से प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए सुझावों का पालन करने और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया.इस पैनल चर्चा में प्रो. ब्रजेश कुमार, विभागाध्यक्ष एवं अधिष्ठाता, वाणिज्य एवं व्यवसाय अध्ययन विभाग; प्रो. कृष्णन चालिल, विभागाध्यक्ष अर्थशास्त्र एवं नीति अध्ययन विभाग; प्रो. प्रवीण कुमार, विभागाध्यक्ष राजनीतिक अध्ययन विभाग; प्रो. अवनीश प्रकाश सिंह, विभागाध्यक्ष कृषि विभाग; डॉ. मंगलेश कुमार मंगलम, अधिष्ठाता, मानव विज्ञान संकाय; डॉ. हरेश नारायण पांडेय, डॉ. हेमंत कुमार सिंह, डॉ. राजनारायणन एस, डॉ. प्रणव त्रिपाठी, डॉ. पावस कुमार; डॉ. प्रदीप राम, श्रीमती रेनु तथा डॉ. लुन शामिल थे.परिचर्चा में सात सूत्रीय आह्वान पर विस्तार से चर्चा की गई तथा पैनल विशेषज्ञों द्वारा कई विशिष्ट सुझाव दिए गए.इनमें व्यापक स्तर पर जैविक खेती को अपनाना, ड्रिप सिंचाई प्रणाली का उपयोग, विश्वविद्यालय की मौखिक परीक्षाओं (वाइवा-वोसे) का ऑनलाइन आयोजन, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना तथा राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी एवं जवाबदेही की भावना को प्रोत्साहित करना शामिल था.चर्चा के मुख्य निष्कर्षों को पैनल एवं विश्वविद्यालय द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री के आह्वान को अपनाने का निर्णय लिया गया. साथ ही परिसर से समुदाय तक सूक्ष्म एवं व्यापक स्तर पर लागू किए जाने हेतु कई नीतिगत सुझाव भी प्रस्तुत किए गए.चर्चा के मुख्य बिंदुओं में व्यक्तिगत सुविधा से ऊपर कर्तव्य को रखना, हरित कृषि एवं हरित ऊर्जा को बढ़ावा देना, उत्सवों में स्वर्ण उपभोग को कम करना

प्रखंड में चलाया गया वहां जांच अभियान, वसूला गया फाइन

पाकुड़: जिले के लिट्टीपाड़ा प्रखंड में जिला परिवहन पदाधिकारी मिथिलेश कुमार चौधरी एवं थाना प्रभारी लिट्टीपाड़ा के नेतृत्व में स्पेशल एंटी क्राइम वाहन जांच अभियान आम्रपारा -लिट्टीपारा मुख्य मार्ग पर वाहन जांच अभियान चलाया, वाहन जांच अभियान चलाने का मुख्य उद्देश्य थाना लेटी पद अंतर्गत घटित हो रही प्रतिदिन थोड़ा दुर्घटनाओं में इजाफा है, थाना अंतर्गत घटित हो रही है सभी सड़क दुर्घटनाओं का होने का मुख्य कारण तेज गति से वाहन चलाना, वाहनों में बैठ क्षमता से अतिरिक्त सवारी की ढुलाई, तथा मोटरवाहन अधिनियम के विभिन्न धाराओं का उल्लंघन है, जिला मे दुर्घटनाओं में कमी लाने तथा लोगों को नियमों का पालन करने को जागरूक करने, तथा नियमों को अनदेखा करने तथा सरकार द्वारा निर्धारित दंड की राशि वसूल करने के प्रावधान को बढ़ावा देना है, जांच के क्रम में लगभग 30 से 35 दो पहिया वाहन, 2 टैम्पो, 1 बस, 01 ट्रैक्टर की जांच की गई, जिसमें बिना हेलमेट, बिना ड्राइविंग लाइसेंस, बिना नंबर प्लेट, बस में बैठ क्षमता से अतिरिक्त छत पर सवारी बैठाने, टेंपो पर अतिरिक्त छत पर सवारी बैठाने को लेकर कुल 38,850/- रुपए का दंड की राशि वसूल की गई, साथी पकड़े गए सभी वाहन चालकों को हिदायत दिया गया कि, सड़क पर चलने के क्रम में सरकार द्वारा निर्धारित सभी नियमों का पालन करें, अन्यथा पकड़े जाने पर जुर्माना की राशि नियमों का अनुपालन न करने तथा तथा बार-बार नियमों का तोड़ने को लेकर दोगुना के दर से दंड की राशि वसूल की जाएगी

डीएम ने तीनों महत्वपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता के तौर पर करवाने के दिए सख्त निर्देश

युवा शक्ति न्यूज

गया : जिले के डीएम शशांक शुभंकर की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में जिला के सभी प्रखंडों के वरीय प्रभारी पदाधिकारी गणों, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी अंचलाधिकारी के साथ जिला में चल रहे जनगणना 2027, फार्मर रजिस्ट्रेशन एवं सहयोग शिविर से संबंधित चल रहे कार्यों की समीक्षा की गई.डीएम ने सभी प्रखंडों के वरीय प्रभारी पदाधिकारी अपने-अपने निर्धारित प्रखंडों में इन तीनों कार्यों का लगातार अनुश्रवण एवं निरीक्षण करने का निर्देश दिये हैं.डीएम ने सभी बीडीओ एवं संबंधित पदाधिकारी गणों को इन तीनों महत्वपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता के तौर पर करवाने का सख्त निर्देश दिया है.राज्य सरकार के निर्देश के आलोक में आम नागरिकों को अपनी समस्याएँ, शिकायतें एवं सुझाव सीधे प्रशासन के समक्ष रखने तथा उनके त्वरित एवं प्रभावी समाधान के उद्देश्य से जिले में सहयोग शिविर का आयोजन किया जा रहा है.जन शिकायतों के निष्पादन को और अधिक सुलभ एवं प्रभावी बनाने के लिए वर्तमान व्यवस्थाओं के अतिरिक्त अब प्रत्येक माह के प्रथम एवं तृतीय मंगलवार को पंचायत स्तर पर सहयोग शिविर आयोजित किए जाएंगे.यह पहल सात निश्चय-3 के अंतर्गत सबका सम्मान, जीवन आसान के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए की जा रही है, ताकि आम लोगों की समस्याओं का समाधान संवेदनशीलता एवं त्वरित कार्रवाई के साथ किया जा सके.पूरे राज्य में प्रथम सहयोग शिविर 19 मई 2026 को लगाया जा रहा है. **जिले के सभी प्रखंडों में चयनित 28 पंचायतों में सहयोग शिविर का आयोजन किया जाएगा.**सभी 28 पंचायतों के लिए वरीय पदाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है.शिविर आयोजन की मुख्य विशेषताएँ है कि प्रत्येक पंचायत में निर्धारित रोस्टर के अनुसार शिविर का आयोजन किया जाएगा.शिविर का आयोजन पंचायत सरकार भवन अथवा निकट के सार्वजनिक स्थल पर किया जाएगा.संबंधित पदाधिकारी शिविर स्थल पर उपस्थित रहकर आम लोगों से सीधे संवाद करेंगे.प्राप्त शिकायतों का मौके पर ही निपटारा अथवा त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.आमजनों के बैठने हेतु पर्याप्त कुर्सी/टेबल की व्यवस्था पेयजल एवं

पब्लिक एड्रेस सिस्टम की उपलब्धता शिविर के सुचारू संचालन हेतु सभी आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था की जाएगी.शिविर आयोजन से पूर्व 30 दिनों से आवेदन प्राप्त करने की व्यवस्था की गई है.पंचायत, थाना, प्रखंड, अंचल एवं अनुमंडल स्तर के सभी पदाधिकारी आवेदन संग्रहण सुनिश्चित करेंगे.प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी शिविर के सफल आयोजन के लिए उत्तरदायी होंगे.डीएम ने निर्देश दिया है कि इस योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार समाचार पत्रों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं सोशल मीडिया के माध्यम से किया जाए, ताकि अधिक से अधिक लोग इस पहल का लाभ उठा सकें.जिला प्रशासन सभी नागरिकों से अपील करता है कि वे सहयोग शिविर में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकर अपनी समस्याओं एवं शिकायतों को सीधे प्रशासन के समक्ष रखें तथा इस जन-हितैषी पहल का लाभ उठाएं.**02 से 31 मई 2026 तक संचालित मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई.**जनगणना के कार्यो की समीक्षा में प्रखंडवार मकान सूचीकरण कार्य की समीक्षा की गई तथा प्रखंडों के वरीय पदाधिकारी की देखरेख में जनगणना कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए.बैठक के दौरान जनगणना 2027 के प्रथम चरण के अंतर्गत 02 मई 2026 से 31 मई 2026 तक संचालित मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई.

डीएम ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समयसीमा के भीतर कार्यों को गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण कराने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए.डीएम ने सभी चार्ज जनगणना अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे अपने-अपने क्षेत्र में नियुक्त प्रगणकों की हाउस लिस्टिंग ब्लॉक में नियमित उपस्थिति सुनिश्चित कराएं तथा प्रतिदिन मकान सूचीकरण का कार्य संपादित कराएं. साथ ही संबंधित पर्यवेक्षकों को कार्यों का सतत अनुश्रवण करने का निर्देश दिया गया.बैठक में यह भी निर्देश दिया गया कि सभी एचएलबी क्षेत्रों में जनगणना कार्य शीघ्र प्रारंभ कराया जाए तथा किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए.सभी प्रखंडों के वरीय पदाधिकारियों को अपने आवंटित क्षेत्रों एवं नगर निकायों का नियमित क्षेत्र भ्रमण कर जनगणना कार्यों की निगरानी करने एवं चार्ज जनगणना अधिकारियों के कार्यों की समीक्षा सुनिश्चित करने को कहा गया.डीएम शशांक शुभंकर ने कहा कि जनगणना कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण एवं राष्ट्रीय दायित्व से जुड़ा कार्य है, इसलिए सभी पदाधिकारी इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए समयबद्ध एवं प्रभावी तरीके से निष्पादित करें.**अभियान चलाकर किसानों का फार्मर रजिस्ट्री आईडी बनाया जा रहा-- डीएम.**फार्मर रजिस्ट्री की समीक्षा में डीएम ने बताया गया कि जिले में 12 मई 2026 से 30 जून 2026 तक विशेष अभियान चलाकर किसानों का फार्मर रजिस्ट्री आईडी बनाया जा रहा है. इसके लिए सभी पंचायतों में कैंप आयोजित करवाने का निर्देश दिए हैं, ताकि अधिक से अधिक किसानों को योजना का लाभ मिल सके.डीएम ने सभी सीओ को निर्देश दिया कि फार्मर रजिस्ट्री आईडी के लिए परिमार्जन के लिए प्राप्त आवेदनों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करें, ताकि किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो और अधिकाधिक किसानों का पंजीकरण समय पर किया जा सके.उन्होंने राजस्व विभाग एवं कृषि विभाग के सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों को आपसी समन्वय स्थापित कर अभियान को सफल बनाने का निर्देश दिया.साथ ही किसानों को जागरूक करते हुए पंचायत स्तर पर आयोजित कैंपों में अधिक से अधिक किसानों की भागीदारी सुनिश्चित करने को कहा.

न्यूज़ कॉर्नर

सिंधू और लक्ष्य सेन थाईलैंड ओपन के क्वार्टर फाइनल में, श्रीकांत बाहर

बैंकॉक: भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पी वी सिंधू और लक्ष्य सेन बृहस्पतिवार को यहां सीधे गेम में जीत के साथ पांच लाख डॉलर इनामी राशि के थाईलैंड ओपन सुपर 500 टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए. दो बार की ओलंपिक पदक विजेता और छठी वरीयता प्राप्त सिंधू ने महिला एकल के दूसरे दौर में 28 मिनट के भीतर डेनमार्क की अमेली शूल्ज को 21.13, 21.15 से हराया. सातवीं वरीयता प्राप्त सेन ने चीन के झू शुआन चेन को 21.12, 21.13 से मात दी. सिंधू का सामना अब शीर्ष वरीयता प्राप्त तीसरी रैंकिंग वाली जापान की अकाने यामागुची से होगा. वहीं सेन दूसरी वरीयता प्राप्त थाईलैंड के कुंलावुत वितिदसर्न के बीच होने वाले मैच के विजेता से खेलेंगे. पुरूष युगल में सात्विक साइराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की अंतिम आठ में पहुंच गए. उन्होंने मलेशिया के ब्रायन जेरेमी और मुहम्मद हाइकल को 21.12, 21.19 से मात दी. अब उनका सामना छठी वरीयता प्राप्त जापान के ताकुमी नोमूरा और युइची शिमोगामी से होगा. हालांकि दुनिया के पूर्व नंबर एक खिलाड़ी किदांबी श्रीकांत चीनी ताइपे के दुनिया के 47वें नंबर के खिलाड़ी सू ली यांग के खिलाफ कड़े मुकाबले में एक घंटा 10 मिनट में 16.21, 21.11, 18.21 की हार के साथ प्रतियोगिता से बाहर हो गए. इस साल थाईलैंड मास्टर्स सुपर 300 खिताब जीतने वाली देविका सिहाग को थाईलैंड की पिचामोन ओपासिनिपुत ने 23.21, 21.11 से मात दी.

एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में कांस्य पदकों से चमके अजीत

गांधीनगर: अजीत नारायण ने बृहस्पतिवार को यहां पुरुषों के 71 किग्रा वर्ग में क्लीन एवं जर्क और समग्र दोनों में कांस्य पदक जीते जिससे भारत ने एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन जारी रखा. एशिया के बेहतरीन भारोत्तोलकों के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करते हुए अजीत ने संयम दिखाते हुए क्लीन एवं जर्क में 174 किग्रा और कुल 314 किग्रा का वजन उठाया जिससे भारत को पोडियम में स्थान मिला. इस वर्ग का स्वर्ण पदक कोरिया के वोन जू रि (351 किग्रा) को मिला जबकि चीन के जियान चेन ने 335 किग्रा के वजन से रजत पदक हासिल किया. इस तरह अजीत चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले तीसरे भारतीय हैं. कोमल कोहर ने सोमवार को महिला 48 किग्रा में कांस्य पदक जीतकर भारत का खाता खोला था जिसके बाद झानेश्वरी यादव ने बुधवार को 53 किग्रा वर्ग में एक रजत और एक कांस्य पदक अपने नाम किया.

स्विंग गेंदबाजी की लय फिर हासिल करने के लिये अपने ही पुरानी वीडियो देख रही हूं : रेणुका

मुंबई: भारत की अनुभवी तेज गेंदबाज रेणुका सिंह ठाकुर ने बृहस्पतिवार को कहा कि वह पिछले महीने दक्षिण अफ्रीका के कठिन दौरे के बाद स्विंग गेंदबाजी की लय फिर हासिल करने के लिये अपने ही पुराने वीडियो देख रही हैं. दुनिया की तीसरे नंबर की भारतीय टीम को दक्षिण अफ्रीका ने पांच मैचों की टी20 श्रृंखला में 4.1 से हराया. रेणुका ने 12 जून से शुरू हो रहे टी20 विश्व कप से पहले पीटीआई को दिये इंटरव्यू में कहा, ''मैं रोज अभ्यास करती हूं लेकिन हर बार गेंद को स्विंग नहीं मिलता. दक्षिण अफ्रीका में गेंदबाजी को लेकर काफी संघर्ष करती रही. लेकिन अब मेरे पास अपनी स्विंग वापिस पाने के लिये 10-15 दिन का समय है.'' टूर्नामेंट का प्रसारण और लाइवस्ट्रीम जियो हॉटस्टार और स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जायेगा. रेणुका ने कहा, ''जब आप अच्छा प्रदर्शन नहीं करते तो कुछ भी आपके लिये काम नहीं करता. मैं कुछ समय से गेंद स्विंग नहीं करा पा रही थी और उसे वापिस पाने की कोशिश थी. मैं अपने पुराने वीडियो देख रही हूं कि मैं क्या करती थी और उम्मीद है कि लय वापिस पा लूंगी.'' भारतीय टीम 10 से 16 मई तक बेंगलुरू में उत्कृष्टता केंद्र में अभ्यास शिविर में थी और जल्दी ही द्विपक्षीय श्रृंखला और टी20 विश्व कप के लिये इंग्लैंड जायेगी. भारतीय टीम टी20 विश्व कप से पहले इंग्लैंड के खिलाफ तीन मैचों की टी20 श्रृंखला खेलेगी. इसके अलावा लॉर्ड्स पर एक टेस्ट भी खेला जायेगा.

सीएसके ने चोटिल जेमी ओवरटन की जगह डियान फोरेस्टर को चुना

चेन्नई: चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) ने बृहस्पतिवार को इंग्लैंड के जेमी ओवरटन की जगह दक्षिण अफ्रीकी आल राउंडर डियान फोरेस्टर को टीम में शामिल किया. ओवरटन दाहिनी जांघ में चोट के कारण इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के बाकी मैच से बाहर हो गए हैं. आईपीएल ने बृहस्पतिवार को एक बयान में कहा कि फोरेस्टर 75 लाख रुपये में सीएसके से जुड़ेंगे. फोरेस्टर ने इस साल मार्च में न्यूजीलैंड के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका में पदार्पण किया था और पांच अंतरराष्ट्रीय मैचों में 83 रन बनाए हैं. बुधवार को सीएसके ने घोषणा की थी कि ओवरटन अपनी चोट की गंभीरता का पता लगाने के लिए ब्रिटेन लौटेंगे. ओवरटन ने पांच बार की विजेता टीम के लिए आईपीएल अभियान में अहम भूमिका निभाई है, उन्होंने 10 मैचों में 14 विकेट लिए हैं और 136 रन बनाए हैं. सीएसके ने महाराष्ट्र के चोटिल ऑलराउंडर रामकृष्ण घोष की जगह कर्नाटक के ऑलराउंडर मैकनील नोरोन्हा को भी टीम में लिया था. चेन्नई की यह फ्रेंचाइजी अपने पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के बिना खेल रही है जबकि शीर्ष क्रम के बल्लेबाज आयुष म्हात्रे और तेज गेंदबाज खलील अहमद भी सत्र के बीच में चोटों के कारण बाहर हो गए.

लखनऊ के खिलाफ जीत दर्ज करके प्लेआफ की उम्मीदें कायम रखना चाहेगी चेन्नई

लखनऊ: लचर प्रदर्शन के बावजूद प्लेआफ की दौड़ में कायम चेन्नई सुपर किंग्स शुक्रवार को आईपीएल के मैच में लखनऊ सुपर जाइंट्स के खिलाफ शानदार जीत दर्ज करके अपना दावा बनाये रखना चाहेगी जबकि दौड़ से बाहर हो चुकी लखनऊ के लिये यह महज प्रतिष्ठा का मुकाबला है. चेन्नई ने टूर्नामेंट के दूसरे चरण में समय पर जीत दर्ज करके अपनी उम्मीदें कायम रखी है जबकि लखनऊ की टीम का प्रदर्शन बेहद ही खराब रहा. चेन्नई को अपने बाकी सारे मैच जीतने के अलावा दूसरे मैचों के नतीजे भी अनुकूल रहने की दुआ करनी होगी. चेन्नई फिलहाल 11 मैचों में से छह जीतकर पांचवें स्थान पर है. अच्छी 'फिनिशिंग' नहीं होने के कारण आलोचना झेलने वाली पांच बार की चैम्पियन चेन्नई टीम ने संजू सैमसन, उर्विल पटेल, कप्तान रूतुराज गायकवाड़ और कुछ उदीयमान खिलाड़ियों के दम पर अच्छी वापसी की. शीर्षक्रम पर उर्विल के बेखौफ प्रदर्शन से पावरप्ले में चेन्नई का प्रदर्शन बेहतर हुआ है. शुक्रवार को शिवम दुबे, कार्तिक शर्मा और डेवाल्ड ब्रेविस को भी बीच के ओवरों में अच्छा प्रदर्शन करना होगा. जांघ की चोट के कारण हरफनमौला जैमी ओवर्टन के बाहर होने से चेन्नई की गेंदबाजी कमजोर हुई है. ओवर्टन ने दस मैचों में 14 विकेट लिये और वह इस सत्र में चेन्नई की गेंदबाजी की धुरी थे. अकील हुसैन, मुकेश चौधरी और अंशुल कम्बोज ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है जबकि अफगानिस्तान के बायें हाथ के स्पिनर नूर अहमद प्रभावी रहे हैं. दूसरी ओर लखनऊ को कप्तान ऋषभ पंत के लगातार खराब फॉर्म का खामियाजा भुगतना पड़ा. उसके गेंदबाज विरोधी टीमों पर दबाव बनाने में नाकाम रहे और चेन्नई के खिलाफ पहले चरण के मैच में तो वे 203 रन बनाकर भी हार गए. जोश इंगलिस, निकोलस पूरन और मिचेल मार्श ने टुकड़ों में अच्छा प्रदर्शन किया है लेकिन एक ईकाई के रूप में टीम नाकाम रही है. **टीमें :**

मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा.

(चेन्नई सुपर किंग्स) : रुतुराज गायकवाड (कप्तान), एमएस धोनी (विकेटकीपर), संजू सैमसन (विकेटकीपर), कार्तिक शर्मा (विकेटकीपर), डेवाल्ड ब्रेविस, सरफराज खान, उर्विल पटेल (विकेटकीपर), अमन खान, शिवम दुबे, जैक फॉल्क्स, रामकृष्ण घोष, अंशुल कंबोज, जेमी ओवरटन, मैथ्यू शॉर्ट, प्रशांत वीर, राहुल चाहर, श्रेयस गोपाल, गुरजापनीत सिंह, मैट हेनरी, अकील हुसैन, स्पेंसर जॉनसन, मुकेश चौधरी, नूर अहमद. **(लखनऊ सुपर जाइंट्स) :** ऋषभ पंत (कप्तान और विकेटकीपर), अब्दुल समद, अक्षत रघुवंशी, आयुष बडोनी, मुकुल चौधरी, हिम्मत सिंह, जोश इंग्लिस (विकेटकीपर), एडेन मार्क्रम, निकोलस पूरन (विकेटकीपर), अर्शिन कुलकर्णी, जॉर्ज लिंडे, मिचेल मार्श, शाहबाज अहमद, आकाश सिंह, अवेश खान, मोहम्मद शमी, मोहसिन खान, एनरिक नॉर्किया, प्रिंस यादव, दिग्वेश राठी, मणिमारन सिद्धार्थ, अर्जुन तेंदुलकर, नमन तिवारी, मयंक यादव.

श्रीजेश की जगह सोयेज जूनियर पुरूष हॉकी टीम के कोच बने

नयी दिल्ली: फ्रांस के फ्रेडरिक सोयेज को बृहस्पतिवार को भारतीय जूनियर पुरूष हॉकी टीम का नया कोच बनाया गया जो दो बार के ओलंपिक पदक विजेता पी आर श्रीजेश की जगह लेंगे. पूर्व स्टार गोलकीपर श्रीजेश का अनुबंध पिछले साल चेन्नई और मदुरै में एफआईएच जूनियर विश्व कप में कांस्य पदक जीतने के बाद खत्म हो गया था. हॉकी इंडिया ने उनके अनुबंध का नवीनीकरण नहीं किया. सोशल मीडिया पर एक तल्ख पोस्ट में श्रीजेश ने अपनी निराशा व्यक्त करते हुए बुधवार को कहा कि उनके कार्यकाल के दौरान पाँच टूर्नामेंटों में पाँच पदक जीतने के बावजूद उनका अनुबंध नहीं बढाया गया लेकिन हॉकी इंडिया ने तर्क दिया कि यह फैसला 2036 ओलंपिक की मेजबानी की भारत की महत्वाकांक्षाओं के अनुरूप एक टिकाऊ और उच्च स्तरीय प्रदर्शन वाला इकोसिस्टम बनाने के दीर्घकालिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए लिया गया था. यूरोपीय हॉकी के बेहतरीन कोचों में से एक सोयेज के पास शीर्ष स्तर पर 15 साल का कोचिंग का अनुभव है . वह 1995 से 2010 तक फ्रांस के लिये 196 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले और 195 गोल किये. इसके बाद फ्रांस और स्पेन के कोच रहे. उनके कोच रहते स्पेन रियो ओलंपिक में पांचवें स्थान पर रहा. वह तोक्यो ओलंपिक में भी स्पेन के कोच रहे जबकि पेरिस ओलंपिक 2024 में फ्रांस के मुख्य कोच थे. स्पेन के कोच रहते उन्होंने टीम को 2019 यूरोपीय चैम्पियनशिप में रजत पदक दिलाया. सोयेज के कोच रहते फ्रांस की अंडर 18 टीम 2025 यूरोपीय चैम्पियनशिप में रजत पदक जीती थी. वह 2021 से 2024 तक फ्रेंच हॉकी महासंघ के हाई परफॉर्मेंस निदेशक रहे. उन्होंने तीन ओलंपिक (2016, 2020, 2024) के अलावा दो विश्व कप (2018, 2023) में कोच की भूमिका निभाई. इसके अलावा छह यूरोपीय चैम्पियनशिप (2013, 2015, 2017, 2019, 2021, 2023) में भी कोच रहे. हाई परफार्मेंस सिस्टम, खिलाड़ियों के विकास और पेनल्टी कॉर्नर रणनीति के लिये मशहूर सोयेज ने लगातार ऐसी टीमें तैयार की हैं जिनमें सभी स्तरों पर सुदृढ़ रणनीतिक संरचना और प्रतिस्पर्धी निरंतरता मौजूद रही है.

एचसीएल राष्ट्रीय युगल स्क्वाश के क्वार्टरफाइनल में जीते अभय सिंह-वेलावन सेंथिलकुमार

चेन्नई: अभय सिंह और वेलावन सेंथिलकुमार की शीर्ष वरीयता प्राप्त जोड़ी ने बृहस्पतिवार को यहां तीसरी एचसीएल राष्ट्रीय युगल स्क्वाश चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में शुभम और वेदांत पटेल पर 11-4, 11-2 से शानदार जीत के साथ अपने खिताब बचाने की शुरुआत की. अभय ने पिछले साल अनाहत सिंह के साथ मिश्रित युगल का खिताब भी जीता था. इस बार वह रथिका सीलन के साथ जोड़ी बना रहे हैं. दूसरी वरीयता प्राप्त जोड़ी ने रवि दीक्षित और जेनेट विधि पर 10-12, 11-8, 11-9 से कड़े मुकाबले में जीत के साथ अंतिम चार में जगह बनाई.

श्रीलंका में त्रिकोणीय श्रृंखला के लिए सूर्यवंशी भारत 'ए' टीम में, तिलक करेंगे कप्तानी

नयी दिल्ली: युवा बल्लेबाजी सनसनी वैभव सूर्यवंशी को नौ जून से श्रीलंका में शुरू हो रही 50 ओवर की त्रिकोणीय श्रृंखला के लिए बृहस्पतिवार को भारत 'ए' टीम में शामिल किया गया. भारत और मेजबान श्रीलंका के अलावा टूर्नामेंट की एक अन्य टीम अफगानिस्तान 'ए' है. मैच दाम्बुला में खेले जाएंगे. भारत 'ए' गॉल में दो बहु दिवसीय (चार दिन के) 'टेस्ट' मैच भी खेलेगी लेकिन उसके लिए टीम की घोषणा बाद में की जाएगी. माना जा रहा है कि सूर्यवंशी को टीम में इसलिए शामिल किया गया है क्योंकि चयनकर्ता उन्हें भारत 'ए' टीम के साथ परखना चाहते हैं. चयनकर्ता 26 जून से शुरू होने वाले ब्रिटेन (आयरलैंड और इंग्लैंड) दौरे के लिए सीनियर टीम में चुने जाने से पहले उन्हें आजमाना चाहते हैं. यह तीन देशों की श्रृंखला 21 जून को समाप्त होगी. भारत की 15 सदस्यीय टीम की औसत उम्र लगभग 23 साल है. केवल तेज गेंदबाज अरशद खान, युद्धवीर सिंह और यश ठाकुर ही ऐसे खिलाड़ी हैं जिनकी उम्र 25 साल से अधिक है. टीम में कोई भी खिलाड़ी 30 साल से अधिक का नहीं है और सभी ने विजय हजारे ट्रॉफी (राष्ट्रीय एकदिवसीय चैंपियनशिप) में अच्छा प्रदर्शन किया है. इसके अलावा वे सभी आईपीएल में अनुबंधित

भी हैं. तिलक (मुंबई इंडियन्स) और उप कप्तान रियान पराग (राजस्थान रॉयल्स) के अलावा सूर्यवंशी (राजस्थान रॉयल्स), प्रियांश आर्य, प्रभसिमरन सिंह, सूर्यांश शेडगे (सभी पंजाब किंग्स), हर्ष दुबे (सानराइजर्स हैदराबाद), निशांत सिंधू, अरशद खान (दोनों गुजरात टाइटंस), और आयुष बडोनी (लखनऊ सुपर जाइंट्स) भी मौजूदा आईपीएल सत्र के दौरान अपनी-अपनी टीम के नियमित खिलाड़ी रहे हैं. टीम में शामिल अंशुल कंबोज (टेस्ट), रियान पराग और तिलक वर्मा (टी20 अंतरराष्ट्रीय और एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय) पहले ही सीनियर टीम के लिए खेल चुके हैं. वहीं आयुष बडोनी को इस साल की शुरुआत में भारतीय टीम में चुना गया था लेकिन उन्हें कोई मैच खेलने का मौका नहीं मिला था. तिलक इससे पहले भी भारत 'ए' की कप्तानी कर चुके हैं जबकि आर्य ने पिछले साल ऑस्ट्रेलिया 'ए' के खिलाफ शतक बनाया था. स्पिनरों में दुबे, शेडगे, विपराज निगम शामिल हैं जबकि प्रभसिमरन और कुमार कुशाग्र दो विकेटकीपर हैं. भारत 'ए' की टीम श्रीलंका 'ए' (नौ और 15 जून) और अफगानिस्तान 'ए' (11 और 17 जून) के खिलाफ दो-दो मैच खेलेगी. शीर्ष दो टीम 21 जून को होने वाले फाइनल में भिड़ेंगी. **त्रिकोणीय श्रृंखला के लिए भारत 'ए' टीम:** तिलक वर्मा (कप्तान), प्रियांश आर्य, वैभव सूर्यवंशी, रियान पराग, आयुष बडोनी, निशांत सिंधू, हर्ष दुबे, सूर्यांश शेडगे, प्रभसिमरन सिंह, कुमार कुशाग्र, विपराज निगम, यश ठाकुर, युद्धवीर सिंह, अंशुल कंबोज और अरशद खान.

आईपीएल 2026 के बाद अक्षर पटेल, अजिंक्य रहाणे और ऋषभ पंत की कप्तानी खतरे में

नई दिल्लीः इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में निराशाजनक अभियान के कारण तीन फ्रेंचाइजी के कप्तानों को इस महीने के अंत में सत्र के समापन के बाद अपने पद से हाथ धोना पड़ सकता है. अलग अलग फ्रेंचाइजी के उतार चढ़ाव पर नजर रखने वाले सूत्रों ने इसका संकेत दिया है. अक्षर पटेल, अजिंक्य रहाणे और ऋषभ पंत ने लगातार दो सत्र में अपनी टीम की कप्तानी की है लेकिन अपनी टीम को प्लेऑफ में ले जाने की कोशिश में बुरी तरह नाकाम रहे हैं. आधिकारिक रूप से अभी सिर्फ लखनऊ सुपर जायंट्स ही टूर्नामेंट से बाहर हुई है जिससे पंत लगातार दो सत्र में खराब प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी रहे हैं, लेकिन सभी व्यावहारिक वजहों से रहाणे की अगुआई वाली कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) और अक्षर की कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल्स के भी लीग के आखिरी दौर में बने रहने की उम्मीद कम है. कप्तान और खिलाड़ी के तौर पर अक्षर के का प्रदर्शन खराब रहा है, उन्होंने नौ पारियों में 112.50 के स्ट्राइक-रेट से महज 100 रन बनाए हैं जिसमें से 56 रन एक पारी में और बाकी 44 रन आठ पारियों में बने हैं. यह जब है तब उन्होंने ज्यादातर में शीर्ष पांच में बल्लेबाजी की है. इन 12 मैच में अक्षर ने केवल 36 ओवर गेंदबाजी की है जो तीन ओवर प्रति मैच हैं जिसमें उन्होंने 8.05 के इकोनोमी रेट से 10 विकेट झटके हैं. हालांकि साथी स्पिनर कुलदीप यादव का इकोनोमी रेट और भी खराब है. आईपीएल सूत्र ने गोपनीयता की शर्त

पर कहा, ''अक्षर अपनी कप्तानी की काबिलियत साबित करने में पूरी तरह विफल रहे हैं और ज्यादातर फैसले लेने के लिए हेमांग बदानी और वेणुगोपाल राव पर निर्भर हैं. ऐसे में अगर वह अगले साल भी कप्तान बने रहते हैं तो यह एक चमत्कार होगा.'' सूत्र ने कहा, ''पूरे कोचिंग स्टाफ को भी रिटेन किए जाने की उम्मीद कम है.'' 2027 में होने वाली मेगा नीलामी में अक्षर को बतौर खिलाड़ी रिटेन किया जा सकता है. लेकिन अब तक कप्तानी में उनका प्रदर्शन फीका ही रहा है. पंत ने अलग-अलग स्थान पर बल्लेबाजी करने की कोशिश की है लेकिन अक्सर ऐसा लगा है कि वह अपने कंधों पर काफी बोझ उठाए हुए हैं. एक फ्रेंचाइजी के लिए तुरंत नतीजे मिलना आम बात है, लेकिन लगातार दो सत्र के लिए क्वालीफाई नहीं कर पाना लखनऊ सुपर जायंट्स के मालिक संजीव गोयंका को शायद ही पसंद आए. गोयंका को ऐसे व्यक्ति के रूप में जाना जाता है जो मनचाही कीमत देने को तैयार है लेकिन वह ऐसे व्यक्ति भी हैं जो ऐसे प्रदर्शन की मांग करते हैं जो मेहनताने के साथ सही साबित हो सकें. पंत के 138 के स्ट्राइक-रेट से 251 रन टी20 के आधुनिक मानकों के हिसाब से खराब ही हैं. उन पर दबाव है इस बात से पता चलता है कि उन्होंने 11 मैचों में सिर्फ नौ छक्के लगाए हैं. उनके बल्ले की लय भी गायब है और टीम संयोजन के कुछ फैसलों ने टीम के समर्थकों को भी हैरान कर दिया है. वहीं केकेआर में रहाणे की नियुक्ति काफी हद तक 'कोई विकल्प नहीं' होने के कारण हुआ मामला था क्योंकि फ्रेंचाइजी के पास भरोसेमंद कप्तान के विकल्प की कमी थी. वहीं उनके मुंबई के पूर्व साथी अभिषेक नायर मुख्य कोच थे. हालांकि केकेआर इस बात से परेशान था कि अंगकृष रघुवंशी आधुनिक टी20 क्रिकेट में शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों की मांग के अनुसार प्रदर्शन नहीं कर पाए. रघुवंशी ने 139 से ज्यादा के स्ट्राइक-रेट से 340 रन बनाए जबकि कप्तान रहाणे ने 133 के स्ट्राइक-रेट से 237 रन बनाए. दोनों ने शीर्ष तीन में बल्लेबाजी की जिससे लगभग हर मैच में शुरूआती लय धीमी रही. दोनों ने 11 मैचों में मिलकर सिर्फ 25 छक्के लगाए. रहाणे और रघुवंशी को तो एक ही अंतिम एकादश में साथ नहीं खेलना चाहिए था और प्रबंधन की जिद फ्रेंचाइजी के लिए महंगी साबित हुई.

टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स का चौथी तिमाही का मुनाफा 31 प्रतिशत घटकर 5,878 करोड़ रुपये

मुंबई: टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स (टीएमपीवी) का वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में एकीकृत शुद्ध लाभ 31.29 प्रतिशत घटकर 5,878 करोड़ रुपये रह गया. कंपनी ने वित्त वर्ष 2024-25 की समान (जनवरी-मार्च) तिमाही में 8,556 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ अर्जित किया था. समीक्षाधीन तिमाही में कंपनी की परिचालन आय सात प्रतिशत बढ़कर 1.05 लाख करोड़ रुपये हो गई, जो 2024-25 की इसी तिमाही में 98,377 करोड़ रुपये थी. कंपनी ने बयान में कहा, '' जगुआर लैंड रोवर (जेएलआर) का उत्पादन सामान्य होने और घरेलू बाजार में रिकॉर्ड बिक्री के कारण हालांकि तिमाही आधार पर प्रदर्शन में उल्लेखनीय सुधार हुआ है. इससे चौथी तिमाही में मुक्त नकदी प्रवाह (एफसीएफ) 11,400 करोड़ रुपये रहा.'' बयान के अनुसार जेएलआर पर साइबर हमले, शुल्क, चीन लक्जरी कर, विपणन खर्च के दबाव और कच्चे माल की ऊंची कीमतों जैसे कई प्रतिकूल कारकों का समूचे वित्त वर्ष में कारोबार की लाभप्रदता पर असर पड़ा. कंपनी ने कहा, '' जेएलआर की उत्पादन इकाइयों में रुकावट आने से मुक्त नकदी प्रवाह पर प्रतिकूल असर पड़ा जिससे एकीकृत शुद्ध कर्ज बढ़कर 30,700 करोड़ रुपये हो गया.'' टीएमपीवी के मुख्य वित्तीय अधिकारी धीमन गुप्ता ने कहा, '' वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में सभी एकीकृत वित्तीय मानकों में उल्लेखनीय सुधार हुआ क्योंकि साइबर घटना के बाद जेएलआर का परिचालन सामान्य हुआ और घरेलू कारोबार ने सकारात्मक रुख बनाए रखा. भविष्य में हम नए उत्पादों की पेशकश और लागत नियंत्रण संबंधी उपायों के जरिए अपनी कारोबारी मजबूती को और बढ़ाने पर ध्यान देंगे. हालांकि, वैश्विक भू-राजनीतिक परिस्थितियों और जिंस कीमतों पर अब भी नजर रखने की जरूरत है.''

अपोलो टायर्स का चौथी तिमाही का मुनाफा तीन गुना से अधिक होकर 631 करोड़ रुपये

नयी दिल्ली: अपोलो टायर्स लिमिटेड का वित्त वर्ष 2025-26 की जनवरी-मार्च तिमाही में एकीकृत शुद्ध लाभ तीन गुना से अधिक होकर 630.97 करोड़ रुपये रहा है. कंपनी ने पिछले वित्त वर्ष-2024-25 की समान तिमाही में 184.62 करोड़ रुपये का एकीकृत शुद्ध लाभ अर्जित किया था. अपोलो टायर्स ने शेयर बाजार को दी सूचना में बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में कंपनी की एकीकृत परिचालन आय बढ़कर 7,335.67 करोड़ रुपये हो गई, जो 2024-25 की समान तिमाही में 6,423.59 करोड़ रुपये थी. कंपनी ने कहा कि उसने वित्त अधिनियम 2026 के तहत रियायती कर व्यवस्था अपनाने का फैसला किया है. इसके तहत कंपनी पर लागू कर दर पहले के 34.94 प्रतिशत से घटकर 25.17 प्रतिशत हो जाएगी और उसे न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) से भी छूट मिलेगी. कंपनी ने घटी हुई कर दर के आधार पर अपनी स्थगित कर देनदारियों का पुनर्मूल्यांकन किया, जिससे उसे 573.67 करोड़ रुपये का सकारात्मक प्रभाव मिला. समीक्षाधीन तिमाही में कंपनी का कुल खर्च बढ़कर 6,753.36 करोड़ रुपये हो गया, जो वित्त वर्ष- 2024-25 की समान तिमाही में 6,072.67 करोड़ रुपये था. कंपनी के निदेशक मंडल ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए एक रुपये अंकित मूल्य वाले प्रत्येक शेयर पर 2.50 रुपये के अंतिम लाभांश की सिफारिश की है. यह आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों की मंजूरी के अधीन होगा.

कारोबार

शेयर बाजार में लगातार दूसरे दिन तेजी, सेंसेक्स 790 अंक चढ़ा

मुंबई: घरेलू शेयर बाजारों में उतार-चढ़ाव के बीच बृहस्पतिवार को लगातार दूसरे दिन तेजी रही और सेंसेक्स करीब 790 अंक चढ़कर बंद हुआ. दूरसंचार, दवा और निजी बैंकिंग शेयरों में खरीदारी आने से बाजार को मजबूती मिली. बीएसई का 30 शेयरों वाला मानक सूचकांक सेंसेक्स 789.74 अंक यानी 1.06 प्रतिशत की बढ़त के साथ 75,398.72 अंक पर बंद हुआ. सेंसेक्स ने सत्र की मजबूत शुरुआत की लेकिन जल्द ही यह नकारात्मक क्षेत्र में चला गया. हालांकि, दूरसंचार और बैंकिंग शेयरों में खरीदारी लौटने से यह एक समय 1,000 अंक से अधिक चढ़कर 75,681.88 अंक के स्तर तक पहुंच गया था. वहीं, एनएसई का 50 शेयरों पर आधारित मानक सूचकांक निफ्टी भी 277 अंक यानी 1.18 प्रतिशत चढ़कर 23,689.60 अंक पर बंद हुआ. इस तरह बाजार में लगातार दूसरे दिन तेजी का रुख कायम रहा. सेंसेक्स की कंपनियों में भारती एयरटेल में सर्वाधिक पांच प्रतिशत से अधिक की तेजी आई. कंपनी का वार्षिक राजस्व पहली बार दो लाख करोड़ रुपये के पार पहुंचने के बाद निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ी. इसके अलावा एचडीएफसी बैंक, सन फार्मा, अदाणी पोर्ट्स, बजाज फाइनेंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एनटीपीसी, कोटक महिंद्रा बैंक, टाइटन, आईटीसी और एसबीआई जैसे शेयरों में भी बढ़त दर्ज की गई. वहीं इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, टीसीएस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एक्सिस बैंक और मारुति

सुजुकी के शेयरों में गिरावट रही. जियोजीत इन्वेस्टमेंट्स के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा, ''रुपये के रिकॉर्ड निचले स्तर और कच्चे तेल की ऊंची कीमतों के बावजूद बाजार ने दिन के निचले स्तर से मजबूत वापसी की.'' नायर ने कहा कि सरकार द्वारा रुपये की कमजोरी को संभालने के संभावित कदमों, जैसे विदेशी निवेशकों के लिए बॉन्ड कर राहत और पूंजी बहिर्गमन रोकने के उपायों की उम्मीद से निवेशकों का भरोसा बढ़ा. एशिया के अन्य बाजारों में मिश्रित रुख रहा. चीन का शंघाई कम्पोजिट और जापान का निक्की गिरावट के साथ बंद हुए जबकि हांगकांग का हैंगसेंग स्थिर रहा. दक्षिण कोरिया का कॉस्पी बढ़त में रहा. यूरोपीय बाजार दोपहर के कारोबार में तेजी के साथ कारोबार कर रहे थे. अमेरिकी बाजार भी बुधवार को अधिकतर बढ़त के साथ बंद हुए थे. वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड करीब एक प्रतिशत बढ़कर 106.48 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया. इस बीच, कच्चे तेल के ऊंचे दाम और विदेशी पूंजी की निकासी के चलते रुपया 95.73 प्रति डॉलर (अस्थायी) के अपने सबसे निचले स्तर तक फिसल गया. शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक, विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने बुधवार को 4,703.15 करोड़ रुपये के शेयर बेचे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) ने 5,869.05 करोड़ रुपये की खरीदारी की.

रुपया सात पैसे टूटकर 95.73 प्रति डॉलर के नए सर्वकालिक निचले स्तर पर

मुंबई: अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया बृहस्पतिवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले और कमजोर होकर रिकॉर्ड निचले स्तर 95.73 (अस्थायी) पर रहा. मजबूत अमेरिकी डॉलर और ऊंची ऊर्जा कीमतों के कारण बढ़ती मुद्रास्फीति की चिंताओं के बीच घरेलू मुद्रा में यह गिरावट आई. विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने कहा कि मुद्रास्फीति की चिंताओं और वैश्विक बाजार में डॉलर की मजबूती के कारण रुपये में कमजोर रुख बना रह सकता है. उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया संकट और होर्मुज जलडमरूमध्य की नाकाबंदी से भारत के कच्चे तेल आयात पर असर पड़ा है. कच्चे तेल की कीमतों में तेज वृद्धि से ईंधन आयात भी महंगा हो गया है. कारोबारियों के अनुसार, कच्चे तेल की ऊंची कीमतों, मजबूत डॉलर और पश्चिम एशिया संकट को लेकर चिंताओं के कारण निवेशकों की धारणा प्रभावित हुई है, जिससे रुपया इस वर्ष एशिया की सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली मुद्रा बन गया है. इस साल अब तक इसमें छह प्रतिशत से अधिक की गिरावट आ चुकी है. अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले 95.74 पर कमजोर खुला. दिनभर उतार-चढ़ाव वाले कारोबार में डॉलर के मुकाबले रुपये की विनिमय दर 95.61 के उच्च स्तर और 95.96 के सर्वकालिक निचले स्तर तक गई. अंत में रुपया 95.73 (अस्थायी) प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जो पिछले बंद भाव से सात पैसे की गिरावट है. बुधवार को रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 95.80 के रिकॉर्ड निचले स्तर तक पहुंच गया था और अंत में 95.66 पर बंद हुआ था. मिराए एसेट शेयरखान के शोध विश्लेषक अनुज चौधरी ने कहा, मुद्रास्फीति की चिंताओं और मजबूत डॉलर के कारण रुपये में नकारात्मक रुख बने रहने की उम्मीद है.

थोक मुद्रास्फीति में जबर्दस्त उछाल, अप्रैल में 42 माह के उच्चस्तर 8.3 प्रतिशत पर पहुंची

नयी दिल्ली: पश्चिम एशिया संकट से ईंधन, बिजली एवं कच्चे पेट्रोलियम की कीमतों में तेज वृद्धि के कारण अप्रैल में थोक मुद्रास्फीति सालाना आधार पर पांच प्रतिशत बढ़कर 42 महीने के उच्चतम स्तर 8.3 प्रतिशत पर पहुंच गई. थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) पर आधारित मुद्रास्फीति मार्च में 3.88 प्रतिशत थी. वैश्विक ब्रोकरेज फर्म बार्कलेज के अनुसार, थोक मुद्रास्फीति में क्रमिक वृद्धि इस श्रृंखला में अब तक की सबसे अधिक रही है. वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में तीव्र वृद्धि ने मुख्य मुद्रास्फीति दर में उछाल आया. धातुओं, रसायनों और वस्त्रों की विनिर्माण लागत में वृद्धि के कारण मुख्य थोक मुद्रास्फीति सालाना आधार पर पांच प्रतिशत तक बढ़ गई. पश्चिम एशिया युद्ध और होर्मुज जलडमरूमध्य में अवरोध ने भारत में कच्चे पेट्रोलियम के आयात को बाधित कर दिया है. साथ ही, वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में भारी वृद्धि ने ईंधन आयात को महंगा बना दिया है. मंत्रालय ने बयान में कहा, ''अप्रैल, 2026 में मुद्रास्फीति खनिज तेल, कच्चे पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, मूल धातु, अन्य विनिर्माण और गैर-खाद्य वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि के कारण अधिक रही.'' वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, खाद्य पदार्थों में मुद्रास्फीति दर अप्रैल में 1.98 प्रतिशत रही जबकि मार्च में यह 1.90 प्रतिशत थी. गैर-खाद्य पदार्थों में मुद्रास्फीति अप्रैल में बढ़कर 12.18 प्रतिशत हो गई जो पिछले महीने 11.5 प्रतिशत थी. विनिर्मित उत्पादों में मुद्रास्फीति अप्रैल में 4.62 प्रतिशत रही जबकि पिछले महीने यह 3.39 प्रतिशत थी. ईंधन और बिजली श्रेणी में, एलपीजी में मुद्रास्फीति दर अप्रैल में 10.92 प्रतिशत रही. पेट्रोल में महंगाई दर 32.40 प्रतिशत रही, जो पिछले महीने 2.50 प्रतिशत थी. डीजल में महंगाई दर अप्रैल में 25.19 प्रतिशत रही जबकि मार्च में यह 3.26 प्रतिशत थी. वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में 50 प्रतिशत की वृद्धि के बावजूद सरकार ने अब तक पेट्रोल और घरेलू एलपीजी की कीमतों को स्थिर रखा है ताकि उपभोक्ताओं को कीमतों में बढ़ोतरी के असर से बचाया जा सके. वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में हालांकि वृद्धि की गई है. इसका असर अप्रैल में खुदरा मुद्रास्फीति की 3.48 प्रतिशत की दर में स्पष्ट नजर आया. इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च की निदेशक मेघा अरोड़ा ने कहा कि मुख्य मुद्रास्फीति के मई, 2026 में बढ़कर नौ प्रतिशत तक पहुंचने का अनुमान है. इसकी मुख्य वजह उच्च ऊर्जा कीमतों का धीरे-धीरे पूरी अर्थव्यवस्था पर असर डालना और उसका इस्तेमाल करने वाले क्षेत्रों यानी विनिर्माण क्षेत्र पर इसका प्रभाव पड़ना है. उन्होंने कहा कि थोक मुद्रास्फीति के अधिक रहने के आसार हैं क्योंकि इसमें ईंधन का हिस्सा ज्यादा होता है. साथ ही उपभोक्ताओं तक कच्चे तेल की ऊंची कीमतों का असर धीरे-धीरे पहुंच रहा है, क्योंकि अब तक सरकार एवं पेट्रोलियम विपणन कंपनियों ने उसका बड़ा हिस्सा खुद वहन किया है. बजाज ब्रोकिंग के बुनियादी विश्लेषक शाश्वत सिंह ने कहा कि बढ़ती लॉजिस्टिक लागत, माल ढुलाई और जिंस कीमतों का असर अब धीरे-धीरे थोक महंगाई में दिखाई देने लगा है. इसका असर आगे उपभोक्ता मुद्रास्फीति पर भी पड़ सकता है. बार्कलेज के अनुसार, मई में पेट्रोल और डीजल दोनों की कीमतों में जल्द पांच रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की जा सकती है, क्योंकि कच्चे तेल की कीमतें अब भी ऊंची बनी हुई हैं. साथ ही ऐसा लगता है कि मौद्रिक नीति समिति आपूर्ति झटके से बढ़ी महंगाई को नजरअंदाज करेगी और 2026 के बाकी समय में नीतिगत दर रेपो में कोई बदलाव नहीं करेगी.

न्यूज कॉर्नर

सबरीमाला मामले पर सुनवाई पूरी, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय की नौ जजों की संविधान बेंच ने सबरीमाला मंदिर मामले पर सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया है. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस मामले पर 16 दिनों तक सुनवाई की. उच्चतम न्यायालय की 9 जजों की संविधान बेंच ने इस मामले पर 7 अप्रैल से सुनवाई शुरू की थी. केंद्र सरकार ने इस मामले पर दाखिल अपने हलफनामे में कहा है कि सबरीमाला मंदिर में माहवारी से जुड़े आयु वर्ग की महिलाओं के प्रवेश पर रोक धार्मिक आस्था और स्वायतता का मामला है. केंद्र सरकार ने कोर्ट से इस प्रतिबंध को बरकरार रखने की मांग की है और कहा है कि ऐसे मामलों में न्यायिक समीक्षा की सीमा सीमित होनी चाहिए.मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली इस बेंच में जस्टिस बीवी नागरत्ना, जस्टिस एमएम सुंदरेश, जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह, जस्टिस अरविंद कुमार, जस्टिस एजे मसीह, जस्टिस पीबी वराले, जस्टिस आर महादेवन और जस्टिस जॉयमाल्या बागची शामिल हैं.28 सितंबर 2018 को उच्चतम न्यायालय ने 4-1 के बहुमत से फैसला सुनाया था. कोर्ट ने कहा था कि महिलाओं के साथ काफी समय से भेदभाव होता रहा है. महिला पुरुष से कमतर नहीं है. एक तरफ हम महिलाओं को देवी स्वरुप मानते हैं दूसरी तरफ हम उनसे भेदभाव करते हैं. कोर्ट ने कहा था कि बायोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल वजहों से महिलाओं के धार्मिक विश्वास की स्वतंत्रता को खत्म नहीं किया जा सकता है.तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा समेत चार जजों ने कहा था कि ये संविधान की धारा 25 के तहत मिले अधिकारों के विरुद्ध है.

तेज रफ्तार स्कॉरपियो की चपेट में आकर डिलीवरी ब्वाय की मौत, एक घायल

हिसार: 4 मई (हि.स.). शहर के डाबड़ा चौक पुल पर तेज रफ्तार स्कारपियो गाड़ी ने डिलीवरी देकर जा रहे दो जौमेटा राइडर में टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि उक्त स्कॉरपियो एक जौमेटो ब्वाय को काफी दूर तक घसीटते हुए ले गई, जिससे उसकी मौत हो गई जबकि दूसरा युवक घायल हो गया. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार गुरुवार तड़के हुए हादसे के बाद स्कार्पियो चालक ने अपनी गाड़ी रोकने की बजाय मौके से फरारहो गया. हादसे में पटेल नगर निवासी लगभग 21 वर्षीय सचिन की मौत हो गई जबकि दूसरे मोटरसाइकिलपर सवार आजाद नगर निवासी सुरेन्द्र को चोटें आई, जो उपचाराधीन है. वहां से गुजर रहेलोगों ने घायल को उपचार के लिए शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया. हादसे की सूचना मिलने पर अर्बन एस्टेट और सिविल लाइन पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नागरिक अस्पताल पहुंचाया. पुलिस ने चालक के खिलाफ लापरवाही का केस दर्ज कर जांच आरंभ कर दी है. पटेल नगर में रहने वाले लाल बहादुर ने बताया कि 21 साल का भांजा सचिन परिवार के साथ पटेल नगर में रहता था. परिवार मूलरूप से उत्तर प्रदेश के जिला अमेठी के गांव समरे का रहने वाला है. उन्होंने बताया कि भांजा जेमोटो में डिलीवरी देने का काम करता था.रात को वह डाबड़ा चौक की तरफ किसी को डिलीवरी देने के लिए गया था. साथ में उसका साथी आजाद नगर निवासी सुरेंद्र भी था.

हिसार में प्याज से भरा ट्रक पलटा, एक की मौत

हिसार: जिला के उकलाना क्षेत्र में लितानी मोड के पास अचानक बेसहारा पशु आने से प्याज से भरा ट्रक पलट गया. हादसे में कैथल जिले के बोपर गांव निवासी 70 वर्षीय इन्द्र सिंह की मौत हो गई. हादसे के समय ट्रक में चालक और एक अन्य क्लीनर भी था. गनीमत रही की उनको चोटें नहीं आई. घटना की सूचना मिलने पर उकलाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को जिले के नागरिक अस्पताल पहुंचाया. कैथल जिला के बोपर गांव निवासी तरसेम सिंह ने बताया कि वह ट्रक चालक है. क्लीनर इंद्र सिंह और एक अन्य के साथ नासिग से प्याज लेने के लिए गए थे. आठ मई को ट्रक में प्याज लोड कर पंजाब के लुधियाना शहर के लिए निकले थे. रात करीब दो बजे लितानी मोड के पास पहुंचे तो अचानक ट्रक के सामने बेसहारा पशु आ गया जिससे संतुलन बिगड़ गया और ट्रक पलट गया. ऐसे में क्लीनर इंद्र सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया. उसे उपचार के लिए नागरिक अस्पताल लेकर जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने परिजनों के बयान में इतफाकिया कार्रवाई की है.

हीरो होंडा चौक पर ट्रक की चपेट में आने से स्कूटी सवार की मौत

गुरुग्राम: हीरो होंडा चौक के पास सर्विस लेन पर गुरुवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में स्कूटी सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई. हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी. मृतक युवक की पहचान फिलहाल नई बस्ती निवासी के रूप में हुई है, हालांकि देर शाम तक उसके नाम की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी थी. बताया जा रहा है कि युवक कुछ समय पहले ही अपने घर से निकला था और स्कूटी पर कहीं जा रहा था. इसी दौरान सर्विस लेन पर सामने से आ रहे ट्रक से उसकी टक्कर हो गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रक अपनी सही दिशा में आ रहा था, जबकि स्कूटी सवार गलत दिशा से अचानक सामने आ गया, जिससे यह हादसा हुआ. ट्रक चालक विशाल शर्मा ने भी पुलिस को दिए बयान में यही बात कही है. पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर चालक से पूछताछ शुरू कर दी है. हादसे के कारण हीरो होंडा चौक और आसपास के क्षेत्र में कुछ समय के लिए यातायात प्रभावित रहा.

प्रथम पृष्ठ का शेषांश

कलकत्ता हाईकोर्ट में ममता...

इससे पहले उन्होंने राज्य में मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया को चुनौती देने वाली अपनी याचिका पर अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश होकर दलीलें दी थीं.ममता ने कहा कि चुनाव परिणामों की घोषणा के बाद राज्य में कम से कम 10 लोगों की हत्या कर दी गई, तृणमूल कांग्रेस के लगभग 150-160 कार्यालयों में तोड़फोड़ की गई और हिंसा की लगभग 2,000 घटनाएं हुईं. उन्होंने कहा, 10 मृतकों में से छह हिंदू हैं. कृपया पुलिस से उचित कार्रवाई करने के लिए कहें. वे पुलिस को प्राथमिकी दर्ज नहीं करने दे रहे हैं. मेरे परिवार में 12 साल की बच्चियों को बलात्कार की धमकी दी जा रही है.ममता ने आरोप लगाया कि स्थिति इस हद तक बिगड़ गई है कि वह खुद भी शिकायत दर्ज कराने के लिए पुलिस थाने तक नहीं पहुंच पा रही हैं और उन्हें ऑनलाइन माध्यम का सहारा लेना पड़ रहा है. उन्होंने दावा किया कि राज्य में मछली बाजारों और मांस की दुकानों पर सुनियोजित तरीके से हमले किए गए हैं.ममता ने पीठ के समक्ष पेश तस्वीरों का हवाला देते हुए कहा कि महिलाओं, बच्चों और अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों को खास तौर पर निशाना बनाया गया है, जबकि पार्टी कार्यालयों में पुलिस के सामने लूटपाट की गई है और उन पर कब्जा कर लिया गया है. उन्होंने कहा, अनुसूचित जाति (एससी) के एक परिवार, जिसमें 92 वर्षीय विधवा भी शामिल थी, को उसके घर से निकाल दिया गया. उन्होंने (भाजपा समर्थकों ने) कई घरों में तोड़फोड़ की. बड़ी संख्या में लोग हिंसा झेल रहे हैं, जिनमें सामान्य जाति के हिंदू भी शामिल हैं. तृणमूल सुप्रीमो ने पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि कुछ मामलों में पक्षपातपूर्ण कार्रवाई की गई, जबकि अन्य मामलों में निष्क्रियता दिखाई गई.

वीडी सतीशन सोमवार...

पैमाने पर राजनीतिक शुभारंभ का विकल्प चुना जाएगा.सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस नेतृत्व और प्रमुख सहयोगियों, जिनमें इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और केरल कांग्रेस गुट शामिल हैं, के बीच पोर्टफोलियो आवंटन और मंत्री पदों पर प्रतिनिधित्व को लेकर गहन विचार-विमर्श जारी है. सत्ता बंटवारे का व्यापक फार्मूला काफी हद तक तय हो चुका है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण विभागों और कैबिनेट के भीतर क्षेत्रीय संतुलन को लेकर अभी भी चर्चा जारी है.

ईरान ने यूएई तट के....

भारत के विदेश मंत्रालय ने इस घटना को गंभीर और अस्वीकार्य बताते हुए नागरिक जहाजों पर लगातार हो रहे हमलों की कड़ी निंदा की है. हमले के पीछे कौन था, इसकी जानकारी फिलहाल स्पष्ट नहीं हो सकी है. यह घटना बुधवार को उस समय हुई जब जहाज ओमान के तट के पास से गुजर रहा था. मंत्रालय ने यह भी बताया कि सभी भारतीय चालक दल को ओमान की तटरक्षक टीम ने सुरक्षित बचा लिया और उन्हें दिबा बंदरगाह पर पहुंचाया गया है.

दिल्ली के सरकारी कार्यालयों में सप्ताह में दो दिन वर्क फ्रॉम होम, 'मेरा भारत मेरा योगदान' अभियान की हुई घोषणा

नई दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को दिल्ली सरकार के कार्यालयों में सप्ताह में दो दिन वर्क फ्रॉम होम, सरकारी वाहनों के ईंधन की खपत 20 फीसदी कम करने और 'मेरा भारत मेरा योगदान' अभियान जैसी कई घोषणाएं कीं. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ईंधन बचत की अपील के मद्देनजर दिल्ली सचिवालय में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय बैठक में इससे संबंधित फैसले लिए गए.मुख्यमंत्री ने गुरुवार को दिल्ली सचिवालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वैश्विक स्तर पर जारी आर्थिक अस्थिरता, पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव, ईंधन संकट और बढ़ती आयात लागत का प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ रहा है और भारत भी इससे अछूता नहीं है. ऐसे समय में देशहित को सर्वोपरि रखते हुए प्रत्येक नागरिक का दायित्व है कि वह संसाधनों की बचत और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अपना योगदान दे.

मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली सरकार ने ईंधन बचत और ट्रैफिक प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णय लिए हैं. दिल्ली सरकार के सभी विभागों में सप्ताह में दो दिन 'वर्क फ्रॉम होम' व्यवस्था लागू की जाएगी. निजी कंपनियों और संस्थानों को भी अपनी सुविधा के अनुसार सप्ताह में दो दिन वर्क फ्रॉम होम लागू करने की सलाह दी जा रही है. इस संबंध में श्रम विभाग द्वारा किसी भी प्रकार की समस्या के समाधान के लिए सिंगल विंडो हेल्प डेस्क व कॉल सेंटर भी स्थापित किया जाएगा. साथ ही सरकार बड़ी कंपनियों और संस्थानों से व्यक्तिगत स्तर पर संवाद कर सहयोग सुनिश्चित करेगी.

उन्होंने स्पष्ट किया कि यह व्यवस्था उन आवश्यक सेवाओं पर लागू नहीं होगी, जो सीधे जन-सुविधाओं और सार्वजनिक कार्यों से जुड़ी हैं. इनमें पब्लिक डीलिंग से संबंधित विभाग, फायर सर्विस, अस्पताल, जेल प्रशासन, सार्वजनिक परिवहन, बिजली एवं जल आपूर्ति इत्यादि जैसी आवश्यक सेवाएं शामिल हैं. उन्होंने कहा कि सरकारी स्तर पर वाहनों के उपयोग को न्यूनतम किया जाएगा. नए निर्णय के अनुसार अधिकारियों के पेट्रोल अलाउंस में 20 प्रतिशत तक की कटौती की गई है. जिन वाहनों की पहले 200 लीटर पेट्रोल की सीमा थी, उसे घटाकर 160 लीटर तथा 250 लीटर की सीमा को घटाकर 200 लीटर किया गया है.

उन्होंने बताया कि हर सोमवार को 'मेट्रो मंडे' के रूप में मनाया जाएगा, जिसमें मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और सरकारी कर्मचारी जहां तक संभव होगा, मेट्रो एवं सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करेंगे. दिल्ली सरकार के कार्यालयों का समय अब सुबह 10:30 बजे से शाम 7 बजे तक निर्धारित किया गया है, जबकि दिल्ली नगर निगम कार्यालय सुबह 8:30 बजे से शाम 5 बजे तक संचालित होंगे. केंद्र सरकार के कार्यालयों का समय सुबह 9 से शाम 5:30 बजे है. कार्यालयों के समय के इस अंतराल से ट्रैफिक का दबाव कम किया जा सकेगा. मुख्यमंत्री ने दिल्ली की जनता से सप्ताह में एक दिन 'नो व्हीकल डे' मनाने की अपील करते हुए कहा कि नागरिक अपनी सुविधा अनुसार एक दिन निजी वाहन का उपयोग न करने का संकल्प लें. उन्होंने कहा कि अगले छह महीने तक दिल्ली सरकार कोई नया पेट्रोल, डीजल, सीएनजी या हाइब्रिड वाहन नहीं खरीदेगी. उन्होंने यह भी जानकारी दी कि ग्रेड-1 से ग्रेड-8 तक के कर्मचारियों और अधिकारियों को यदि वे अपने ट्रांसपोर्ट अलाउंस का कम से कम 25 प्रतिशत सार्वजनिक परिवहन जैसे मेट्रो आदि पर खर्च करते हैं तो सरकार की ओर से 10 प्रतिशत अतिरिक्त ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया जाएगा.उन्होंने कहा कि मालवाहक कंपनियों से अपील की जाएगी कि वे अपने माल की ढुलाई ट्रकों के बजाय ट्रेन से करें. इससे डीजल की बचत होगी.

मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि सरकारी कर्मचारियों के बीच सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली की 29 सरकारी कॉलोनियों में रहने वाले कर्मचारियों के लिए 58 फीडर बसों का विशेष रूट प्लान तैयार किया गया है, जो कर्मचारियों को कॉलोनियों से मेट्रो स्टेशनों तक पहुंचाने का कार्य करेंगी. इसके साथ ही सभी विभागों के घरेलू यात्रा व्यय में भी 20 प्रतिशत तक कटौती की जाएगी तथा सरकार की 50 प्रतिशत बैठकों को ऑनलाइन मोड में आयोजित किया जाएगा.मुख्यमंत्री ने विश्वविद्यालयों और कॉलेजों से अपील की कि नॉन-प्रैक्टिकल क्लासेस, गेस्ट लेक्चर्स और प्रशासनिक बैठकों को अधिकतम ऑनलाइन माध्यम से संचालित किया जाए.

मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले एक वर्ष तक दिल्ली सरकार के मंत्री और अधिकारी किसी भी आधिकारिक विदेशी दौरे पर नहीं जाएंगे. पहले से निर्धारित कुछ आधिकारिक विदेशी कार्यक्रमों को भी रद्द कर दिया गया है. साथ ही अगले तीन महीने तक बड़े सरकारी सार्वजनिक कार्यक्रमों और कॉन्फ्रेंसों को सीमित रखा जाएगा. उन्होंने दिल्लीवासियों से भी अपनी विदेशी यात्राओं को सीमित करने की अपील की है.मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजली की बचत के लिए सभी सरकारी कार्यालयों में एयर कंडीशनर 24 से 26 डिग्री तापमान पर अनिवार्य रूप से सेट किए जाएंगे. कार्यालयों में ऊर्जा बचत के लिए सेंसर और मास्टर स्विच भी लगाए जाएंगे ताकि अनावश्यक बिजली खपत रोकी जा सके.

मुख्यमंत्री ने कहा 'मेरा भारत मेरा योगदान' को लेकर पूरी दिल्ली में 90 दिनों तक जनजागरुकता अभियान चलाया जाएगा. इसके अंतर्गत स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, आरडब्ल्यूए, महिला समूहों, संस्थानों और कंपनियों में विभिन्न प्रकार की शपथ दिलाई जाएंगी. इनमें ईंधन बचत, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग, अनावश्यक निजी वाहन उपयोग में कमी, गैर-जरूरी विदेशी यात्रा से बचाव, 'मेड इन इंडिया' उत्पादों को अपनाने तथा खाद्य तेल की अनावश्यक खपत कम करने जैसे विषय शामिल है.

सीएम रेखा गुप्ता ने अपने काफिले को चार वाहनों में सीमित किया

नई दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ईंधन बचत की अपील के बाद गुरुवार को अपने आधिकारिक काफिले को चार वाहनों में सीमित कर दिया है. इसमें इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) एवं सार्वजनिक परिवहन को प्राथमिकता देने का भी निर्णय लिया गया है.

मुख्यमंत्री गुरुवार को डॉ. बी.आर अंबेडकर विश्वविद्यालय के 14वें दीक्षांत समारोह में शामिल होने के लिए भी न्यूनतम सुरक्षा और इलेक्ट्रिक वाहन के जरिए पहुंचीं. उनका यह कदम न केवल पर्यावरण संरक्षण बल्कि वीआईपी संस्कृति से आगे बढ़कर जिम्मेदार एवं संवेदनशील प्रशासनिक व्यवस्था की दिशा में एक महत्वपूर्ण संदेश है.

मुख्यमंत्री ने एक विज्ञप्ति जारी कर जानकारी दी कि वह अपने काफिले में अधिकतर चार वाहनों को रखेंगी. उन्होंने न केवल अपने काफिले की गाड़ियों की संख्या कम की, बल्कि मंत्रियों और अधिकारियों को भी निर्देश दिया कि वे विभागीय कार्यों के लिए मेट्रो, बसों या इलेक्ट्रिक वाहनों को प्राथमिकता दें. उन्होंने सभी मंत्रियों, विधायकों, अधिकारियों और नागरिकों से भी सार्वजनिक परिवहन, कारपूलिंग और इलेक्ट्रिक वाहनों को प्राथमिकता देने की अपील की.

असम में घुसपैठ कर रहे 12 बांग्लादेशियों को रोका गया : हिमंत बिस्वा सरमा

गुवाहाटी: असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्व सरमा ने गुरुवार को कहा कि सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) और असम पुलिस ने 12 कथित घुसपैठियों को असम में घुसपैठ करने से रोक दिया.मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में यह जानकारी साझा करते हुए कहा कि यह अभियान बीती मध्य रात्रि के ठीक बाद चलाया गया था, जो राज्य में अवैध घुसपैठ पर चल रही कड़ी कार्रवाई का ही एक हिस्सा है.डॉ. हिमंत बिस्व सरमा ने बताया कि बुधवार और गुरुवार की मध्य रात्रि करीब 12:20 बजे, असम पुलिस ने बीएसएफ के साथ मिलकर घुसपैठियों की हलचल को रोका और 12 अवैध लोगों को असम में घुसने से रोक दिया. हालांकि, राज्य के किस हिस्से से घुसपैठ हो रही थी.

नीट परीक्षा समाप्त करने की मांग तेज: नई शिक्षा नीति पर राष्ट्रीय बहस छेड़ने का आह्वान

जयपुर: नीट परीक्षा 2026 में पेपर लीक और लगातार सामने आ रही अनियमितताओं के बाद अब देशभर में परीक्षा प्रणाली को लेकर विरोध तेज होने लगा है. राष्ट्रीय यूनाइटेड बैकवर्ड क्लासेज (एनयूबीसी) सहित राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यक महासंघ ने केंद्र सरकार से नीट परीक्षा को तत्काल प्रभाव से समाप्त करने की मांग उठाई है.महासंघ के पदाधिकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को संबोधित मांग पत्र में कहा कि नीट परीक्षा के दौरान लगातार पेपर आउट, तकनीकी गड़बड़ियों और अनियमितताओं ने लाखों विद्यार्थियों एवं अभिभावकों को मानसिक तनाव में डाल दिया है. उनका कहना है कि बार-बार सामने आ रहे विवादों से परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं.महासंघ ने सुझाव दिया कि मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए 12वीं कक्षा की मेरिट आधारित प्रणाली लागू करने पर विचार किया जाना चाहिए. उनका मानना है कि इससे विद्यार्थियों को अत्यधिक मानसिक दबाव, महंगी कोचिंग संस्कृति और प्रतियोगी परीक्षा के तनाव से राहत मिल सकेगी. एनयूबीसी के प्रदेश अध्यक्ष हनुमान सहाय सिरसी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सीताराम मीणा, प्रदेश महासचिव संगठन श्रवण कुमार मेहरड़ा तथा राष्ट्रीय मुख्य संरक्षक डॉ. मदन यादव ने देशभर के शिक्षाविदों, सामाजिक संगठनों और आमजन से इस मुद्दे पर व्यापक राष्ट्रीय बहस छेड़ने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों के हित में पारदर्शी, न्यायपूर्ण और भरोसेमंद शिक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है.

ब्रिटेन की राजनीति में हलचल, स्वास्थ्य मंत्री वेस स्ट्रीटिंग ने दिया इस्तीफा

लंदन: ब्रिटेन की राजनीति में उस समय हलचल तेज हो गई जब प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर के प्रमुख सहयोगियों में शामिल स्वास्थ्य मंत्री वेस स्ट्रीटिंग ने सरकार से इस्तीफा दे दिया. स्ट्रीटिंग ने कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री के नेतृत्व पर अब भरोसा नहीं रहा और ऐसे माहौल में सरकार में बने रहना अनुचित और सिद्धांतों के खिलाफ होगा.स्ट्रीटिंग का इस्तीफा ऐसे समय आया है, जब लेबर पार्टी हालिया स्थानीय चुनावों में खराब प्रदर्शन के बाद आंतरिक असंतोष का सामना कर रही है. इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स में हुए चुनावों में पार्टी को झटके लगे, जिसके बाद करीब 90 लेबर सांसदों ने सार्वजनिक रूप से स्टार्मर से पद छोड़ने की मांग की है.

अपने इस्तीफा पत्र में स्ट्रीटिंग ने कहा कि देश में बढ़ती राजनीतिक अस्थिरता और राष्ट्रवादी ताकतों के उभार ने यूनाइटेड किंगडम की एकता के लिए चुनौती पैदा कर दी है. उन्होंने आरोप लगाया कि लेबर पार्टी अपने समर्थकों को स्पष्ट दिशा और मजबूत नेतृत्व देने में विफल रही है.

हालांकि, स्ट्रीटिंग ने फिलहाल पार्टी नेतृत्व की दौड़ में उतरने की औपचारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक उन्हें स्टार्मर के संभावित उत्तराधिकारी के रूप में देख रहे हैं. लेबर पार्टी में नेतृत्व चुनौती शुरू करने के लिए उन्हें सांसदों के एक बड़े वर्ग का समर्थन जुटाना होगा.स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर स्ट्रीटिंग को ब्रिटेन की राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा (एनएचएस) में सुधार की जिम्मेदारी सौंपी गई थी. उनके इस्तीफे के दिन ही जारी सरकारी आंकड़ों में एनएचएस की वेटिंग लिस्ट में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई, जिसे उनकी बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है.

दिल्ली आबकारी घोटाला : केजरीवाल समेत चार आरोपितों को अवमानना का नोटिस

नई दिल्ली: दिल्ली आबकारी घोटाला मामले की सुनवाई कर रही दिल्ली उच्च न्यायालय की जज जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत चार आरोपितों के खिलाफ कोर्ट की अवमानना का नोटिस जारी किया है. जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच ने केजरीवाल के अलावा संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और दुर्गेश पाठक को अवमानना का नोटिस जारी किया है. जस्टिस शर्मा की बेंच ने इस मामले को अब दूसरे बेंच के पास सुनवाई के लिए भेज दिया है. कोर्ट ने कहा कि अगर इन आरोपितों पर कार्रवाई नहीं हुई तो अराजकता फैलेगी. जस्टिस शर्मा ने कहा कि जब संस्था को ट्रायल पर रखा जाता है तो ये जज का कर्तव्य है कि वो इन आरोपों से संचालित न हो. उन्होंने कहा कि कोर्ट को ये पता चला कि पत्र और वीडियो के जरिये सोशल मीडिया कैंपेन चलाया गया जो काफी सर्कुलेट हुआ. ये एक सुनियोजित और संगठित कैंपेन था. जस्टिस शर्मा ने कहा कि कोर्ट के अंदर हुई कार्यवाही को कोर्ट के बाहर एक समानांतर नैरेटिव चलाया गया.

जस्टिस शर्मा ने कहा कि उन्हें निष्पक्ष आलोचना और असहमति को स्वीकार करने का प्रशिक्षण मिला है. सोशल मीडिया पर कैंपेन के जरिये न केवल किसी एक जज के खिलाफ नैरेटिव बनाया गया, बल्कि ये पूरी न्यायपालिका को कटघरे में खड़ा किया गया. नैरेटिव चलाने वाले कुछ लोगों को राजनीतिक शक्ति भी हासिल है. संपादित वीडियो सर्कुलेट किया गया. जस्टिस शर्मा ने कहा कि जब मैंने अपना फैसला सुनाया तो उनके पास उच्चतम न्यायालय जाने का विकल्प था लेकिन वे नहीं गए, बल्कि वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर मेरे खिलाफ कैंपेन चलाया गया.

जस्टिस शर्मा ने कहा कि मेरी ड्यूटी संविधान के प्रति है. जब उन्होंने ये रास्ता चुना तो हमने भी दूसरा रास्ता चुना. उन्होंने कहा कि कोर्ट के अंदर केजरीवाल ने कहा कि वे कोर्ट का

सम्मान करते हैं लेकिन बाहर उन्होंने हमारे खिलाफ अभियान चलाया. जस्टिस शर्मा ने कहा कि उनके बच्चों का इससे कोई लेना-देना नहीं है. उसके बावजूद उन्हें टारगेट किया गया. वो चाहते थे कि मैं डर जाऊं और इस केस से अलग हो जाऊं. मेरे पास एक दूसरा रास्ता कोर्ट की अवमानना का है. मैंने वो दूसरा रास्ता चुना. वो मुझे डराना चाहते थे.

जस्टिस शर्मा ने आज सुबह ही कहा था कि वे कुछ लोगों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू करेंगी. उन्होंने कहा था कि वो अब इस मामले में शांत नहीं बैठेंगी.

त्रिपुरा सरकार का बड़ा फैसला, आधे कर्मचारी करेंगे वर्क फ्रॉम होम

अगरतला: त्रिपुरा में ईंधन का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और लोगों को किसी प्रकार की घबराहट या अनावश्यक खरीदारी करने की जरूरत नहीं है. राज्य सरकार सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को और अधिक मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है. यह बातें त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉ. माणिक साहा ने गुरुवार को कही.

एक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सभी लोगों से अनावश्यक रूप से सोना और ईंधन नहीं खरीदने तथा ईंधन का सीमित उपयोग करने की अपील की है. इसी दिशा में त्रिपुरा सरकार ने भी कदम उठाते हुए ग्रुप-सी और ग्रुप-डी के 50 प्रतिशत कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की अनुमति दी है, ताकि ईंधन की बचत की जा सके. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए निर्देश हमेशा सोच-समझकर लिए जाते हैं. उन्होंने कोविड-19 का उल्लेख करते हुए कहा कि उस समय भी प्रधानमंत्री ने इसी तरह की कई सावधानियां अपनाने की अपील की थी, जिसका लोगों ने पालन किया था. उन्होंने कहा कि आज सड़कों पर वाहनों की संख्या भी कम दिखाई दे रही है, जिससे साफ है कि आम लोग भी ईंधन बचाने को लेकर जागरूक हो रहे हैं.

गुवाहाटी से लौटने के बाद मुख्यमंत्री ने पुलिस महानिदेशक और मुख्य सचिव के साथ बैठक कर स्थिति की समीक्षा की और इसके बाद प्रशासनिक कामकाज प्रभावित हुए बिना ईंधन बचत के उपाय लागू किए गए.

माणिक साहा ने कहा कि देश को ईंधन आयात को लेकर कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए सरकार और आम जनता दोनों को मिलकर जिम्मेदारी निभानी होगी. उन्होंने विश्वास जताया कि देश जल्द ही वर्तमान परिस्थितियों से बाहर निकल आएगा. साथ ही उन्होंने कहा कि निजी वाहनों पर निर्भरता कम करने के लिए राज्य में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को और अधिक सशक्त बनाया जाएगा.मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य में ईंधन का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और फिलहाल राशनिंग को लेकर कोई निर्देश जारी नहीं किया गया है.

युवा शक्ति माथापच्ची- 68

● **बाएं से दाएं**

1. पुराना, जो सदा से होता आया है, 5. नियत अवधि वाला, 6. मनुष्य-संबंधी, 7. जिसका तला पतला होता जाए, 9. शहर, 11. विष, 12. अर्पण करना, बांटना, 14. सबसे बडा देवता, विष्णु, 15. घुडसाल, 17. परम्पराहीन, नया,

● **उपर से नीचे**

1. उत्तम भाव, परोपकार, 2. सरकार द्वारा अधिग्रहण, 3. उलटा करो तो एक संख्या, 4. ज्यादातार, प्राय:, 7. जिसका क्षय न हो, अविनाशी, 8. दूर की वस्तु/स्थान/मनुष्य को दर्शाने वाला शब्द, 9. माथा झुकना, 10. रोग, विष, गला, यदि, 13. जिसकी अवधि तय है, 16. बिच्छू का डंक उलटा है यहां,

उत्तर कल के अंक में

माथापच्ची- 67 का हल

प्र	ति	वे	द	न	■	सं	■	द
त्या	■	■	शा	■	सं	सा	ध	न
शी	र्षा	स	न	■	र	■	द	
■	■	ह	न	न	■	■	घ	ना
ह	रा	ना	■	वा	■	ह	टा	ना
म	जा	■	■	ज	ठ	र	■	■
स	■	ब	■	■	ह	म	रा	ज
फ	रि	या	द	■	रा	■	■	न
र	■	र	■	व्य	व	हा	रि	क

सुडोकू-47

	1				4	2		8
			2	5		1	7	
					1		9	3
1		8	5		2	9		7
	5		4		3		8	
6		2	7		8	3		1
3	8		9					
	9	7		3	5			
5		1	8				3	

9X9 के उपरोक्त खानों में एक से नौ तक के अंक ऐसे भरें ताकि हर कॉलम और उसके हर छोटे खाने में एक नंबर ही आयें. उत्तर अगले अंक में

सूडोकू -46 का उत्तर

6	8	5	7	2	1	9	4	3
2	3	7	5	9	4	8	6	1
9	1	4	3	8	6	7	5	2
4	6	3	1	7	2	5	9	8
5	7	2	8	6	9	1	3	4
1	9	8	4	5	3	2	7	6
3	5	6	2	1	7	4	8	9
7	4	1	9	3	8	6	2	5
8	2	9	6	4	5	3	1	7

बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के वंशज की नैहाटी को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की योजना

कोलकाताः नैहाटी से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक और ''वंदे मातरम्'' के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के वंशज सुमित्रो चटर्जी ने बुधवार को कहा कि उनकी योजना इस महान उपन्यासकार के जन्मस्थान को एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की है, जहां लोग आकर उनके पैतृक घर को देख सकें. चट्टोपाध्याय का जन्म 1838 में वर्तमान उत्तर 24 परगना जिले के नैहाटी कस्बे के पास स्थित काठालपाड़ा गांव में हुआ था. भाजपा के टिकट पर नैहाटी विधानसभा सीट से चुनाव जीतने वाले चटर्जी ने बुधवार को विधायक पद की शपथ ली. उन्होंने चुनाव से ठीक पहले भाजपा का दामन थामा था. शपथ ग्रहण के बाद बातचीत में चटर्जी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार को ''वंदे मातरम्'' को वास्तविक सम्मान देने के लिए धन्यवाद दिया. उन्होंने कहा कि पहले सरकारी कार्यक्रमों में इसे राष्ट्रीय गीत के रूप में पूर्ण रूप से नहीं गाया जाता था. उन्होंने पूर्व राज्य और केंद्र सरकारों पर आरोप लगाया कि उन्होंने चट्टोपाध्याय के आवास के लिए उसे अधिग्रहित कर विरासत भवन घोषित करने के अलावा कुछ नहीं किया. विधायक ने कहा कि चट्टोपाध्याय के पैतृक आवास को पर्यटकों के सामने उचित तरीके से प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके कारण यह अब तक काफी उपेक्षित बना हुआ है. उन्होंने कहा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले ही कह चुके हैं कि केंद्र सरकार के पास नैहाटी को बंकिम चंद्र की स्मृतियों से जुड़े पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की व्यापक योजनाएं हैं, जहां उनकी बहुआयामी प्रतिभा, राष्ट्रवादी विचारधारा और साहित्यिक कृतियों को देशी और विदेशी पर्यटकों के सामने प्रस्तुत किया जाएगा. चटर्जी ने कहा कि नैहाटी के निवासी और चट्टोपाध्याय के वंशज होने के नाते उनके पास पूरे इलाके के विकास के लिए कई नए सुझाव हैं. उन्होंने कहा कि नैहाटी को समग्र पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना के तहत वहां मौजूद एक बड़ी लेकिन अनुपयोगी झील को साफ कर मत्स्य परियोजना शुरू की जा सकती है. झील के पास एक रिसॉर्ट बनाया जा सकता है और उसे ''डेस्टिनेशन वेडिंग'' स्थल के रूप में विकसित किया जा सकता है. ''वंदे मातरम्'' की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1875 या 1876 में की थी. बाद में इसे उनके 1882 में प्रकाशित उपन्यास आनंदमठ में शामिल किया गया. चटर्जी ने कहा कि हालांकि यह कहा जाता है कि राष्ट्रीय गीत की रचना चिनसुरा में हुई थी, लेकिन नैहाटी ने भी इसकी रचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. हुगली जिले का चिनसुरा और नैहाटी, दोनों हुगली नदी के दो किनारों पर स्थित हैं.

एसआईआर से हटाए गए नामों को नहीं मिलेगा राशन

सरकारी योजनाओं से बाहर करने की तैयारी

कोलकाताः निर्वाचन आयोग की ओर से कराई गई विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया यानी एसआईआर अब केवल मतदाता सूची तक सीमित नहीं रही है. बंगाल की नई भाजपा सरकार अब इसी आंकड़े के आधार पर सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों की भी जांच करने जा रही है. सरकार ने संकेत दिए हैं कि एसआईआर के दौरान जिन लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं, उन्हें राशन, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण और अन्य सामाजिक योजनाओं से बाहर किया जा सकता है. भाजपा सरकार बनने के बाद बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने साफ किया है कि मतदाता सूची से हटाए गए लोगों को फिलहाल कई सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा. दरअसल, निर्वाचन आयोग ने बंगाल के 2026 विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची को शुद्ध करने के लिए एसआइआर अभियान चलाया था. इसके तहत मृत, डुप्लीकेट और कथित रूप से अयोग्य मतदाताओं के नाम हटाए गए. रिपोर्ट के अनुसार बंगाल में लगभग 91 लाख नाम सूची से हटाए गए. बंगाल में हटाए गए नामों में 27 लाख से अधिक लोगों को लाजिकल डिस्क्रेपेंसी श्रेणी में रखा गया था, जिसके कारण वे विधानसभा चुनाव में मतदान नहीं कर सके थे. बंगाल सरकार अब मतदाता सूची को सरकारी योजनाओं के डाटाबेस से जोड़कर लाभार्थियों की जांच करेगी. महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री अग्निमित्रा पाल ने कहा कि एक जून से शुरू होने वाली 'अन्नपूर्णा भंडार' योजना में केवल सत्यापित महिलाओं को ही शामिल किया जाएगा. इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपये देने का वादा किया गया है. उन्होंने कहा कि जिन लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं या जिनके मामले अभी ट्रिब्यूनल में लंबित हैं, उन्हें फिलहाल योजना का लाभ नहीं मिलेगा. सरकार यह भी जांच करेगी कि मृत व्यक्तियों या कथित अवैध घुसपैठियों के नाम पर कहीं योजनाओं का लाभ तो नहीं लिया जा रहा. सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार यदि बाद में किसी व्यक्ति का नाम फिर से मतदाता सूची में जुड़ जाता है तो उसे दोबारा लाभार्थी सूची में शामिल किया जाएगा. मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि पुरानी सभी सामाजिक योजनाएं जारी रहेंगी, लेकिन अब पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से चलेगी. उन्होंने कहा कि किसी मृत व्यक्ति, अवैध घुसपैठिये या गैर भारतीय नागरिक को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं लेने दिया जाएगा. बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने पहले भी एसआइआर प्रक्रिया का विरोध किया था. पार्टी का आरोप था कि अल्पसंख्यक और प्रवासी बहुल इलाकों में बड़े पैमाने पर नाम हटाकर मतदाताओं को मतदान से वंचित किया गया.

श्री शिक्षायतन स्कूल के विद्यार्थियों का शानदार प्रदर्शन

युवा शक्ति न्यूज

कोलकाता : पिछले वर्षों की भांति इस वर्ष भी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा (कक्षा 12वीं) 2026 में श्री शिक्षायतन स्कूल के विद्यार्थियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए विद्यालय का गौरव बढ़ाया है. विद्यालय ने 88.04% का उत्कृष्ट औसत (मीन) बनाए रखा, जो शहर के अधिकांश विद्यालयों से बेहतर है. विद्यालय के सभी 230 विद्यार्थियों ने 70% से अधिक अंक प्राप्त किए. विज्ञान संकाय में सर्वाधिक 98.6%, मानविकी संकाय में 98.4% तथा वाणिज्य संकाय में 98.2% अंक प्राप्त हुए. कुल 32 विद्यार्थियों ने 95% एवं उससे अधिक अंक प्राप्त किए, जबकि 99 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक अर्जित कर उल्लेखनीय सफलता हासिल की. विद्यार्थियों का न्यूनतम परिणाम भी 72.6% रहा, जो श्री शिक्षायतन स्कूल के उच्च शैक्षणिक स्तर को दर्शाता है. विशेष गर्व की बात यह है कि 45 विद्यार्थियों ने विभिन्न विषयों में शत-प्रतिशत (100 में 100) अंक प्राप्त कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है. यह उपलब्धि इसलिए भी विशेष है क्योंकि जब पूरे देश में प्रतिशतों में गिरावट देखी गई है, तब भी विद्यालय ने अपने उत्कृष्ट परिणामों की परंपरा को कायम रखा है. पिछले सात वर्षों से विद्यालय के सभी विद्यार्थी लगातार 60% से अधिक अंक प्राप्त करते आ रहे हैं. इस शानदार सफलता का श्रेय विद्यार्थियों की लगन, शिक्षकों की अथक मेहनत, अभिभावकों के सहयोग तथा विद्यालय प्रबंधन की दूरदर्शी सोच और कुशल मार्गदर्शन को जाता है. विद्यालय परिवार इस सफलता पर सभी विद्यार्थियों को हार्दिक बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता है.

केंद्र सरकार का बड़ा फैसला

सीबीआई निदेशक प्रवीण सूद को फिर मिला सेवा विस्तार

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के निदेशक प्रवीण सूद के कार्यकाल को एक बार फिर बढ़ाने का फैसला किया है. यह उनके कार्यकाल में दूसरा सेवा विस्तार है. इससे पहले मंगलवार को अगले सीबीआई निदेशक की नियुक्ति के लिए पीएमओ में बैठक हुई थी. जिसमें मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी शामिल हुए थे. केंद्र सरकार ने बुधवार को सीबीआई निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल फिर से एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया. सूद ने 25 मई 2023 को दो वर्ष की अवधि के लिए सीबीआई निदेशक का पदभार संभाला था. इससे पहले मई 2025 में भी उनको एक साल के सेवा विस्तार दिया गया था, अब वह इस पद पर मई 2027 तक बने रहेंगे. सरकार की ओर से जारी बयान में मुताबिक, उनके कार्यकाल को बढ़ाने का निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई चयन समिति की बैठक में लिया गया. इस समिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी शामिल थे. चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर नियुक्तियों की मंत्रिमंडलीय समिति (एसीसी) ने एक वर्ष की अवधि के लिए सूद के कार्यकाल के विस्तार को मंजूरी दी. प्रवीन सूद 1986 बैच के कर्नाटक कैडर के भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी हैं. उन्हें केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) का निदेशक नियुक्त किए जाने से पहले कर्नाटक के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) के रूप में कार्यरत थे. सूद का जन्म 1964 में हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में हुआ था. उन्होंने 22 वर्ष की आयु में भारतीय पुलिस सेवा ज्वाइन की थी.

श्री जैन विद्यालय हावड़ा का उच्च माध्यमिक परीक्षा फल शत प्रतिशत रहा

युवा शक्ति न्यूज

हावड़ा : श्री जैन विद्यालय, फॉर बॉयज़, हावड़ा का इस वर्ष भी उच्च माध्यमिक परीक्षा का नतीजा शत प्रतिशत रहा है. इस वर्ष कुल परीक्षार्थियों की संख्या 210 थी, जिनमें से 90 प्रतिशत से ऊपर 3 छात्र, 80- 89 प्रतिशत 34 छात्र, 70-79 प्रतिशत 89 छात्र, 60-69 प्रतिशत 74 छात्र तथा 60 प्रतिशत से कम 13 छात्र उत्तीर्ण रहे हैं. कॉमर्स विभाग में प्रथम स्थान युवराज सिंह (454), द्वितीय स्थान रितेश तिवारी (442) और तृतीय स्थान अनुज कुमार राय और कारण साव (441) प्राप्त किए हैं. साइंस विभाग में प्रथम स्थान विशाल शाह (459), द्वितीय स्थान अमन गुप्ता (455) और तृतीय स्थान शुभम कुमार सिंह (441) प्राप्त किए हैं. आर्ट विभाग में प्रथम स्थान आकाश कुमार झा (435), द्वितीय स्थान रत्नेश तिवारी (325) और तृतीय स्थान पीयूष अग्रवाल (315) प्राप्त किए हैं. विद्यालय की प्रिन्सिपल श्रीमती इंदु जोसफ चौधरी ने सभी छात्रों सहित शिक्षकों को बधाई और धन्यवाद दिया. विद्यालय के सचिव श्री ललित जी कांकरिया ने विद्यालय के शत प्रतिशत परीक्षा फल के लिए सभी शिक्षकों एवं छात्रों को बधाई दिया. वहीं श्री जैन विद्यालय फॉर गर्ल्स, हावड़ा का इस वर्ष उच्च माध्यमिक परीक्षा का नतीजा शत प्रतिशत रहा है. इस वर्ष परीक्षार्थियों की कुल संख्या 368 थीं, जिनमें से 90 प्रतिशत से अधिक 28 छात्राएं, 80-89 प्रतिशत 83 छात्राएं, 70-79 प्रतिशत 128 छात्राएं, 60-69 प्रतिशत 85 छात्राएं और 60 प्रतिशत से कम 44 छात्राएं उत्तीर्ण रही हैं. कॉमर्स विभाग में प्रथम स्थान अमिषा झा (479), द्वितीय स्थान भूमिका मिश्र ((477) और तृतीय स्थान ज्योति ठाकुर (480) प्राप्त की हैं. साइंस विभाग में प्रथम स्थान समद्रिता प्रामाणिक (450), द्वितीय स्थान खुशबू कुमारी हलवाई (444) तथा तृतीय स्थान शगुन बेनिया (441) प्राप्त की हैं. आर्ट्स विभाग में प्रथम स्थान प्रियाणी गुप्ता (470), द्वितीय स्थान रिद्धिशा सिंह (432) और तृतीय स्थान अंजली मिश्रा (429) प्राप्त की है. विद्यालय की प्रधानाध्यापिका श्रीमती मौसमी घोषाल ने अपने सभी छात्राओं एवं शिक्षिकाओं को बधाई और धन्यवाद दिया. विद्यालय के सचिव श्री ललित जी कांकरिया ने विद्यालय के शत-प्रतिशत परीक्षा फल के लिए सभी को धन्यवाद एवं बधाई दिया.

SHREE JAIN VIDYALAYA
(A unit of Shree S. S. Jain Sabha)
18/D, Phusraj Bachhawat Path (Sukeas Lane),
KOLKATA-700 001

ADMISSION GOING ON
SCIENCE & COMMERCE STREAM
For Class-XI [2026-27]

Facilities :
☑ Interactive Flat Panels in all Classrooms
☑ All Classrooms fully Airconditioned
☑ Modern & Digital Library
☑ State of the Art Science Labs
☑ Highly Qualified Teaching Faculty

100% Tuition Fee* Waiver those obtaining above 90% marks & 50% Tuition Fee* Waiver for those obtaining above 85% marks.
* Condition apply.

CONGRATULATIONS!
for Excellent HIGHER SECONDARY Result.
Out of 333 Students appeared
All Students Ranked 1st Division

HIGHER SECONDARY SCIENCE
1ST EMON MONDAL Marks : 470 [94%]
2ND AYUSH PANDEY Marks : 461 [92.2%]
3RD ARSHAD ESRAR Marks : 455 [91%]

COMMERCE
1ST HIMANSU SHAW Marks : 474 [94.8%]
2ND ARSHIT KUMAR PRASAD Marks : 473 [94.6%]
2ND ANKUSH PANDEY Marks : 473 [94.6%]
2ND MAHESH DIGGA Marks : 473 [94.6%]
3RD ANKUR SHAW Marks : 470 [94%]

Outstanding Result in MADHYAMIK
1ST PARMESWAR LAL PAREEK Marks : 637 [91%]
2ND AYUSH SHAW Marks : 634 [90.57%]
3RD ASHUTOSH SHAW Marks : 630 [90%]

Visit : www.sjv.edu.in or Contact School Office | for Online Admission visit : www.admissiontree.in | FORMS AVAILABLE | Helpline : 8335 958 941 [11 am to 3 pm]
bindumedia.co.in

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक सुधांशु शेखर द्वारा दी इंडियन एक्सप्रेस लिमिटेड, एक्सप्रेस हाउस, एन एच 6 मौजा-प्रशस्थ व अंकुरहाटी,पोस्ट- सलप, थाना-डोमजूर, जिला-हावड़ा-711409 से मुद्रित एवं 19, सर हरिराम गोयनका स्ट्रीट, कोलकाता-700 007 से प्रकाशित. प्रधान संपादक : **सुधांशु शेखर,**
प्रबंध कार्यालय : 19, सर हरिराम गोयनका स्ट्रीट, कोलकाता-700 007, RNI No. WBHIN/2007/22434 फोन : 9831494084, टेलीफैक्स : 22743382 ई-मेल : yuvashakti@hotmail.com प्रकाशन संबंधी समस्त विवादों का निपटारा कोलकाता न्यायालय के अधीन